चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

02 फरवरी–08 फरवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

दिल्ली विधानसभा चुनाव

मुद्दे की नहीं व्यक्तित्व की लड़ाई है

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

दिल्ली विधानसभा चुनाव में तेजी से बदलाव दिखाई दे रहा है. सभी पार्टियां आक्रामक नज़र आ रही हैं. प्रचार-प्रसार में कोई किसी से पीछे नहीं है. सभी पार्टियां पानी की तरह पैसा बहा रही हैं. लेकिन, अफ़सोस इस बात का है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव मुद्दा विहीन हो गया है. भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं. ये तीनों पार्टियां मुद्दों को छोड़कर चेहरे के भरोसे चुनाव लड़ रही हैं. इनके बीच एक–दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतियोगिता चल रही है. एक–दूसरे पर आरोप लगाकर बहस जीतने की होड़ लगी है. जनता का दिल जीतने का प्रयास कोई भी नहीं कर रहा है. तीनों पार्टियों ने चुनाव को मुद्दों से भटका कर व्यक्तित्व की लड़ाई बना दिया है. इस बीच आम आदमी पार्टी की उलझनें बढ़ गई हैं. पार्टी को विरोधियों से ज़्यादा अपने ही नेताओं के बयानों से नुक़सान हो रहा है.

मनीष कुमार

दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां पिछले छह महीने से चल रही थीं. इसमें कोई शक नहीं है कि इस चुनाव का एजेंडा आम आदमी पार्टी ने तय किया. सबसे पहले उसने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा. सबसे ज़्यादा प्रचार–प्रसार भी आम आदमी पार्टी ने ही किया. चुनाव प्रचार के जितने भी तरीके हैं, जैसे कि पोस्टर, पैम्फलेट, होर्डिंग, रैलियां, सभाएं और रेडियो में आम आदमी पार्टी छाई हुई थी. केजरीवाल दिल्ली के लोगों की पहली पसंद बन चुके थे. कहने का मतलब यह कि आम आदमी पार्टी चुनाव की घोषणा के वक्त सबसे आगे चल रही थी. चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे थी. लेकिन, दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल तब आया, जब भारतीय जनता पार्टी ने देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी और जन–लोकपाल आंदोलन में अन्ना हजारे की सहयोगी रहीं किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया.

अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस चुनौती का आकलन सही ढंग से नहीं कर पाए. केजरीवाल और उनके साथी रैलियां कर रहे थे, ज़मीनी स्तर पर मेहनत करने में जुटे थे. वहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने स्थिति का जायजा लिया और इस नतीजे पर पहुंचे कि समय की कमी की वजह से ज़मीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी से निपटना मुश्किल है. भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन की लड़ाई छोड़कर आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू कर दिया. आम आदमी पार्टी के नाराज़ नेताओं से संपर्क साधा गया. और, उन्हें एक–एक करके भाजपा में शामिल कराने का सिलसिला शुरू हो गया. पहले छोटे–छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी ने सदस्यता देनी शुरू की. यह सिलसिला तीन–चार दिनों तक चला. फिर आम आदमी पार्टी के तीन मुस्लिम उम्मीदवारों को तोड़कर पार्टी में शामिल किया गया. फिर किरण बेदी को बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया. उसके एक दिन बाद आम आदमी पार्टी का चेहरा रहीं शाज़िया इल्मी को पार्टी से जोड़ा गया. अगले दिन कांग्रेस पार्टी की पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं दलित नेता कृष्णा तीरथ को भी पार्टी ने सदस्यता दी. इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक रहे विनोद कुमार बिन्नी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया. इस प्रकरण को लगातार मीडिया कवरेज मिल रही थी. हर दिन इन ख़बरों को सुर्खियां मिली. टीवी पर बहस का मुद्दा बनाया गया. भारतीय जनता पार्टी का मकसद सफल होता गया. इस प्रकरण के ज़रिये वह विरोधियों का मनोबल तोड़ने में सफल हुई. हैरानी की बात यह है कि इस सफलता में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक अपरिपक्वता ने भी काफी योगदान दिया. हक़ीक़त यह है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के सारे नेता काफी समय से नाराज़ थे. पार्टी की गतिविधियों में वे सक्रिय नहीं थे. इससे पार्टी को खास नुक़सान भी नहीं होने वाला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मनोवैज्ञानिक युद्ध की इस रणनीति को आम आदमी पार्टी की राजनीतिक अपरिपक्वता ने सफल बनाया और वह भाजपा के जाल में फंस गई. वे जितना बोलते गए, पार्टी का समर्थन और कार्यकर्ताओं का मनोबल उतना ही टूटता गया.

आम आदमी पार्टी ने भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया. कल तक जो उनकी पार्टी में थे, उन्हें अवसरवादी और दलाल कहना शुरू कर दिया गया. आम आदमी पार्टी के नेताओं की सबसे बड़ी ग़लती यह है कि उन्होंने टीवी डिबेट को जीतने के चक्कर में अपने ही कार्यकर्ताओं का विश्वास खो दिया. नतीजा यह हुआ कि आम आदमी पार्टी का वैचारिक और सांगठनिक विरोधाभास खुलकर सामने आ गया. केजरीवाल पर फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की ऐसी धुन सवार है कि वह भूल गए कि दिल्ली चुनाव पार्टी के लिए अस्तित्व का सवाल है, इसलिए पार्टी को एकजुट रखना ज़रूरी है. हालात ऐसे बन गए कि केजरीवाल अपनी पार्टी के ही संस्थापकों को संतुष्ट रखने में विफल साबित हुए. और, मुसीबत यह है कि चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी विचारधारा और संगठन के तौर पर बिखरती नज़र आ रही है. कल तक जो पार्टी के चेहरे हुआ करते थे, आज वही लोग या तो पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर अपने घर में बैठ गए हैं. कार्यकर्ता नाराज़ हैं. दिल्ली के ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के ख़िलाफ़ नारेबाजी हो रही है. कार्यकर्ता केजरीवाल के ख़िलाफ़ नारेबाजी और बयानबाजी कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि नेता रैलियां एवं सभाएं कर रहे होते हैं और मंच के नीचे जनता के बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे युवा पार्टी और केजरीवाल के ख़िलाफ़ पर्चे बांटते नज़र आते हैं. पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं. हैरानी की बात यह है कि इनमें चार मुस्लिम नेता भी थे, जो 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे. आम आदमी पार्टी इन झटकों से संभल भी नहीं पाई थी कि उसके संरक्षक एवं अति महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने ऐसा बयान दे दिया कि पार्टी चारों खाने चित्त हो गई.

आम आदमी पार्टी के संरक्षक शांति भूषण ने भाजपा की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी की तारीफ़ कर दी. यह ख़बर एक अख़बार में छपी. ख़बर में केवल इतना लिखा था कि शांति भूषण ने कहा कि किरण बेदी केजरीवाल जैसी ही ईमानदार मुख्यमंत्री होंगी. लेकिन, आम आदमी पार्टी के अपरिपक्व प्रवक्ताओं ने राई का पहाड़ बना दिया. अगर केजरीवाल की तरह आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं ने इसे नज़रअंदाज कर दिया होता, तो शायद बात आगे नहीं बढ़ती. लेकिन, पार्टी प्रवक्ताओं ने शांति भूषण पर दनादन सवाल दागना शुरू कर दिया. वे यह भूल गए कि वे जिस पार्टी में हैं और जिस आंदोलन की उपज हैं, वे उसी पार्टी और आंदोलन के संस्थापक पर ही सवाल उठा रहे हैं. आम आदमी पार्टी के कच्चे प्रवक्ताओं के जवाब में शांति भूषण ने एक परिपक्व राजनीतिक प्रतिक्रिया दी. टीवी चैनलों पर वह खुलकर सामने आ गए. उन्होंने कहा कि किरण बेदी को सीएम कैंडिडेट बनाना भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है. इतना ही नहीं, उन्होंने केजरीवाल को योग्यता के लिहाज से तीसरे नंबर पर रख दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अजय माकन भी केजरीवाल से बेहतर मुख्यमंत्री होंगे. ग़ौरतलब है कि जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी, तब इन्हीं शांति भूषण ने एक करोड़ रुपये देकर पार्टी का कामकाज शुरू करने के लिए आशीर्वाद दिया था. शांति भूषण का केजरीवाल पर यह हमला महज इत्तेफाक नहीं

(शेष पृष्ठ 2 पर)

दलबदलुओं को सबक सिखाने का वक्त

भारतीय राजनीति में दल–बदल का सिलसिला कोई नया नहीं है. आयाराम–गयाराम का मुहावरा भारतीय राजनीति की ही देन है. भारतीय राजनीति का यह पुराना रोग मौजूदा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है. लेकिन इस बार चुनौती दिल्ली के मतदाताओं के सामने है कि वे इससे कैसे निपटते हैं. दिल्ली में अधिकांश मतदाता पढ़े–लिखे हैं लेकिन उन्हें मौके की नजाकत को समझते हुए उन सभी मौकापरस्त नेताओं को सबक सिखाना होगा जो चुनाव आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं. दिल्ली के मतदाताओं को पूरे देश के लिए एक संदेश देना होगा कि बहुत हुआ, अब बस... ऐसे दलबदलुओं को नकार कर यह बताना होगा कि जनता हर उस मौकापरस्त नेता को सबक सिखाएगी जो चुनावी मौसम आते ही अपना राजनीतिक चोला बदल लेते हैं. मौजूदा चुनाव में भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और अन्य दलों से कई नेताओं ने दलों की अदला–बदली की है. यहां सवाल यह है कि भारतीय राजनीति को साफ करने के लिए चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होने के बाद राष्ट्रीय और प्रादेशिक दलों के नेताओं के दल–बदल पर कानूनी रूप से रोक लगाने का प्रावधान क्यों नहीं करता?

किरण बेदी से भाजपा को फायदा होगा पेज-03

बिहार को नफरत की आग में झोंकने की साजिश पेज-04

जपा के चक्कर में टूट न जाए सपा..! पेज-05

साई की महिमा पेज-12

मुद्दे की नहीं, व्यक्तित्व की लड़ाई है

पृष्ठ एक का शेष

है, बल्कि पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी का नतीजा है. लोकसभा चुनाव से पहले से ही पार्टी के अंदर दो गुट हैं. एक गुट चाहता है कि पार्टी उन मूल्यों को प्राथमिकता दे, जिनके आधार पर पार्टी की शुरुआत हुई. यह पार्टी आंतरिक प्रजातंत्र, शक्ति के विकेंद्रीकरण और व्यवस्था परिवर्तन जैसे मूल्यों को लेकर बनाई गई, जिससे आम आदमी की राजनीति और सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो. इस गुट को अरविंद केजरीवाल के बर्ताव से परेशानी होती है. इसके सदस्यों का कहना है कि पार्टी बनाते वक्त यह धारणा थी कि इसमें कोई अध्यक्ष नहीं होगा, कोई पार्टी का सुप्रीमो नहीं होगा. यह एक राष्ट्रीय चरित्र वाली कमेटी होगी, जो मुद्दों पर अपनी राय रखेगी और पार्टी का संयोजक होगा, जो कमेटी के सदस्यों की राय के बीच समन्वय करेगा. इस गुट का आरोप है कि केजरीवाल सत्ता के भूखे हो गए हैं और पार्टी में वह संयोजक नहीं, बल्कि किसी सुप्रीमो की तरह बर्ताव करते हैं. वह किसी से संपर्क नहीं रखते, किसी की राय नहीं सुनते. वह स्वयं फ़ैसला करते हैं और उसे पार्टी पर थोप देते हैं. इस गुट का यह भी आरोप है कि पार्टी को एक पर्सनालिटी कल्ट में बदल दिया गया है. इस गुट का मानना है कि पार्टी को एक व्यक्ति–एक पद की नीति पर चलना चाहिए. इसकी शिकायत यह भी है कि हर जगह सिर्फ़ केजरीवाल नज़र आते हैं और पार्टी के सभी मूल्यों को ताख पर रख दिया गया है. शांति भूषण ने यह कहकर इस गुट की भावनाओं को आवाज़ दी है कि केजरीवाल सत्ता के भूखे हो गए हैं और केजरीवाल पार्टी के अंदर एक डिक्टेटर (तानाशाह) की तरह काम करते हैं. साथ ही शांति भूषण ने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं से शिकायत मिल रही है कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पैसे लेकर टिकट बेचे हैं. सबसे बड़ी बात शांति भूषण ने यह कही कि अरविंद केजरीवाल पार्टी संयोजक के पद से इस्तीफ़ा दें, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए और नया संयोजक नियुक्त किया जाए. बताया जाता है कि केजरीवाल विरोधी गुट चाहता है कि योगेंद्र यादव को पार्टी का नया संयोजक नियुक्त किया जाना चाहिए.

यहां यह भी समझना ज़रूरी है कि अगर पार्टी में शांति भूषण जैसे लोग संरक्षक होंगे, तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है. चुनाव में 15 दिन भी नहीं बचे थे, जब शांति भूषण ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया. शांति भूषण का हमला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निराश करने वाला ज़रूर है, लेकिन इसके लिए ज़िम्मेदार भी आम आदमी पार्टी के कच्चे नेता ही हैं. राजनीति का खेल मानसिक रूप से अपरिपक्व लोगों के लिए नहीं है. यह एक गंभीर काम है और इससे करोड़ों लोगों का भविष्य तय होता है. आम आदमी पार्टी का उतावलापन और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं ही उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं. आम आदमी पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में 33 फ़ीसद वोट मिले थे. पार्टी नेताओं की रणनीति सिर्फ़ यह होनी चाहिए थी

कि संगठन को एकजुट रखकर और नाराज़ नेताओं को संतुष्ट करके इसमें दो–तीन फ़ीसद वोटों का इज़ाफ़ा किया जाए. योगेंद्र यादव जैसे चुनावी विश्लेषक पार्टी में होते हुए भी यह बात केजरीवाल को क्यों समझ में नहीं आई कि दिल्ली में जिस किसी पार्टी को 35 फ़ीसद से ज़्यादा वोट मिलेंगे, वह पार्टी आराम से बहुमत हासिल कर लेगी. जिस तरह की ग़लतियां आम आदमी पार्टी ने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान कीं, वही ग़लतियां इस दिल्ली चुनाव में भी दोहराई जा रही हैं. परिपक्व नेताओं की यह निशानी होती है कि वे इस बात को समझते हैं कि कब, कहां और कैसे किसी मुद्दे को हाइप देना है और किन मुद्दों पर चुप्पी साधनी है. केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता अब तक चुप्पी साधने की कला नहीं सीख पाए हैं.

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं में राजनीतिक अपरिपक्वता तो है ही, साथ ही अति उत्साह में वे सच और झूठ का फ़र्क़ भी मिटा देते हैं. ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी उस थ्योरी पर काम करती है कि जनता की याददाश्त कमज़ोर होती है, इसलिए मीडिया में कुछ भी सच–झूठ बोल दो, जनता को पता नहीं चलेगा. यही वजह है कि शांति भूषण के हमले के बाद पार्टी प्रवक्ता इतने परेशान हो गए कि वे एक के बाद एक झूठ बोलते चले गए. सबसे बड़ा झूठ कवि से नेता बने कुमार विश्वास ने टाइम्स नाउ चैनल पर बोला. उन्होंने दावा किया कि भूतपूर्व सेनाध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने उनके सामने अन्ना हजारे को भारतीय

यह भी समझना ज़रूरी है कि अगर पार्टी में शांति भूषण जैसे लोग संरक्षक होंगे, तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है. चुनाव में 15 दिन भी नहीं बचे थे, जब शांति भूषण ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया. शांति भूषण का हमला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निराश करने वाला ज़रूर है, लेकिन इसके लिए ज़िम्मेदार भी आम आदमी पार्टी के कच्चे नेता ही हैं. राजनीति का खेल मानसिक रूप से अपरिपक्व लोगों के लिए नहीं है. यह एक गंभीर काम है और इससे करोड़ों लोगों का भविष्य तय होता है.

जनता पार्टी के ख़िलाफ़ बयान देने या मोर्चा खोलने से मना किया था. सच्चाई यह है कि अन्ना हजारे, जनरल वीके सिंह और कुमार विश्वास की एक साथ कभी मुलाकात हुई ही नहीं. दरअसल, झूठ बोलने की सारी सीमाएं लांघते हुए विश्वास यह भूल गए कि जब रामलीला मैदान में अन्ना का आंदोलन चल रहा था, तब जनरल वीके सिंह इस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उस वक्त वह देश के थलसेना अध्यक्ष थे. कुमार विश्वास ने जो बयान दिए, वे न सिर्फ़ झूठे हैं, बल्कि उनकी पार्टी के लिए नुक़सानदायक भी हैं. मजेदार बात यह है कि कुमार विश्वास की मुलाकात जनरल वीके सिंह से सिर्फ़ एक बार हुई, वह भी आधे घंटे की और कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में. यह उस वक्त की बात है, जब अरविंद केजरीवाल नंदनगरी में बिजली बिल को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे. भूख हड़ताल को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा था. उस दौरान अन्ना हजारे और जनरल वीके सिंह हरियाणा में जनतंत्र यात्रा कर रहे थे. केजरीवाल अपनी भूख हड़ताल की साख बचाने के लिए चाहते थे कि अन्ना दिल्ली आकर उनकी भूख हड़ताल को उन्हें पानी पिलाकर ख़त्म करें. उसी दौरान कुमार विश्वास और मनीष सिसौदिया की जनरल वीके सिंह से पहली और आख़िरी बार मुलाकात हुई थी. आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह समझना चाहिए कि टीवी चैनलों पर आकर सफेद झूठ बोलना भविष्य के लिए उचित नहीं है. इस तरह की बयानबाजी दो ही वजहों से होती है. एक तो जब नेता जनता को बेवकूफ समझने की ग़लती करते हैं या फिर वे आदतन ऐसा काम करते हैं.

आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार और भाषा उसके आदर्शों के मुताबिक नहीं है. पार्टी के प्रवक्ता और नेता सरेआम अपने ही नाराज़ कार्यकर्ताओं को बुरा–भला कहने का एक भी मौक़ा नहीं छोड़ते. इसका गहरा असर पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं पर पड़ता है. कई कार्यकर्ता पार्टी की कार्यशैली से परेशान हैं. यही वजह है कि 2013 की तरह इस बार पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे हैं. ज़्यादातर कार्यकर्ताओं की शिकायत यह है कि पार्टी में उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया है, जिन्होंने अपना खून–पसीना बहाकर जन–लोकपाल आंदोलन को सफल बनाया था और फिर उसके बाद पार्टी को दिल्ली में खड़ा किया था. उनकी शिकायत यह भी है कि पार्टी के शीर्ष पर बाहर के लोग एक गैंग बनाकर स्थापित हो गए हैं. वे कार्यकर्ताओं से बात तक नहीं करते. वही लोग पार्टी के नाम पर हर जगह अपना चेहरा चमकाते हैं. वही लोग टीवी पर भी नज़र आते हैं. बाहर से आए लोगों को पार्टी में जबरदस्त तरजीह दी जाती है, जिससे कार्यकर्ता नाराज़ हैं. सबसे ज़्यादा निराश वे कार्यकर्ता हैं, जो अपनी नौकरी, अपना भविष्य और अपना करियर दांव पर लगाकर इस आंदोलन से जुड़े थे. आम आदमी पार्टी के सामने व्यापक चुनौती है. पार्टी एक चक्रव्यूह में फंसी है. अगर वह दिल्ली चुनाव जीत गई, तो इस चक्रव्यूह से बाहर आने के रास्ते खुल जाएंगे और अगर वह दिल्ली चुनाव हार जाती है, तो इस चक्रव्यूह में और भी ज़्यादा फंस जाएगी. और, तब पार्टी का हश्र वही होगा, जो चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु का हुआ था. ■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 48
दिल्ली, 02 फरवरी–08 फरवरी 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060
+91–8451050786
+91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

नाटकीय विदाई

जिन वरिष्ठ बाबुओं को बाहर का रास्ता दिखाना होता है, उन्हें मोदी सरकार नाटकीय तरीके से बाहर निकालती है. दो महीने पहले एसपीजी चीफ दुर्गा प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नेपाल की यात्रा पर थे और अचानक उन्हें बर्खास्त कर दिया गया. बीते दिनों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के प्रमुख अविनाश चंदर को इसी तरह बाहर निकाले जाने का आदेश दिया गया. दोनों बाबुओं को कथित तौर पर मीडिया के माध्यम से खुद को हटाए जाने की ख़बर मिली. डीआरडीओ प्रमुख के मामले में अफ़वाहें तभी शुरू हो गई थीं, जब एनडीए सरकार सत्ता में आई थी. इस तथ्य के अलावा कि वह पिछली यूपीए सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, हाल में जिस तरह से मोदी ने डीआरडीओ की आलोचना की थी, उससे चंदर के दिन बस गिने ही जा रहे थे. लेकिन, हैरानी उन्हें बाहर किए जाने के तरीके को लेकर हुई. वह सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने उन्हें अनुबंध पर 18 महीने के लिए फिर से हायर (नियुक्त) किया था. बहरहाल, अब दिल्ली नए डीआरडीओ प्रमुख का इंतज़ार कर रही है. और, यह भी देखना बाकी है कि डीआरडीओ की ओर से अटकाए गए कौन से रक्षा सौदे जल्दी राहत पाते हैं. ■

अनिश्चित भविष्य

पुराने नेहरूवादी योजना आयोग के बाद अब नीति आयोग से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, लेकिन नई संरचना में भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारियों का एक ऐसा वर्ग भी है, जो नए मोदी युग में अपने भविष्य को लेकर परेशान है. जनता के बीच आईईएस जाहिर तौर पर आईएएस जितना जाना–पहचाना शब्द नहीं है. इसमें अनुभवी अर्थशास्त्री और वित्त विशेषज्ञ शामिल हैं. तत्कालीन योजना आयोग में सौ आईईएस अधिकारी थे. नीति आयोग के शीर्ष पदानुक्रम की बड़ी धूमधाम के साथ घोषणा की गई. वहीं आईईएस बाबुओं को नए संगठन में अपनी भूमिका के बारे में जानकारी नहीं है. कुछ को अन्य मंत्रालयों या विभागों में भेजे जाने का डर है. कुछ निराशावादी लोगों को सेवा में धीमी गति से गिरावट होने की भी उम्मीद है. आख़िरकार, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया नेहरूवादी अर्थशास्त्र के कभी प्रशंसक नहीं रहे हैं. क्या इन बाबुओं की भविष्यवाणी सच साबित होगी? ■

थॉमसन चले घर

खेल सचिव का पद मिलने का वादा पूरा न होने के बाद भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक जीजी थॉमसन ने कथित तौर पर, हाल में यह पद छोड़ दिया है और उन्होंने अपने मूल कैडर केरल वापस भेजे जाने की मांग की है, जहां उन्हें मुख्य सचिव का पद दिए जाने की बात कही जा रही है. सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट सचिव अजीत सेठ ने इसे मंजूरी दे दी है, लेकिन पद छोड़ने के थॉमसन के फ़ैसले ने खेल संस्थाओं की आंतरिक कलह को सतह पर ला दिया है. यह माना जा रहा है कि थॉमसन की ओर से पैरवी करने वालों में खेल मंत्री सर्बानंदा सोनवाल भी शामिल थे, लेकिन उनके प्रयास नौकरशाही की बाधाओं को पार नहीं कर सके. दिलचस्प रूप से 1980 बैच के आईएएस अधिकारी थॉमसन राज्य के मुख्य सचिव के रूप में इस महीने के अंत में केरल में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलों की देखरेख करेंगे. इस बीच सरकार ने थॉमसन की पदोन्नति के निर्णय में भले ही देरी की हो, लेकिन उनका उत्तराधिकारी तलाशने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया. ख़बर है कि नेशनल एंटी डोम्पिंग एजेंसी के महानिदेशक जीएसजी अय्यंगर थॉमसन की जगह ले सकते हैं. ■

dilipcherian@gmail.com

किसी भी राजनीतिक दल की जीत में सबसे महत्वपूर्ण किरदार दल के उन कार्यकर्ताओं का होता है जो जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाते हैं. ऐसा माना जाता है कि पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं तो निश्चित रूप से नेताओं को बेहतर नतीजे हासिल होंगे. भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को भाजपा का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे शायद यही रणनीति काम कर रही है. दरअसल आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के सामने भाजपा कोई ऐसा चेहरा रखना चाहती थी जिस पर किसी तरह के आरोप न हों साथ ही वह जनता के बीच अरविंद केजरीवाल की तरह लोकप्रिय भी हो.

दिल्ली चुनाव

किरण बेदी से भाजपा को फायदा होगा

अरुण तिवारी

किरण बेदी को सीएम का पद का उम्मीदवार घोषित करके भाजपा ने आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की हवा निकालने की कोशिश की है. पार्टी नेतृत्व ने यह निर्णय निश्चित रूप से सिर्फ इसलिए नहीं लिया है कि किरण बेदी सबसे काबिल नेता साबित होंगी क्योंकि भाजपा के पास कद्दावर नेताओं की कमी नहीं है. इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि दिल्ली में भाजपा के निशाने पर सीधे अरविंद केजरीवाल हैं. अगर पार्टी को उनका जवाब सही तरीके से देना था तो उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत थी जिस पर जनता उसी तरह से विश्वास करे जैसा वह केजरीवाल पर करती है. किरण बेदी इसके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थीं क्योंकि वे अन्ना आंदोलन के शुरुआती समय से ही जुडी रहीं थीं. लोग उनमें भी ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और कुशल प्रशासन देखते हैं. ऐसे में पार्टी के भीतर विरोधों के बावजूद उन्हें सीएम उम्मीदवार बनाया गया और अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर चुनौती दी गई. इस कदम की वजह से भले ही भाजपा के भीतर द्वंद्व चल रहा हो, लेकिन भाजपा के इस कदम की वजह से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आने के लिए मजबूर हो गई. शुरूआत में आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर किरण बेदी पर हमले करने से बच रही थी, लेकिन समय के साथ किरण बेदी पर हमले करने शुरू कर दिए. इसकी वजह यह है कि आप ने चुनावी प्रचार में प्रारंभिक बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन किरण बेदी के नामांकन दाखिल करने के एक दिन बाद उन पर हमले तेज कर दिए. आम आदमी पार्टी ने उन्हें इंडिया अगेन्स्ट करप्शन में भाजपा का जासूस तक कह दिया.

किसी भी राजनीतिक दल की जीत में सबसे महत्वपूर्ण किरदार दल के उन कार्यकर्ताओं का होता है जो जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाते हैं. ऐसा माना जाता है कि पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं तो निश्चित रूप से नेताओं को बेहतर नतीजे हासिल होंगे. भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को भाजपा का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे शायद यही रणनीति काम कर रही है. दरअसल आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के सामने भाजपा कोई ऐसा चेहरा रखना चाहती थी जिस पर किसी तरह के आरोप न हों साथ ही वह जनता के बीच अरविंद केजरीवाल की तरह लोकप्रिय भी हो. लोकसभा चुनावों के बाद कई प्रदेशों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए. भाजपा ने किसी भी राज्य में चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था. चुनावी बिगुल बजते ही आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल

ने इस बात को मुख्य मुद्दा बना दिया कि चुनावी लड़ाई के लिए भाजपा के पास सीएम पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है. धीरे–धीरे यह बात लोगों को सच भी लगने लगी थी. इस दौरान कई चुनावी सर्वे के परिणामों में यह बात भी साबित होने लगी थी कि अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच सीएम पद के सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी साबित हो रहे हैं. इसी वजह से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व एक ऐसे चेहरे की तलाश में था, जिसे लेकर पार्टी में कोई विवाद भी न हो और वह अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की भाषा में जवाब भी दे सके.

किरण बेदी के भाजपा में शामिल होने के कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली मौजूद थे. शायद ऐसा इसलिए भी किया गया था कि इससे दिल्ली भाजपा के सभी नेताओं को यह संदेश मिल जायेगा कि किरण बेदी ही पार्टी की सीएम उम्मीदवार होंगी. हालांकि उस दिन अमित शाह ने इस बात की औपचारिक घोषणा तो नहीं की, लेकिन दो दिन बाद पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई कि विधानसभा चुनाव में किरण ही पार्टी का चेहरा होंगी. कुछ विशेषज्ञ इसे भाजपा के मास्टर स्टोक के रूप में देख रहे हैं तो कई इसे एक गलत कदम भी मान रहे हैं. मास्टर स्टोक मानने वालों का कहना है किरण बेदी काफी पहले से देश में एक लोकप्रिय चेहरा हैं. लोग उन्हें तब से जानते हैं जब अरविंद केजरीवाल का कोई नाम भी नहीं जानता था. इसके अलावा एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुकी हैं. जिस अन्ना आंदोलन को केजरीवाल ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं, उसमें किरण बेदी सक्रिय रूप से जुड़ी रहीं थीं. किरण बेदी को महिला वोटरों के बीच खास लोकप्रियता हासिल है. ये खूबियां उन्हें अरविंद केजरीवाल से इक्कीस साबित करती हैं. वहीं इस कदम को गलत मानने वालों का कहना है कि एक बाहरी व्यक्ति को सीएम उम्मीदवार घोषित करना भाजपा की परिपाटी नहीं रही है. ऐसे में इस तरह का कदम उठाए जाने से जनता के बीच यह गलत संदेश जा सकता है कि भाजपा के भीतर क्या कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो दिल्ली का सीएम बन सके. इसके अलावा किरण बेदी वे किरण बेदी के पास राजनीतिक अनुभव की कमी देखते हैं. उनके प्रतिद्वंद्वी अरविंद केजरीवाल को राजनीति में आए ज्यादा दिन तो नहीं हुए हैं लेकिन उन्होंने कम समय में ही राजनीति के कई रंग देख लिए हैं. ये सारी बातें अरिवंद केजरीवाल के पक्ष में बैठती हैं, इस वजह से वे किरण बेदी से बेहतर उम्मीदवार साबित होंगे.

हालांकि ऐसा नहीं है कि पार्टी आलाकमान के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद किरण बेदी का पार्टी में विरोध न हुआ हो. उनके सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने के तुरंत बाद दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी का बयान आया था कि किरण को चेहरा बनाने से पहले पार्टी आलाकमान ने उनसे कोई राय नहीं ली. इसे लेकर वह काफी दुखी दिखाई दिए. इसके बाद उन्होंने कहा था कि पार्टी का जो भी आदेश हो उसका पालन तो किया जाएगा लेकिन ऐसा करने से पहले राय ली जानी चाहिए थी. यहां याद रखने वाली बात यह है कि पहले यही माना जा रहा था कि जगदीश मुखी ही पार्टी के सीएम पद के प्रत्याशी हो सकते हैं. हालांकि इस बात की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की थी. लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऑटो रिक्शा पर केजरीवाल और जगदीश मुखी के पोस्टर लगवाए थे और जनता से सवाल किया था कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? विरोध की सबसे मजबूत आवाज दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के समर्थकों की ओर से उठी. उनके समर्थकों ने पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था. इसके बाद सतीश उपाध्याय ने इस घटना पर स्पष्टीकरण दिया और अपने समर्थकों को शांत करने की कोशिश की. भोजपुरी के मशहूर गायक और दिल्ली में भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने किरण बेदी द्वारा चाय पार्टी पर बुलाए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि वे हमारी नेता नहीं हैं. कुछ ही घंटों बाद उनका भी स्पष्टीकरण आ गया कि उनके बयान को तोड़–मरोड़कर पेश किया गया, उन्हें किरण बेदी से कोई दिक्कत नहीं है.

किरण बेदी के खिलाफ पार्टी में आवाज तो उठ रही है लेकिन इसे शीर्ष नेतृत्व का दबाव ही कहा जा सकता है कि नेताओं को नाराजगी जाहिर करने के बाद स्पष्टीकरण देने पड़ रहे हैं. दरअसल, नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं जिन्हें लेकर उनमें आपसी मतभेद सामने आते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से किरण बेदी को उम्मीदवार घोषित किया गया है, ऐसी परिस्थिति में किसी भी पार्टी में दिक्कतें आ सकती हैं. लेकिन यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी पर मजबूत पकड़ ही है वे विरोधों को दबाने में शपल हो रहे हैं. लेकिन विरोधी स्वरों को दबाने का खामियाजा पार्टी को चुनाव में हो सकता है. हालांकि किरण बेदी के सीएम कैंडिडेट घोषित होने के बाद से पार्टी के कार्यकर्ता काफी खुश हैं क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल के जवाब में एक ऐसा नेता मिल गया है जो उन्हें मजबूत टक्कर और करारा जवाब दे सकेगा. दोनों में से कौन सवा सेर साबित होगा, इसके लिए हमें चुनावी नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

दिल्ली चुनाव

चल पड़ी है बगावत की बयार

नवीन चौहान

दिल्ली विधानसभा चुनाव का शंखनाद होते ही दिल्ली का पारा चरम पर पहुंच गया है. हर दल अपनी चालों से विपक्षी दलों को मात देने में किसी तरह की कोर–कसर नहीं छोड़ रहा है. भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को अपने साथ जोड़कर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि विपक्षी दलों, खासकर आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने दांतों तले उंगली दबा ली. उनके पास भाजपा की इस चाल का कोई जवाब नहीं था. किरण बेदी के राजनीति में क़दम रखते ही विरोधी दलों में बगावत की बयार चल पड़ी. सबसे पहले आम आदमी पार्टी की शाजिया इल्मी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की इसके बाद आप के पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी भी भाजपा में शामिल हो गए. इससे पहले आप के संस्थापक सदस्य अश्विनी कुमार और आप सरकार के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रहे एमएस धीर भी भाजपा में शामिल हो गए थे. दलबदल की हद तो तब हो गई, जब कांग्रेस का दलित चेहरा एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की. उसके बाद शाम होते–होते वह भाजपा की औपचारिक रूप से सदस्य बन गईं. यह एक बार फिर से उठ खड़ी होने की कोशिश कर रही कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था. दूसरी पार्टी में पलायन करने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद आम आदमी पार्टी के सदस्यों की है. पलायन तक़रीबन हर पार्टी से हो रहा है, लेकिन अचानक से सबकी पसंदीदा पार्टी भाजपा बन गई है. भाजपा से केवल वे लोग दूसरे दलों की ओर रुख कर रहे हैं, जो टिकट पाने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन टिकट कटते ही उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर लिया.

दल–बदल के सबके अपने–अपने कारण हैं. भाजपा में शामिल हुए आप के बागी पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी 2013 में लक्ष्मीनगर सीट से चुनाव लड़े थे. उन्हें केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी थी. इस वजह से उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया. पार्टी ने उनके ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था. इसके बाद बिन्नी ने अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया था. बिन्नी यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि भाजपा के सहयोग के बिना वह अपने मकसद में सफल नहीं हो सकते. इसी वजह से वह नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहे थे और भाजपा में प्रवेश करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे. किरण बेदी द्वारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते ही बिन्नी को मौक़ा मिल गया और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया. भाजपा ने उन्हें मनीष सिसौदिया के ख़िलाफ़ पटपड़गंज सीट से चुनाव मैदान में उतारा है. भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद बिन्नी ने कहा, मैं भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ होने के कारण अन्ना आंदोलन का हिस्सा था. मैं नहीं जानता था कि कुछ अवसरवादी लोग मुझे और दिल्ली के लोगों को ठगेंगे. उन्होंने लोगों से झूठे वादे किए और अपने

दल-बदल के सबके अपने-अपने कारण हैं. भाजपा में शामिल हुए आप के बागी पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी 2013 में लक्ष्मीनगर सीट से चुनाव लड़े थे. उन्हें केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी थी. इस वजह से उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया. पार्टी ने उनके ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था.

लाभ के लिए अन्ना जैसे महान व्यक्ति का इस्तेमाल किया.

आम आदमी पार्टी के टिकट पर आरके पुरम सीट से विधानसभा और गाज़ियाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली शाज़िया इल्मी ने लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया. वह लोकसभा चुनाव गाज़ियाबाद से नहीं लड़ना चाहती थीं, लेकिन पार्टी ने उन्हें जबरदस्ती जनरल वीके सिंह के ख़िलाफ़ चुनाव मैदान में उतारा. लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद शाज़िया ने आप से इस्तीफ़ा दे दिया. इसके बाद वह किसी पार्टी में नहीं गईं. हालांकि, अटकलें लगाई जा रही थीं कि वह भाजपा में जा सकती हैं, लेकिन उन्होंने जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला नहीं लिया. वह लगातार आप की नीतियों और क़दमों की आलोचना करती रहीं. किरण बेदी के शामिल होने के बाद उनके लिए भाजपा में आना आसान हो गया. 2013 में जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले मनिंदर सिंह धीर पार्टी का सिख चेहरा थे. आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान वह विधानसभा अध्यक्ष रहे. आप में आंतरिक लोकतंत्र की कमी की बात कहते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया. आप छोड़ भाजपा में शामिल होने का ईनाम धीर को भी मिला, उन्हें जंगपुरा से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है.

इस विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का झुकाव आम आदमी की तरफ़ बढ़ रहा है, ऐसी बातें राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़े और पिछले विधानसभा चुनाव में उसके टिकट पर चुनाव लड़ने वाले तीन मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी आप का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया. 2013 में मटिया महल से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे शकील अंजुमन देहलवी, कृष्णा नगर से आप उम्मीदवार रहे इशरत अली अंसारी और बल्लीमारान से पार्टी उम्मीदवार रहीं फरहाना अंजुम किरण बेदी के सदस्यता ग्रहण करने के दिन भाजपा में शामिल हो गए. शकील अंजुमन देहलवी को भाजपा ने मटिया महल से उम्मीदवार बनाया है. वह भाजपा द्वारा जारी 62 उम्मीदवारों की सूची में जगह पाने वाले अकेले मुस्लिम हैं.

दलित उम्मीदवारों का भी आप से मोहभंग हो रहा है. पिछले विधानसभा चुनाव में अंबेडकर नगर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए अशोक कुमार चौहान भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. हालांकि, आप ने इस बार उन्हें अंबेडकर नगर से टिकट न देने का मन बना लिया था, इसी वजह से वह भाजपा में शामिल हो गए. भाजपा ने बतौर ईनाम उन्हें अंबेडकर नगर से चुनाव मैदान में उतारा है. उधर, भाजपा से इस्तीफ़ा देने वालों में धीर सिंह बिधूड़ी का नाम सबसे आगे है. वह ओखला से टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया. बसपा से भाजपा में शामिल हुए ब्रह्म सिंह बिधूड़ी को वरीयता दी गई और ओखला से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष एवं पार्षद करतार सिंह तंवर भाजपा छोड़कर आप में शामिल हो गए.

दिल्ली में विभिन्न पार्टियों के छोटे–बड़े नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं. कांग्रेसी नेता एवं पीतमपुरा के पूर्व पार्षद राजेश यादव भी भाजपा में शामिल हो गए. राजेश यादव को भाजपा ने बादली सीट से उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह के बेटे सरदार अरविंदर सिंह, राष्ट्रीय लोकदल की निगम पार्षद अनीता त्यागी, पूर्व कांग्रेस पार्षद दीपक चौधरी, प्रदेश कांग्रेस सचिव शशिकांत दीक्षित, कांग्रेसी नेता गोपाल पहाड़िया, अशोक लोहिया, अरदेश शर्मा, महेंद्र त्यागी, एमपी शर्मा, सरदार हरप्रीत सिंह के साथ–साथ आम आदमी पार्टी के संदीप दुबे, इंजीनियर चंद्रकांत त्यागी और समाजवादी कार्यकर्ता ओंकार सिंह सिकरवार भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं.

आप अथवा अन्ना आंदोलन से जुड़े नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि भाजपा के पास अपना कोई सशक्त चेहरा नहीं है. वह आप के नेताओं को शामिल कर रही है, जिससे साबित होता है कि भाजपा आम आदमी पार्टी की बी टीम बन गई है. लेकिन, यहां एक बात ग़ौर करने लायक है, जो आम आदमी पार्टी स्वयं को पार्टी विथ डिफरेंस (सबसे अलग) बताती थी, उसमें पार्टी गठन के समय वही लोग साथ आए, जो मौक़ापरस्त थे. अब अधिकांशत: वैसे ही लोग आप छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें लगता है कि इस चुनाव के बाद आप का अस्तित्व ख़तरे में पड़ जाएगा. इसी आशंका के आधार पर वे दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं. उनकी कोई विचारधारा नहीं है. वे सिर्फ़ अपना भविष्य तलाश रहे हैं. उन्हें पार्टी और विचारधारा से ज़्यादा अपने भविष्य की चिंता है. पार्टियों में स्थापित सदस्यों पर पैराशूट उम्मीदवारों को वरीयता देना भी बगावत का एक प्रमुख कारण है. आप ने पिछली बार यह दावा किया कि उसने प्रत्याशियों का चयन जनता की पसंद पर किया है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ. इस बार प्रत्याशियों के चयन में धनाढ्यों को वरीयता दी गई. ऐसे में, जो लोग आंदोलन के समय से आप से जुड़े हुए थे, वे या तो चुपचाप बैठे हैं या पार्टी में साइड लाइन कर दिए गए हैं. जो घुटन भरे माहौल में नहीं रह पा रहे, वे दूसरी पार्टियों में अपने लिए जगह तलाश रहे हैं. यूं तो कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन अब इस मुहावरे में राजनीति को भी शामिल कर लेना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

> ओखला दिल्ली का मुस्लिम–बहुल्य क्षेत्र है, वहां भी किरण बेदी का जादू चलता दिख रहा है. एक 35 वर्षीय घरेलू महिला तनवीर शाहिद तीन बच्चों की मां हैं, उनका कहना है कि किरण बेदी को वह एक उम्मीद की किरण की तरह देखती हैं. उनका कहना है कि मेरी 18 वर्षीय बेटी जब स्कूल जाती है तब से उसके घर वापस लौटने तक मैं परेशान रहती हूं. दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस की मैत्रेयी कॉलेज की डॉक्टर हरचरन कौर किरण बेदी के आक्रामक अंदाज़ को पसंद नहीं करती हैं. उनका कहना है कि नौकरशाह अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते, क्योंकि उनके यहां डिप्लोमेसी नहीं होती और यह भी एक सच्चाई है कि अफसरों की अफसरी कभी नहीं जाती.

बिहार को नफरत की आग में झोंकने की साजिश

अशरफ़ अस्थानवी

बिहार के मुजफ्फरपुर के मुस्लिम बाहुल्य अज़ीज़पुर गांव पर उपद्रवियों के हमले ने राज्य के सांप्रदायिक सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण को भंग कर दिया है. गांव के चार मुसलमानों के मारे जाने की ख़बर है कई लोग लापता हैं. गांव में कई जगह आगजनी की गई, इसमें कई घर जलकर राख हो गए हैं. राजनीतिज्ञ सियासी रोटियां सेंकने में व्यस्त हैं. इस हमले से किसे नुक़सान हुआ यह सब जानते हैं, लेकिन फ़ायदा किसे पहुंचा? दंगे की आग 8 जनवरी की सुबह उस समय भड़की, जब मुज़फ्फरपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर सरिया थाने के तहत अज़ीज़पुर गोठी के एक खेत में 11 दिनों से लापता एक गैर मुस्लिम युवक भार्तेन्दु सहनी की लाश मिलने की खबर फैली. ख़बर मिलते ही गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंच कर लाश और आसपास की परिस्थितियों का निरीक्षण कर ही रहे थे कि आसपास के गांवों के तकरीबन 5 हज़ार लोगों ने दिन के 2 बजे गांव पर हमला कर दिया. हमलावर भारी शस्त्रों से लैस थे. इससे पहले कि अज़ीज़पुर के लोग कुछ समझ पाते या अपने बचाव के लिए कुछ करते, हमलावर उन पर क़हर बनकर टूट पड़े. घरों और बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी और लूटमार की गई. देखते ही देखते 45 घरों वाले इस गांव से आग की लपटें उठने लगीं. दंगाईयों ने मस्जिद को भी नहीं छोड़ा, उसे भी आग के हवाले कर दिया. हमलावारों ने पुलिस और फ़ायर ब्रिगेड को घटनास्थल पर पहुंचने नहीं दिया, घंटों उनका रास्ता रोके रखा, और गांव में खुलकर तांडव मचाया.

घटना के समय मौके पर मौजूद और पीड़ित मोहम्मद मुतुर्जा, मोहम्मद कय्यूम, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद सना उल्लाह, मोहम्मद निसार, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद शकूर, हनीफ़, ऐजाज़ मुन्ना, रियाज़ और मोहम्मद अलाउद्दीन के अलावा कई महिलाओं ने बताया कि आगज़नी से पहले हमलावरों ने घरों से नक़दी, ज़ेवर और क़ीमती सामान लूट लिया, इसके बाद घर में आग लगा दी. गांव की महिलाओं ने बताया कि गांव के अधिकतर पुरुष रोज़गार के लिए राज्य से बाहर रहते हैं, इसलिए गांव में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या अधिक है. एक पीड़ित नजमून ख़ातून ने बताया कि लड़की की शादी के लिए डेढ़ लाख रुपये नक़द और सोने–चांदी के ज़ेवर बनाकर रखे थे, दंगाईयों ने सब कुछ लूट लिया. इस दर्दनाक घटना में अपना सबकुछ खोने वाली सलमा ख़ातून ने रोते हुए बताया कि जिस समय उनके घर पर हमला हुआ, वह घर के अन्दर थीं, हमलावर लोहे की ग्रिल तोड़कर घर में घुस गये. हम डर की वजह से एक कमरे में बंद हो गये, हमलावर दरवाज़ा तोड़ने लगे. इस पर मेरे शौहर ने दरवाज़ा खोला और उनसे हाथ जोड़कर कहा कि हम लोग बिल्कुल निर्दोष हैं, हमें मत मारो. लेकिन दंगाईयों ने कोई बात नहीं सुनी. उन्हें घसीटकर पीटते हुए खेत में ले गये, उन्हें बुरी तरह घायल करने के बाद जिंदा जला दिया.

अब्दुल रज्जाक के घर शरणार्थी महिला ने बताया कि सशस्त्र हमलावरों ने अचानक हमला किया और उनके घरों से सभी क़ीमती सामान, नकदी व जेवर लूट लिए. इरफ़ान की बहन ने बताया कि उसके भाई के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जला दिये गए. मोहम्मद शमशेर के घर वालों ने बताया कि उनके तीन भाईयों मोहम्मद निसार, मोहम्मद शम्सुद्दीन का ख़ानदान सामूहिक रूप से रहता है. हमलावरों ने शाहिद को बुरी तरह घायल करके अधमरा कर दिया है. वह मुज़फ्फरपुर के एक निजि अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि इम्तियाज़, तनवीर और जावेद लाल गंज में भर्ती हैं. अपने भाई को बचाने गईं शकीला उर्फ लाड़ली को भी बेरहमी से निशाना बनाया गया. उनके सिर पर गहरी चोटें आई हैं. इस गांव के लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खो चुके हैं. कड़ाके की सर्दी से बचने और सिर छिपाने के लिए भी अधिकांश लोगों के पास कोई जगह नहीं है. कई मुस्लिम संगठन राहत व बचाव कार्यों में लग गये हैं. सरकार और प्रशासन की ओर से भी लोगों को मुआवाज़ा और राहत पहुंचाने की कार्यवाही शुरू हो गई है. मृतकों के परिजनों को 5–5 लाख रुपये और मकानों की मरम्मत के लिए 1–1 लाख रुपये सरकार की ओर से दिये जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के परिजन इस हिंसा में मारे गये हैं या जो लापता हैं, उनके घरों से रोने और सिसकियों की आवाज के

अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता है. गांव वालों को सबसे अधिक मलाल इस बात का है कि उन्हें निर्दोष होने की सज़ा मिली है. जिस नौजवान के अपहरण और हत्या की वजह से इतनी हिंसा हुई, उसकी अज़ीज़पुर गांव के किसी भी बाशिंदे से कोई दुश्मनी नहीं थी. उसका अपने ही संप्रदाय के किसी व्यक्ति से विवाद चल रहा था और क्योंकि उसे 9 जनवरी को आख़िरी बार मोहम्मद इब्राहीम के घर पर देखा गया था, इसलिये उसके पिता कमल सहनी ने एफआईआर में उनके पोते सदाक़त अली उर्फ विक्की का नाम दे दिया था, कारण बहन से प्रेमप्रसंग बता दिया था, जो कि ग़लत है.

इस संबंध में सदाक़त उर्फ विक्की के दादा इब्राहिम का कहना है कि भारतेंदु 9 जनवरी की सुबह उनके घर आया था और उनके पोते सदाक़त से सरिया चलने को कहा था, लेकिन जुमे का दिन था, इसलिए उसने साथ जाने से इंकार कर दिया. बाद में भारतेंदु किसी दूसरे लड़के के साथ मोटर साइकिल से चला गया. इसके 11 दिन बाद उसकी लाश देखने को मिली. जिस जगह लाश को मिट्टी में दबाया गया था, उसके निरीक्षण से पता चलता है कि लाश को किसी और जगह से लाकर वहां जल्दबाज़ी में मिट्टी से ढंकने की कोशिश की गई है. उन्होंने कहा कि पहले तो प्रेम प्रसंग वाली बात बिल्कुल बे–बुनियाद और फ़र्ज़ी है, समझने वाली बात यह है कि कोई आदमी किसी की हत्या करेगा तो उसे अपने घर के पीछे ही दफ़न क्यों करेगा? दरअसल मुजरिम कोई और है. उसने एफआईआर में सदाक़त उर्फ विक्की का नाम आने के बाद इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए भारतेन्दु की हत्या कर सदाक़त के घर के पीछे डाल दिया. ऐसा कैसे संभव था कि गांव वालों को लाश मिलने की ठीक से सूचना भी नहीं थी कि हज़ारों की संख्या में संप्रदाय विशेष के लोग हथियारों के साथ वहां कैसे पहुंच गये. यह हमला इतने संगठित रूप से हुआ है कि इससे इस बात का साफ़ संकेत मिलता है कि इसके पीछे दंगों का अनुभव रखने वाले संघ परिवार का हाथ है, जो चुनावी वर्ष में एक तीर से दो शिकार करके एक पार्टी विशेष को राजनीतिक लाभ पहुंचाना चाहता है. गौरतलब है कि इस क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व ही भाजपा के विवादित सांसद योगी आदित्यनाथ ने धर्म परिवर्तन की सभा की थी और इस क्षेत्र के भाजपा विधायक और पार्टी के अन्य कई नेता लगातार माहौल खराब करने वाले बयान दे रहे हैं, इसलिए इस पूरे मामले की टाइम बाउंड निष्पक्ष जांच होनी चाहिये.

अज़ीज़पुर गांव में जो कुछ हुआ, वह सांप्रदायिक तत्वों की संगठित साजिश का नतीजा था, अन्यथा स्वर्गीय जगलाल सहनी की विधवा शीला देवी ने अपने घर में एक दर्जन मुस्लिम युवकों व महिलाओं को शरण नहीं दी होती. अज़ीज़पुर में इस समय स्थिति बेहद चिंताजनक है. अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में गहरा भय और असुरक्षा की भावना है. राज्य के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय जनता के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस गांव का दौरा कर चुके हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

महिला सुरक्षा

दूसरों से बेहतर साबित होंगी किरण

वसीम राशिद

किरण बेदी को भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है. बेदी के आने के बाद सच मानिए तो लोगों की दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिलचस्पी बढ़ गई है. किरण बेदी का नाम दिल्लीवालों के लिए नया नहीं है. भाजपा के थिंक टैंक को इस बात का अनुमान हो गया था कि दिल्ली का चुनाव दूसरे राज्यों से अलग है और केजरीवाल के चेहरे के सामने अगर भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा था तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था. ज़ाहिर सी बात थी कि मोदी यह चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसका केवल एक ही तोड़ था कि कोई ऐसा चेहरा हो जिसे दिल्ली वाले जानते हों, पहचानते हों, समझते हों और विश्वास करते हों. यही सोच–समझकर भाजपा ने देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया. केजरीवाल से पहले पंद्रह साल तक दिल्ली की कमान शीला दीक्षित के हाथों में थी. ऐसे में क्या दिल्ली में एक बार फिर महिला मुख्यमंत्री देखने को मिलेगी. दिल्ली की महिलायें किरण बेदी के बारे में क्या सोचती हैं, क्या महसूस करती हैं. क्या किरण बेदी दिल्ली की जनता के बारे में खासकर महिलाओं के लिए कुछ कर पाएंगी. इस सिलसिले में दिल्ली की महिलाओं ने मिलीजुली राय रखी.

सबसे दिलचस्प, यह बात सामने आई कि अधिकतर शिक्षित महिलायें किरण बेदी के पक्ष में नज़र आईं. रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली 60 वर्षीय मार्गरेट वाटर्स पेशे से शिक्षिका हैं, वह किरण बेदी पर बहुत भरोसा जताती हैं. उनका कहना है कि पुलिस में रहने के कारण वह महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को अच्छी तरह समझती हैं, वह अंदर तक की बुराईयों से परिचित हैं. उसी तरह पीतमपुरा की रहने वाली 34 वर्षीय टीचर गौरी शर्मा किरण बेदी को एक असाधारण क्षमताओं वाली महिला मानती हैं. उनके अनुसार किरण बेदी की पूरी जिंदगी ही सख्त अनुशासन और एक्शन लेते हुए गुज़रा है. जाफ़राबाद क्रीसेंट स्कूल की प्रिंसिपल नोशाबा का कहना है कि वह शोहरत की भूखी हैं, अवसरवादी हैं. सीलमपुर की रहने वाली 43 वर्षीय गीता शर्मा एनजीओ चलाती हैं, वह किरण बेदी को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं. उनके अनुसार पहले भी एक महिला ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है, उससे क्या बदल गया? उनके विधायक जो हमारे क्षेत्र में 10 वर्ष हैं, उन्होंने हमारे क्षेत्र को गंदगी का ढ़ेर बना दिया है. हमारी बच्चियों को रास्ता चलते गुंडे पहले भी छेड़ते थे, अब क्या किरण बेदी स्वयं उनकी सुरक्षा के लिए आ जाएंगी? दिलशाद गार्डन में रहने वाली जयंती दीवान किरण बेदी पर विश्वास जताते हुए कहती हैं कि बेदी निश्चित तौर पर नौजवानों की सोच बदलने में सफल होंगी, जैसे उन्होंने नामांकन पत्र भरते जाते समय एक नौजवान को हेलमेट के न पहनने के लिए टोका था, इसी तरह उनकी छोटी–छोटी बात पर नज़र है.

ओखला दिल्ली का मुस्लिम–बहुल्य क्षेत्र है, वहां भी किरण बेदी का जादू चलता दिख रहा है. एक 35 वर्षीय घरेलू महिला तनवीर शाहिद तीन बच्चों की मां हैं, उनका कहना है कि किरण बेदी को वह एक उम्मीद की किरण की तरह देखती हैं. उनका कहना है कि मेरी 18 वर्षीय बेटी जब स्कूल जाती है तब से उसके घर वापस लौटने तक मैं परेशान रहती हूं. दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस की मैत्रेयी कॉलेज की डॉक्टर हरचरन कौर किरण बेदी के आक्रामक अंदाज़ को पसंद नहीं करती हैं. उनका कहना है कि नौकरशाह अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते, क्योंकि उनके यहां डिप्लोमेसी नहीं होती और यह भी एक सच्चाई है कि अफसरों की अफसरी कभी नहीं जाती. जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय की छात्रा आयशा के अनुसार उनके पुराने वीडियोज़ और ट्वीट देखिये तो लगता है कि मोदी को बुरा कहने वाली किरण बेदी ताकत के लिए किसी को भी भगवान बना लेंगी. जेएनयू की छात्रा शहला के अनुसार वह किरण बेदी और केजरीवाल दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करती हैं. उनका कहना है कि दोनों ही अन्ना के चेले हैं और दोनों को शोहरत की भूख है.

> मटियामहल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां की एक कांग्रेस कार्यकर्ता जुबैदा बेगम से जब किरण बेदी के बारे में पूछा गया तो वह भी किरण बेदी को भाजपा का चेहरा मानती हैं, लेकिन वह केजरीवाल की लोकप्रियता से भी इंकार नहीं कर रही हैं. उनका कहना है कि यदि किरण बेदी मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो उन्हें पुरानी दिल्ली की महिलाओं की ख़राब हालत को बदलना होगा, जहां घरेलू हिंसा, यौन अपराध और बलात्कार की घटनाएं आम हैं.

आर के पुरम की विधानसभा दिलशाद हमीदा एक हाउस वाइफ़ हैं, उनका सवाल है कि क्या किरण बेदी गैस सिलेंडर की सब्सिडी प्रत्यक्ष रूप से दिला पाएंगी? किरण बेदी की पार्टी के नेता कभी 10 बच्चों की, कभी 4 बच्चों की बात करते हैं. क्या महिलायें केवल बच्चे पैदा करने की मशीन हैं? क्या किरण बेदी अपनी पार्टी के पास जाकर इस मुद्दे को उठा पाएंगी? 27 वर्षीय साक्षी फिजियोथेरेपिस्ट हैं. वह दिक्षिणी दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में फिजिओथेरेपी विभाग में कार्यरत हैं. उनके ताऊ एमएम सचदेवा किरण बेदी के साथ पुलिस सब इंस्पेक्टर रहे हैं. साक्षी किरण बेदी के मुख्यमंत्री बनने से महिलाओं की सुरक्षा और दिल्ली की महिलाओं के हालात बेहतर होंगे. इसका कारण बताते हुए वह कहती हैं कि उनके ताऊ मिस्टर सचदेवा अक्सर उन्हें बताते थे कि वह एकमात्र पुलिस अधिकारी के साथ काम करते हैं जो बहुत निडर है. कहीं से भी फोन आता था, वह अंधेरे में भी अकेले ही निकल जाती थीं.

मटियामहल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां की एक कांग्रेस कार्यकर्ता जुबैदा बेगम से जब किरण बेदी के बारे में पूछा गया तो वह भी किरण बेदी को भाजपा का चेहरा मानती हैं, लेकिन वह केजरीवाल की लोकप्रियता से भी इंकार नहीं कर रही हैं. उनका कहना है कि यदि किरण बेदी मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो उन्हें पुरानी दिल्ली की महिलाओं की ख़राब हालत को बदलना होगा, जहां घरेलू हिंसा, यौन अपराध और बलात्कार की घटनाएं आम हैं. तुर्कमान गेट में रहने वाली गुलशन सरताज किरण बेदी के राजनीति में आने से बहुत आशांवित नहीं हैं. उनके अनुसार किरण बेदी क़ानून व्यवस्था का अनुभव ज़रूर रखती हैं, लेकिन व्यवहारिक राजनीति का नहीं. इसलिये उन्हें पहले अनुभव की आवश्यकता है. हर नेता सुरक्षा का दावा करता आ रहा है, लेकिन सुरक्षा अच्छी होती तो निर्भया घटना कभी नहीं होती, फिर हम किरण बेदी से कैसे आशा कर सकते हैं कि जबकि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आती है.

25 वर्षीय नूरैन अनवर पेशे से वकील हैं. वह बेदी की बड़ी प्रशंसक हैं. उनका कहना है कि केजरीवाल और बेदी का कोई मुक़ाबला नहीं है. क्षमता, अनुभव और प्रशासन का अनुभव किरण बेदी के पास कहीं अधिक है. महिलायें निश्चित ही उनकी उपस्थिति में स्वयं सुरक्षित महसूस करेंगी. वह महिलाओं के मामलों को बेहतर जानती–समझती हैं. महिलाओं से बातचीत करते हुए यह महसूस ज़रूर हुआ कि कांग्रेस पार्टी कहीं भी इस मुकाबले में नहीं है. इस बात का अहसास हर क्षेत्र की महिलाओं को ख़ूब है और सीधी टक्कर केजरीवाल और किरण बेदी के बीच है,लेकिन क्या किरण बेदी सच में मोदी से बड़ा चेहरा बन पाएंगी. भाजपा का चुनाव प्रचार तो खूब है और बेदी की वे लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं जो भाजपा में नहीं हैं. इसके अलावा दिल्ली की महिलाओं का वोट किरण बेदी के खाते में कितने प्रतिशत जायेगा और दिल्ली का भविष्य क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

विलय के बाद समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय हैसियत का क्या स्वरूप खड़ा होगा और जनता परिवार के नेताओं का ऐतिहासिक चरित्र देखते हुए भविष्य में महा–गठबंधन टूटा (जो अवश्यंभावी है), तो फिर समाजवादी पार्टी किस स्वरूप में आकर खड़ी होगी? सपा नेतृत्व के पास इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है. मुलायम सिंह यादव के पौत्र एवं सांसद तेज प्रताप सिंह और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी की शादी तय होने के बावजूद समाजवादी पार्टी विलय को लेकर इच्छुक नहीं दिख रही है.

दिल्ली चुनाव

कहां-कहां कांटे की टक्कर

ए यू आसिफ

आगामी सात फरवरी को दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कुल 923 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा यानी 23 उम्मीदवार नई दिल्ली और सबसे कम यानी छह उम्मीदवार अंबेडकर नगर क्षेत्र से है. इनमें तीन बड़ी पार्टियों भाजपा, आप और कांग्रेस के उम्मीदवार शामिल हैं तथा असल मुक़ाबले इन्हीं तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच अलग–अलग होंगे. भाजपा ने सात, आप ने छह और कांग्रेस ने पांच महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. इसी तरह भाजपा ने शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर अपने 66 टिकटों में मात्र एक, आप ने 70 में पांच और कांग्रेस ने छह टिकट मुसलमानों को दिए हैं. . ज्ञात रहे कि 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चार और जनता दल यूनाइटेड का एक यानी पांच मुस्लिम उम्मीदवार ही सफल हुए थे. पिछली बार मटिया महल से निर्वाचित जदयू उम्मीदवार शोएब इकबाल इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं.

सत्तर सीटों में से दस सीटें ऐसी हैं, जिन पर पूरे देश की निगाहें केंद्रित हैं. इनमें एक सीट नई दिल्ली की है, जहां आप के संयोजक एवं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कांग्रेस की पूर्व मंत्री किरण वालिया और भाजपा उम्मीदवार एवं दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रनेता नुपूर शर्मा से है. यह वही सीट है, जहां पिछली बार केजरीवाल ने कांग्रेस उम्मीदवार और तीन बार मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित को हराया था. इस बार केजरीवाल को अपनी सीट बचाने के अलावा बहुत कुछ साबित करना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी 2014 के संसदीय चुनाव में दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी. दूसरी सीट कृष्णा नगर की है, जो भाजपा का गढ़ रही है. यहां भाजपा ने हाल में शामिल हुईं किरण बेदी को टिकट दिया है. बेदी का मुकाबला आप के एसके बग्गा और कांग्रेस के वंशीलाल से है. यहां से किरण बेदी की आसान जीत की उम्मीद है. 2013 के चुनाव में यहां से वर्तमान केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन जीते थे.

तीसरी सीट है पटपड़गंज, जहां आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया का मुकाबला भाजपा उम्मीदवार एवं पूर्व विधायक (लक्ष्मी नगर) विनोद कुमार बिन्नी और कांग्रेस के अनिल कुमार से है. यहां सिसौदिया को बिन्नी से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है. ग़ौरतलब है कि बिन्नी ने पिछला चुनाव आप के टिकट पर लड़ा था. चौथी सीट मंगोलपुरी है, जहां आप उम्मीदवार एवं पूर्व मंत्री राखी बिड़ला का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार एवं पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान और भाजपा के सुरजीत से है. पांचवीं सीट है जनकपुरी. यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी का मुकाबला आप के राजेश ऋषि और कांग्रेस के सुरेश कुमार से है. यहां स्थिति इस लिहाज से दिलचस्प है कि सुरेश कुमार जगदीश मुखी के दामाद हैं. पिछली बार मुखी ने राजेश ऋषि को हराया था. छठवीं सीट मालवीय नगर है, जहां आप के विवादस्पद नेता सोमनाथ भारती का मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व स्पीकर योगानंद शास्त्री से है. यहां भाजपा ने नंदनी शर्मा को टिकट दिया है.

सातवीं सीट है द्वारका. यहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र आदर्श शास्त्री आप के उम्मीदवार हैं. वह कांग्रेस के महाबल मिश्रा और भाजपा के प्रद्युम्न राजपूत से टक्कर ले रहे हैं. यहां भी दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा का अपने साथी अनिल शास्त्री के बेटे से मुकाबला है. आठवीं सीट पटेल नगर की है, जहां कांग्रेस छोड़कर भाजपा में हाल में शामिल हुईं पूर्व मंत्री कृष्णा तीरथ आप के हजारी लाल चौहान और कांग्रेस के राजेश लिलोथिया से मुकाबला कर रही हैं. नौवीं सीट है सदर बाज़ार, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन आप के सोमदत्त और भाजपा के प्रवीण जैन से दो–दो हाथ करेंगे. दसवीं सीट ग्रेटर कैलाश है. यहां आप उम्मीदवार एवं पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज का मुकाबला भाजपा के राकेश गुलिया और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी एवं कांग्रेस उम्मीदवार शर्मिष्ठा मुखर्जी से है. शर्मिष्ठा के आने से इस सीट को काफी महत्व मिल गया है. पिछली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में पांच मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी मिली थी, जिनमें चार कांग्रेस से थे और एक जदयू से. अब जदयू से निर्वाचित हुए शोएब इकबाल के कांग्रेस में चले जाने से स्थिति बदल गई है. लेकिन, सीलमपुर के चौधरी मतीन अहमद और ओखला के आसिफ मोहम्मद खां को छोड़कर शेष तीनों पूर्व मुस्लिम विधायकों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है. अगर सीलमपुर की बात करें, तो यहां 65 प्रतिशत मुस्लिम वोट हैं और चौधरी मतीन अहमद काफी लोकप्रिय भी हैं. वह 1993 से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. घनी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र ओखला के आसिफ मोहम्मद खां भी मुसलमानों की समस्याओं, विशेषकर मुसलमानों की गिरफ्तारी के दौरान सरगर्म रहने के कारण पसंद किए जाते हैं. बीती 21 जनवरी को भी बरेलवी विचारधारा के विद्वान एवं कादरी मस्जिद के इमाम मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही की गिरफ्तारी के बाद हुए विरोध प्रदर्शन और उनकी रिहाई में आसिफ की मुख्य भूमिका रही. वह यहां आप उम्मीदवार अमानतुल्लाह खां और भाजपा उम्मीदवार ब्रह्म सिंह बिधूड़ी से टक्कर ले रहे हैं. अगर यहां मुस्लिम वोट आसिफ मुहम्मद खां और अमानतुल्लाह खां के बीच अधिक विभाजित होता है, तो भाजपा को फ़ायदा हो सकता है और बिधूड़ी जीत भी सकते हैं.

सत्तर सीटों में से दस सीटें ऐसी हैं, जिन पर पूरे देश की निगाहें केंद्रित हैं. इनमें एक सीट नई दिल्ली की है, जहां आप के संयोजक एवं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कांग्रेस की पूर्व मंत्री किरण वालिया और भाजपा उम्मीदवार एवं दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रनेता नुपूर शर्मा से है. यह वही सीट है, जहां पिछली बार केजरीवाल ने कांग्रेस उम्मीदवार और तीन बार मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित को हराया था.

65 प्रतिशत वोट वाले मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के शोएब इकबाल लोकप्रिय तो हैं, मगर बार–बार पार्टी बदलने के कारण बदनाम भी हो गए हैं. पहले राजद, फिर जदयू और अब कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे शोएब इकबाल की लड़ाई आप के आसिफ अहमद खां और भाजपा के एकमात्र उम्मीदवार शकील अंजुम देहलवी से है. बल्लीमारान से पांच बार विधायक रहे पूर्व मंत्री हारून यूसुफ से लोगों को सख्त शिकायत है कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया और कभी दिखाई नहीं पड़े. यूसुफ का मुकाबला इमरान हुसैन से है, जो इस क्षेत्र के युवा पार्षद हैं और युवाओं के बीच लोकप्रिय भी. मुस्तफाबाद के पूर्व विधायक हसन अहमद पिछली बार भाजपा के जगदीश प्रधान से बहुत मुश्किल से जीते थे. कहा जा रहा है कि अगर यहां वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, तो इस बार प्रधान यहां से निकल सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

जपा के चक्कर में टूट न जाए सपा..!

प्रभात रंजन दीन

जनता परिवार में विलय के नाम पर समाजवादी पार्टी में साफ़–साफ़ विभाजन हो गया है. यह विभाजन केवल कार्यकर्ताओं में नहीं, बल्कि नेताओं में भी है. सपा नेतृत्व को डर है कि बृहत्तर जनता पार्टी बनाने के चक्कर में कहीं समाजवादी पार्टी का ही नुक़सान न हो जाए. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विलय का फ़ैसला लिया, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी टूट भी सकती है. समाजवादी पार्टी के इस अंतर–कंपन पर भाजपा निगाह लगाए बैठी है. इस ख़तरे की आशंका को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने विलय पर पहल से परहेज करना शुरू कर दिया है. सपा नेतृत्व यह भी नहीं चाहता कि विलय के रास्ते में किसी भी अड़चन का ठीकरा उसके सिर फूटे. लिहाजा, बिहार में जदयू और राजद के बीच विलय को लेकर चल रही नोकझोंक और बढ़ रही अड़चनों का फ़ायदा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिल रहा है. विलय को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में नकारात्मक रुझान दिखाया है. इस महाविलय को सपा नेता लालू यादव की राजनीति बता रहे हैं, जिस पर पहले नीतीश कुमार धराशायी हुए और अब अगर सपा ने हाथ मिलाया, तो मुलायम सिंह धराशायी हो जाएंगे. लिहाजा, बृहत्तर जनता परिवार के आपसी विलय की योजना विलंबित–ताल में जाती साफ़–साफ़ दिख रही है.

जनता परिवार के नेताओं ने पिछले दिनों दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के घर पर बैठक करके विलय का फॉर्मूला तय किया था और आगे काम करने के लिए मुलायम सिंह यादव को अधिकृत किया था, लेकिन पार्टी कैडर में नकारात्मक रुख देखते हुए मुलायम ही इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. जंतर–मंतर पर हुआ धरना मुलायम का यह रुख बनाने में निर्णायक तौर पर सामने आया, क्योंकि यह पाया गया कि धरना–मंच पर लालू–नीतीश ने अपनी–अपनी राजनीति तो खूब चमकाई, लेकिन धरना में भारी भीड़ उत्तर प्रदेश से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं की थी. जंतर–मंतर पर धरने के बाद कार्यकर्ताओं में यह धारणा बनी कि पार्टी का विलय वे किसी भी क़ीमत पर न होने दें और अगर इसके बावजूद विलय हुआ, तो प्रदेश में समानांतर समाजवादी पार्टी का गठन हो. इस नजाकत को देखते और भांपते हुए समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने विलय प्रकरण पर उत्साह दिखाना फिलहाल बंद कर दिया है. समाजवादी पार्टी में सवाल उठ रहे हैं कि महाविलय के बाद कांग्रेस से गठबंधन करने के मसले पर सपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या जवाब देगा और महाविलय से सपा को क्या फ़ायदा मिलने वाला है?

विलय के बाद समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय हैसियत का क्या स्वरूप खड़ा होगा और जनता परिवार के नेताओं का ऐतिहासिक चरित्र देखते हुए भविष्य में महा–गठबंधन टूटा (जो अवश्यंभावी है), तो फिर समाजवादी पार्टी किस स्वरूप में आकर खड़ी होगी? सपा नेतृत्व के पास इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है. मुलायम सिंह यादव के पौत्र एवं सांसद तेज प्रताप सिंह और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी की शादी तय होने के बावजूद समाजवादी पार्टी विलय को लेकर इच्छुक नहीं दिख रही है. पार्टी इतना तो तय मानती है कि विलय से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई मजबूती नहीं मिलने वाली. उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के पास तगड़ा बहुमत है, जिससे पार्टी 2017 तक राज्यसभा में ज़्यादा सदस्य भेज सकती है. विलय का जो दृश्य सामने आ रहा है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि राजद और जदयू में विलय होने के बाद ही समाजवादी पार्टी के इसमें विलय की कोई संभावना बनेगी. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनता परिवार में विलय का साफ़–साफ़ मूड नहीं है. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव भी यह संकेत दे चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का विलय पहले होगा. उन्होंने साफ़ कहा कि अभी बिहार में विलय की ज़रूरत है, क्योंकि राज्य में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं. लेकिन, बिहार में ही विलय की प्रक्रिया सियासी दांव–पेंच में उलझ गई है. विभिन्न भोजों के ज़रिये विलय की राजनीति हो रही है. किसी में नीतीश नहीं जाते, तो किसी में लालू, तो किसी भोज में बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अप्रत्याशित रूप से हाजिर हो जाते है. इसी बीच मांझी भाजपा नेताओं से भी मिलते रहते हैं और इसी में विलय की सारी सियासत गड्डमड्ड होकर रह गई है. विलय होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में समानांतर समाजवादी पार्टी की संभावनाएं तेजी से तैयार हो रही हैं. पार्टी में उपेक्षित चल रहे वरिष्ठ नेताओं की खासी तादाद है, जो समानांतर समाजवादी पार्टी को नेतृत्व देने के लिए लगभग तैयार ही बैठे हैं. इनमें अमर सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे कई नेताओं के नाम लिए जा सकते हैं, जो यह मानते हैं कि जब नीतीश और लालू हाथ मिला सकते हैं, तो अमर और बेनी क्यों नहीं. सपा के अस्तित्व काल से ही बेनी वर्मा जुड़े हुए थे. मुलायम सिंह खुद बेनी वर्मा को बुलाने गए थे. तब जनेश्वर मिश्र को महासचिव पद की ज़िम्मेदारी दी गई थी. लेकिन, बाद में समाजवादी पार्टी पारिवारिक जागीर बन गई और उन्हीं जनेश्वर मिश्र पर अमर सिंह को महासचिव बनाकर थोप दिया गया. जनेश्वर मिश्र उपाध्यक्ष बना दिए गए थे. बाद के क्रम में बेनी प्रसाद वर्मा को भी बाहर जाना पड़ा और अमर सिंह को भी बेइज्जत होकर पार्टी से निकलना पड़ा. आज पार्टी में अच्छे–अच्छे नेता हाशिये पर पड़े हैं. अगर जनता परिवार के दलों का विलय होता है, तो ऐसे विक्षुब्ध नेताओं को समानांतर समाजवादी पार्टी गठित कर मूल समाजवादी संस्कृति की धारा पर लौटने का विकल्प या बहाना मिलेगा. क्योंकि, वे मानते हैं कि मुलायम, नीतीश, शरद, लालू, चौटाला, देवगौड़ा वगैरह के विलय के बाद वही सब अराजकताएं उभरेंगी, जो जनता पार्टी के काल में उभरी थीं. ऐसे में प्रदेश के नेता अपने भविष्य और वजूद को लेकर भी खासे चिंतित हैं. विलय के बाद आलाकमान के बदलने वाले स्वरूप को लेकर भी उत्तर प्रदेश के नेता आशंकित हैं और उन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि वे नीतीश या लालू को अपना नेता नहीं मानेंगे. सपा के ही कुछ लोग इनमें आजम खान का भी नाम लेते हैं, जो मुलायम के अलावा किसी अन्य को नेता नहीं मानते, यहां तक कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी नहीं. ■

विलय को लेकर घमासान

प्रस्तावित विलय को लेकर जदयू और राजद के बीच मचे घमासान का असर केवल बिहार में ही नहीं है, बल्कि इसका गहरा असर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर भी पड़ रहा है. बिहार में सत्तारूढ़ जदयू के कई विधायकों के भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहने की ख़बरें हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी सपा नेताओं और विधायकों के भाजपा के संपर्क में रहने की ख़बरें हैं. बिहार के भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने तो साफ़–साफ़ कह दिया है कि जदयू के 50 से अधिक विधायक भाजपा के समर्थन में हैं और वह जब चाहें, बिहार में जदयू की सरकार धराशायी करा सकते हैं. यह संदेश और संकेत केवल बिहार के लिए थोड़े ही है. सपा नेतृत्व को भी यह पता है कि पार्टी के कई नेता और विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं तथा कभी भी पाला बदल हो सकता है. ऐसे में विलय का निर्णय समाजवादी पार्टी के लिए आत्मघाती हो सकता है और इससे विक्षुब्धों को वैकल्पिक धारा चुनने का सरल मौक़ा मिल सकता है. समानांतर समाजवादी पार्टी के गठन की छटपटाहट का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अभी पिछले ही दिनों दादा मियां के उर्स पर लखनऊ में एकत्र हुए तक़रीबन दो दर्जन विधायकों और एक मंत्री ने सरकार के ख़िलाफ़ खुली नाराज़गी जाहिर की. इसकी ख़बर मिलने पर सपा प्रमुख ने अपने एक खास दूत को बात करने के लिए भेजा, लेकिन उन दूत महाशय को भी खूब खरी–खोटी सुननी पड़ी. वह दूत अखिलेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी हैं. ■

बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी सरकार की तुलना कुछ मामलों में भागवत झा आज़ाद के मुख्यमंत्रित्व काल से की जा सकती है. आज़ाद जी को भी अपनी पार्टी के विधायकों और प्रदेश नेतृत्व के ऐतिहासिक विरोध का सामना करना पड़ा था. उन दिनों कांग्रेसी विधायकों ने अपने आज़ाद–विरोध को तीखा बनाने के लिए गांधी टोपी पहनी थी और विधानसभा में दशकों बाद उस टोपी की बहार देखी गई थी.

दल और सरकार दोनों में दरार

मांझी के प्रशासन चलाने के तौर–तरीकों और बोली–बानी की बाहर तो बाहर, जद (यू) में भी तीखी प्रतिक्रिया हुई. यह अपनी राजनीतिक प्रकृति में घोर नकारात्मक रही. नतीजतन, नीतीश कुमार की आदर्श की राजनीति के चंदोवे में छेद दिखने लगे, बयानों के तीर चलने लगे. और, इस तरह नीतीश–भक्त दलीय नेताओं ने अपने भोथरे हथियार से चंदोवा तार–तार करना शुरू किया. ऐसे में राजनीतिक मर्यादा को खेत आना था और वही हुआ. हालात बिगड़ते चले गए और जीतन राम मांझी पर राजनीतिक ही नहीं, ग़ैर–राजनीतिक आक्षेप भी किए गए, उन्हें मानसिक तौर पर असंतुलित तक कहा जाने लगा.

सुकांत

बिहार के सत्तारूढ़ जनता दल (यू) में महीनों से चल रही तनातनी का अंत क्या है? इस सवाल का सीधा जवाब तो इसके सबसे बड़े नेता (सुप्रीमो कहिए) नीतीश कुमार के पास ही है, लेकिन वह भी ऐसा कुछ नहीं कर या कह रहे हैं, जिससे दल के भावी स्वरूप और जीतन राम मांझी सरकार के कामकाजी बने रहने को लेकर कोई विशेष उम्मीद जगे. हालांकि, महीनों की चुप्पी के बाद इस सप्ताह उन्होंने इस बावत अपना मुंह खोला और मांझी सरकार के किसी संकट से मुक्त रहने की बात कही. पर, इस भरोसे की सारी गंभीरता उनके दलीय प्रवक्ताओं ने अपने बयानों से दो–तीन घंटों के भीतर ही बेअसर कर दी. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके मंत्रियों पर बयानों के तीर चलाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है. तीरंदाज़ी का यह क्रम महीनों से चल रहा है. हालात सहज बनाने के कई नेताओं, जिनमें सहयोगी राजद प्रमुख लालू प्रसाद भी शामिल हैं, के प्रयास निष्फल होते जा रहे हैं.

हालांकि, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद सहित उनके अनेक नए–पुराने शुभचिंतक इसे भाजपा का कुचक्र बताकर अपने राजनीतिक चेहरे की चमक बरकरार रखना चाहते हैं, पर यह बात निरंतर स्पष्ट होती जा रही है कि जद (यू) की एकता और सरकार के भविष्य को लेकर विपक्षी भाजपा को बहुत कुछ करने–कहने की ज़रूरत नहीं है. जद (यू) के कुछ मुखर प्रवक्ताओं एवं नेताओं के राजनीतिक आचरण से इस चुनावी साल में भाजपा की राह आसान होती जा रही है. बिहार के राजनीतिक गलियारे में यह सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि सरकार क्या कर रही है या नीतीश कुमार की राजनीति किधर जा रही है या फिर आसन्न विधानसभा चुनाव में वह और उनका दल कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं या नहीं. बल्कि, सवाल यह होता है कि पार्टी और सरकार क्या इसी तरह लड़ते–भिड़ते चुनाव में पहुंचेगी? इस सवाल का जवाब केवल नीतीश कुमार के पास है.

जद (यू) के अघोषित सुप्रीमो नीतीश कुमार ने पिछले मई में संसदीय चुनाव में हार के लिए मुख्यमंत्री पद की शहादत देकर ज़िम्मेदार राजनीति की मिसाल पेश की थी. उस वक्त विधायकों, अनेक राजनीतिक एवं ग़ैर–राजनीतिक शुभचिंतकों की सलाह को दरकिनार करके उन्होंने जीतन राम मांझी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था और मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी. कुछ महीने तक तो सब कुछ ठीकठाक रहा, पर जल्द ही जीतन राम मांझी को लेकर जद (यू) में असहजता दिखने लगी थी. मांझी अपने काम को कैसे और किस दक्षता से अंजाम दे रहे थे, यह कहना तो फिलहाल कठिन है, पर इतना तो तय है कि वह संचिका और कलम के बदले जुबान पर अधिक भरोसा करने लगे. उनका राजनीतिकरण कुछ उल्लेखनीय घुटे हुए राजनेताओं के साथ हुआ है और कोई तीस वर्षों से वह राज्य की कांग्रेसी और ग़ैर–कांग्रेसी मंत्रिपरिषदों में शामिल रहे, लिहाज़ा यह उनकी राजनीतिक आकांक्षा का तकाज़ा रहा होगा.

मांझी के प्रशासन चलाने के तौर–तरीकों और बोली–बानी की बाहर तो बाहर, जद (यू) में भी तीखी प्रतिक्रिया हुई. यह अपनी राजनीतिक प्रकृति में घोर नकारात्मक रही. नतीजतन, नीतीश कुमार की आदर्श की राजनीति के चंदोवे में छेद दिखने लगे, बयानों के तीर चलने लगे. और, इस तरह नीतीश–भक्त दलीय नेताओं ने अपने भोथरे हथियार से चंदोवा तार–तार करना शुरू किया. ऐसे में राजनीतिक मर्यादा को खेत आना था और वही हुआ. हालात बिगड़ते चले गए और जीतन राम मांझी पर राजनीतिक ही नहीं, ग़ैर–राजनीतिक आक्षेप भी किए गए, उन्हें मानसिक तौर पर असंतुलित तक कहा जाने लगा. यह सब कुछ सार्वजनिक मंचों से या फिर मीडिया के ज़रिये हो रहा था. इतना ही नहीं, जद (यू) नेतृत्व के खास मंत्रियों ने जीतन राम मांझी के कार्यक्रमों का अघोषित बहिष्कार शुरू कर दिया. यह वह मौक़ा था, जब हालात संभालने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन नेतृत्व खामोश ही नहीं रहा, बल्कि उसका पलड़ा इन मांझी विरोधियों के पक्ष में झुका दिखने लगा. ऐसे में जो होना था, वही हुआ यानी जद (यू) के भीतर शीत युद्ध शुरू हुआ, जो अब चरम पर पहुंच गया है.

बिहार की सत्ता राजनीति का हाल यही है कि सरकार बंटी है, दल बंटा है, नीतीश–लालू का जनता परिवार बंटा है. सरकार के चार मंत्रियों ने खुलेआम कहा है कि मांझी के ख़िलाफ़ जारी अभियान जद (यू) के विनाश का कारण बन सकता है. इधर, नीतीश कुमार के पुराने राजनीतिक प्रबंधक एवं सहयोगी के तौर पर परिचित संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार तो मीडिया के ज़रिये जीतन राम मांझी को सोच–समझ कर बोलने की नसीहत तक देने से नहीं हिचक रहे हैं. सहकारिता मंत्री जय कुमार सिंह ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व में काम करने के अपने इरादे का खुलेआम ऐलान किया है. मांझी सरकार के अनेक वरिष्ठ मंत्रियों ने तो नेतृत्व परिवर्तन और नीतीश कुमार को पुन: मुख्यमंत्री बनाने के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक अभियान भी चलाया. इस अभियान का नेतृत्व वे मंत्री कर रहे हैं, जो दशकों से नीतीश कुमार की छाया के तौर पर जाने जाते रहे हैं. मांझी सरकार में उन वरिष्ठ मंत्रियों की संख्या भी कम नहीं है, जो एकमात्र नीतीश कुमार में अपनी निष्ठा जाहिर करने से नहीं चूकते हैं. हालत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते माह मांझी बदलो अभियान को सार्थक बनाने के लिए जद (यू) विधायकों के हस्ताक्षर लेने की पहल की गई, लेकिन इस अभियान का साथ देने के लिए तीन दर्जन विधायक भी खुलकर सामने नहीं आए. यह और ऐसे कई राजनीतिक कार्य हो रहे हैं, जो नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले लोग कर रहे हैं. बिहार के लोगों को यह सहज ही विश्वास नहीं होता कि इतना कुछ उनके अंजान रहते हो रहा है.

दल की ही बात लीजिए, प्रवक्ताओं समेत वे तमाम नेता भी जीतन राम मांझी और उनके समर्थक मंत्रियों पर सार्वजनिक तौर पर निशाना साध रहे हैं, जो बीते वर्षों में नीतीश कुमार के खास रहे हैं. उक्त सारे लोग हर अभियान में आगे किए जाते रहे हैं और पद–सुविधाओं से नवाजे जाते रहे हैं. इन दिनों उक्त सारे लोगों ने जीतन राम मांझी की सार्वजनिक निंदा का अभियान चला रखा है, लेकिन नीतीश कुमार ही नहीं, दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह तक कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हैं. सभी उक्त लोगों को अपने बयानों में संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं. कार्रवाई की बात तो दूर, सुप्रीमो टाइप उक्त बड़े नेता यह भी नहीं कहते कि प्रवक्ताओं की बात से दल सहमत नहीं है, ये प्रवक्ताओं के निजी विचार हैं. यहीं पार्टी नेताओं की बातें अपनी सार्थकता खो देती हैं, वे भ्रमजाल पैदा करने की कोशिश करती हैं. इससे यह हुआ कि जद (यू) का आम नेता–कार्यकर्ता खामोश होकर इस दल से मुक्त होने के विकल्प की तलाश में जुट गया है. भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी जब यह कहते हैं कि जद (यू) के पचास विधायक उनके संपर्क में हैं और भाजपा किसी भी क्षण मांझी सरकार को अपदस्थ कर सकती है, तो वह सच्चाई के निकट हैं. नीतीश कुमार की पार्टी के तीन दर्जन से अधिक विधायक भाजपा के काफी नज़दीक आ गए हैं और वे अब पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते.

यह राजनीतिक तनातनी, जो अपनी प्रकृति में अस्थिरता ही है, राज्य प्रशासन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है. जद (यू) की शैली में राज्य की नौकरशाही भी विभाजित हो गई है. अनेक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गंभीर मसलों पर भी मुख्यमंत्री मांझी से सलाह लेने की जहमत उठाना पसंद नहीं करते. उनके लिए साहब एक ही हैं और सचिवालय के गलियारों में उन साहब के लिए बड़े साहब विशेषण का इस्तेमाल किया जाता है. जीतन राम मांझी सरकार और बड़े साहब की न पटने वाली दूरी के कारण राज्य में किसी लोकप्रिय सरकार के होने का कोई संकेत कहीं नहीं मिल रहा है, सिवाय मंत्रिमंडल की बैठकों के. राज्य की क़ानून–व्यवस्था की स्थिति तो निम्नतम स्तर पर पहुंच ही रही है, विभिन्न योजनाओं का काम भी प्राय: ठप्प है. वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही तक भी विकास मद की चालीस प्रतिशत राशि का खर्च होना तो दूर की बात, उसका आवंटन तक नहीं हुआ है. जिसका मन जहां करता है, वहीं विकास की छोटी लाइन की गाड़ी की चेन खींच देता है. फिर, अनेक या पूर्ववर्ती सभी मुख्यमंत्रियों की तरह जीतन राम मांझी भी प्रतिबद्ध नौकरशाही के कायल हैं और उसी हिसाब से अधिकारियों की सेटिंग कर रहे हैं. हाल के कुछ महीनों में उच्चस्तरीय तबादलों में इसकी साफ़ झलक देखने को मिली है. वह भी खास सामाजिक समूह के अधिकारियों को खास–खास जगहों पर ला रहे हैं. उनके सलाहकारों में उक्त सामाजिक समूह के अधिकारी ही शामिल हैं. इससे सचिवालय स्तर पर ही नहीं, प्रमंडल और ज़िला स्तरों पर भी प्रशासन विभाजित हो गया है. विभाजित सरकार, विभाजित दल और विभाजित प्रशासन बिहार की प्रशासनिक जड़ता का मुख्य ज़िम्मेदार तत्व बन गया है.

बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी सरकार की तुलना कुछ मामलों में भागवत झा आज़ाद के मुख्यमंत्रित्व काल से की जा सकती है. आज़ाद जी को भी अपनी पार्टी के विधायकों और प्रदेश नेतृत्व के ऐतिहासिक विरोध का सामना करना पड़ा था. उन दिनों कांग्रेसी विधायकों ने अपने आज़ाद–विरोध को तीखा बनाने के लिए गांधी टोपी पहनी थी और विधानसभा में दशकों बाद उस टोपी की बहार देखी गई थी. उस अभियान के एक नायक मांझी सरकार में भी हैं. कांग्रेस की आंतरिक कलह और पटना से लेकर दिल्ली तक वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं एवं मंत्रियों के आज़ाद के पक्ष–विपक्ष में बंटे होने के कारण पिछड़े बिहार में विकास की चर्चा बंद हो गई थी. तब तक राजीव गांधी बोफोर्स कांड में घिर चुके थे और आलाकमान का इकबाल निम्नतम स्तर पर पहुंच गया था. एकाधिक कारणों से कांग्रेस के पंगु आलाकमान को विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष शिवचंद्र झा एवं कुछ अन्य बागी नेताओं के सामने घुटने टेकने पड़े थे. मांझी सरकार ऐसे ही राजनीतिक माहौल का सामना कर रही है, लेकिन उसका आलाकमान तो पटना में ही है और सरकार के आसपास. इसलिए यह अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं है कि आलाकमान किधर या किसके साथ है. जद (यू) के महानायक नीतीश कुमार बहुत सारे अच्छे कार्यों, अच्छी नीतियों और अच्छी बातों के लिए इतिहास में याद किए जाएंगे, ऐसा बिहार के अनेक बुद्धिजीवियों का कहना है और यह तथ्य भी है. लेकिन, यह भी सच है कि अपने उत्तराधिकारी जीतन राम मांझी के साथ जद (यू) के नेताओं के राजनीतिक आचरण को लेकर अपनी भूमिका के लिए भी वह याद किए जाते रहेंगे. ■

नीतीश कुमार और लालू प्रसाद सहित उनके अनेक नए-पुराने शुभचिंतक इसे भाजपा का कुचक्र बताकर अपने राजनीतिक चेहरे की चमक बरकरार रखना चाहते हैं, पर यह बात निरंतर स्पष्ट होती जा रही है कि जद (यू) की एकता और सरकार के भविष्य को लेकर विपक्षी भाजपा को बहुत कुछ करने-कहने की ज़रूरत नहीं है. जद (यू) के कुछ मुखर प्रवक्ताओं एवं नेताओं के राजनीतिक आचरण से इस चुनावी साल में भाजपा की राह आसान होती जा रही है. बिहार के राजनीतिक गलियारे में यह सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि सरकार क्या कर रही है या नीतीश कुमार की राजनीति किधर जा रही है या फिर आसन्न विधानसभा चुनाव में वह और उनका दल कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं या नहीं. बल्कि, सवाल यह होता है कि पार्टी और सरकार क्या इसी तरह लड़ते-भिड़ते चुनाव में पहुंचेगी?

feedback@chauthiduniya.com

समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी का गठन

पिता-पुत्र की समानांतर सूची से नेता-कार्यकर्ता हैरान

प्रभात रंजन दीन

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश इकाई की भंग कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर नई कार्यकारिणी की सूची जारी की. दो दिनों बाद ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विदेश यात्रा से लौटे और उन्होंने भी कार्यकारिणी की एक समानांतर सूची जारी कर दी. यह समाजवादी पार्टी का बेजोड़ नमूना है, जहां लोकतंत्र और अराजकता का संपूर्ण घालमेल साफ़-साफ़ दिखता है. पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं कि पूरक सूची ही जारी करनी थी, तो वह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ज़रिये जारी होती, तो फ़ैसलों की गरिमा बनी रहती. प्रदेश कार्यकारिणी में एक भी वरिष्ठ या कद्दावर नेता को शामिल नहीं किया गया है. यह भी कह सकते हैं कि एक भी कद्दावर नेता प्रदेश कार्यकारिणी में आने के लिए तैयार नहीं हुआ.

बहरहाल, यह उत्तर प्रदेश है, जहां महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर नहीं मिलते. समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अखिलेश यादव लंदन की सैर कर रहे होते हैं और यहां उनके पिता मुलायम सिंह यादव उन्हें प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी गठित कर देते हैं. मुलायम सिंह ने अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से प्रदेश कार्यकारिणी गठित की थी, तो प्रदेश अध्यक्ष ने लंदन से लौटते ही कार्यकारिणी में फिर से एक सूची और क्यों जोड़ दी? अगर कार्यकारिणी में कुछ और नाम जोड़ने ही थे, तो वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हवाले से ही क्यों नहीं जारी हुए? इसका मतलब यह भी है कि कार्यकारिणी के गठन को लेकर कोई मंत्रणा नहीं हुई या पूर्व-मंथन नहीं हुआ या फिर वैचारिकी में आपस में ही घनघोर अंतर्विरोध है. इस तरह के कई सवाल हैं, लेकिन उनके आधिकारिक जवाब नहीं मिलने हैं. 2017 का विधानसभा चुनाव सामने रखकर अगर यह कार्यकारिणी बनाई गई है, तो आप यकीन मान लें कि सपा ने अपने कंधे से जुआ उतार दिया है. प्रदेश कार्यकारिणी में किसी गांभीर्य और परिपक्वता के दर्शन नहीं होते. किसी वरिष्ठ नेता को प्रदेश कार्यकारिणी में आमंत्रित सदस्य के बतौर भी शामिल नहीं किया गया है.

सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में और उसके पहले भी मुलायम सिंह यादव अखिलेश सरकार के मंत्रियों की करतूतों के बारे में बार-बार कहते और मुख्यमंत्री को आगाह करते रहे. इस पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ताकतवर मंत्रियों पर कार्रवाई करने के बजाय दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों की भारी-भरकम सूची में कटौती कर दी थी. अखिलेश ने दर्जा प्राप्त मंत्रियों को हटाकर मुलायम सिंह का सम्मान रखने का संदेश देने की कोशिश की और लालबत्ती के बोझ पर अदालत की नाराज़गी दूर करने का काम भी कर लिया. लेकिन, प्रदेश कार्यकारिणी में उन्हीं लालबत्ती-वंचित लोगों में से अधिकांश को शामिल कर बेतालों को फिर उसी डाल पर लौटा लिया गया है. महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के पद से वंचित लोगों में थीं. लंदन यात्रा से लौटते ही अखिलेश यादव ने उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में सचिव बनाकर शामिल कर लिया. इसी तरह उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के अध्यक्ष उज्ज्वल रमण सिंह भी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के सुख से वंचित किए गए थे. उन्हें भी अखिलेश ने प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया.

फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी रहे राधेश्याम सिंह पटेल को अखिलेश यादव ने अपनी सूची में सपा का प्रदेश सचिव बनाया है. अपना दल से जाने के बाद राधेश्याम सिंह पटेल अखंड देशम नामक एक पार्टी चलाते थे. उन्होंने अपनी पार्टी का सपा में विलय करा दिया था. इतनी प्रभावशाली पार्टी का विलय कराने के लिए समाजवादी पार्टी पटेल का अनुग्रह मानती है. अखिलेश ने डॉ. रक्षपाल सिंह को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है. मुजफ्फरनगर के दंगों को लेकर हुए नुक़सान की भरपाई की कोशिश में पार्टी के ज़िलाध्यक्ष डॉ. रक्षपाल सिंह ने छेड़खानी और बलात्कार पर ऐसे विवादास्पद बयान दिए थे, जिससे पार्टी को और भी नुक़सान उठाना पड़ा था. अखिलेश ने उन्हें उसका पुरस्कार दे दिया. हीरा ठाकुर भी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के रूप में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सलाहकार बनाए गए थे. अखिलेश ने हीरा ठाकुर को भी कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है. बसपा से सपा में आए हीरा ठाकुर सार्वजनिक मंच से मायावती को अपशब्द कहने के कारण सपा नेताओं की ओर से भी निंदित हुए थे. अखिलेश ने उस निंदा का उन्हें पुरस्कार दिया. राज्य महिला आयोग की सदस्य रहीं अर्चना राठौर को अखिलेश ने कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है. अनुशासनहीनता के आरोप में समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए गए संजय लाठर को भी अखिलेश ने प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है. मुलायम सिंह ने प्रदेश कार्यकारिणी की जो सूची जारी की थी, उसमें उन्होंने अखिलेश सरकार के मंत्री अरविंद सिंह गोप को महासचिव बनाया. अखिलेश ने जब अपनी सूची जारी की, तो उसमें उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री नारद राय को सदस्य के बतौर शामिल किया. नारद राय अखिलेश के विश्वासपात्र माने जाते हैं. अखिलेश ने रविदास मेहरोत्रा को कार्यकारिणी में शामिल करने की सार्थकता भी दिखाई है. मेहरोत्रा सपा के पुराने जुझारू नेता है. उधर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की तरफ़ से जारी सूची में पूर्वांचल के कद्दावर नेता एवं अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश सिंह का नाम नदारद है. ओमप्रकाश सिंह के स्थान पर अरविंद सिंह गोप को महासचिव बनाया गया है. मुलायम सिंह ने 74 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी घोषित की. इसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फिर से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते हुए नरेश उत्तम को उपाध्यक्ष, अरविंद सिंह गोप को महासचिव, राजकिशोर मिश्रा को कोषाध्यक्ष और राजेंद्र चौधरी को प्रवक्ता सह सचिव बनाया गया. एसआरएस यादव सहित 21 अन्य लोग भी सचिव बनाए गए हैं. कार्यकारिणी में प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से 47 सदस्य भी शामिल किए गए हैं. दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के पद से हटाए गए सुनील सिंह साजन, राजपाल कश्यप, अनीस मंसूरी जैसे लोगों को भी प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिली. वे मुलायम सिंह की सूची के ज़रिये कार्यकारिणी में दाखिल हुए.

लोकसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी, जो नौ महीने के बजाय आठ महीने बाद फिर से पैदा हुई, लेकिन बेहद कमजोर हालत में. पिछले साल 22 मई को राज्य कार्यकारिणी भंग की गई थी. इसी के साथ 15 राज्यस्तरीय प्रकोष्ठों को भी उनके अध्यक्षों को हटाकर भंग कर दिया गया था. सब कुछ भंग चल रहा था, लेकिन अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष के पद पर यथावत चल रहे थे. लिहाजा, मुलायम सिंह द्वारा उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाए जाने की औपचारिकता निभाने का कोई औचित्य नहीं था. पिछले साल 27 अक्टूबर को ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नियुक्त हो गए थे और उन्हें जल्द ही कार्यकारिणी गठित करने की हिदायत दी गई थी. उसी समय सपा संसदीय बोर्ड का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, सचिव प्रो. राम गोपाल यादव और सदस्य के रूप में आजम खान, किरणमय नंदा, रवि प्रकाश वर्मा और शिवपाल यादव मनोनीत किए गए थे. मुख्यमंत्री अखिलेश को भी संसदीय बोर्ड का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया था.

अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली प्रदेश कार्यकारिणी में किसी भी वरिष्ठ नेता को स्थायी आमंत्रित सदस्य के बतौर शामिल करने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई. नई कार्यकारिणी में नए अपरिपक्व चेहरों की भरमार है और इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि नई कार्यकारिणी में कोई नेता ऐसा न शामिल हो जाए, जो अखिलेश के लिए भविष्य में कोई भी मुश्किल पैदा करे. इसलिए अखिलेश के प्रति निष्ठा रखने वालों को ही कार्यकारिणी में जगह मिली. मुलायम सिंह को छोड़कर पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से जुड़े लोगों को कार्यकारिणी में कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया. 2017 के विधानसभा चुनाव में जाने के पहले समाजवादी पार्टी का यही लोकतांत्रिक चेहरा सामने आया है. अखिलेश यादव को आगे कर गठित कार्यकारिणी के बूते समाजवादी पार्टी स्वयं के युवा पार्टी होने का दावा भले करे, लेकिन पार्टी के भीतर का असली युवा संगठन ही नदारद है. सपा के चारों युवा संगठन जैसे समाजवादी छात्रसभा, समाजवादी युवजन सभा, लोहिया वाहिनी और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड भंग हैं, पार्टी के युवा कार्यकर्ता भटक रहे हैं, लेकिन इन संगठनों के गठन को लेकर कोई कवायद नहीं हो रही है. इन संगठनों को नेतृत्व कौन दे, यह भी एक बड़ा सवाल है.■

feedback@chauthiduniya.com

अखिलेश यादव की सूची

लीलावती कुशवाहा-सचिव, राधेश्याम सिंह पटेल- सचिव, दिनेश कुमार सिंह-सचिव, डॉ. रक्षपाल सिंह- सदस्य, हीरा ठाकुर-सदस्य, रविदास मेहरोत्रा-सदस्य, अर्चना राठौर-सदस्य, रंजना सिंह-सदस्य, प्रदीप दीक्षित-सदस्य, नारद राय-सदस्य, उज्ज्वल रमण सिंह- सदस्य, राकेश पाल-सदस्य, विश्वनाथ विश्वकर्मा-सदस्य, राम किशोर अग्रवाल-सदस्य, अजित प्रसाद-सदस्य, संजय लाठर-सदस्य, राजपाल सिंह-सदस्य, श्रीमती सुशीला सरोज-विशेष आमंत्रित सदस्य, अशोक चंद्र शुक्ला-विशेष आमंत्रित सदस्य, प्रेम प्रकाश वर्मा-विशेष आमंत्रित सदस्य, जय गोपाल सोनी-विशेष आमंत्रित सदस्य, समरजीत सिंह-विशेष आमंत्रित सदस्य, लाखन सिंह पाल-विशेष आमंत्रित सदस्य, सुधीर रावत-विशेष आमंत्रित सदस्य.

मुलायम सिंह यादव की सूची

अखिलेश यादव-अध्यक्ष, लखनऊ. नरेश उत्तम-उपाध्यक्ष, फतेहपुर. अरविंद सिंह गोप-महासचिव, बाराबंकी. राज किशोर मिश्रा-कोषाध्यक्ष, लखनऊ. राजेंद्र चौधरी-प्रवक्ता सह सचिव, लखनऊ. एसआरएस यादव-सचिव, लखनऊ. अनीस मंसूरी-सचिव, लखनऊ. मीना राजपूत-सचिव, फिरोजाबाद. मुजाहिद किदवई-सचिव, अलीगढ़. एसएन सिंह-सचिव, इलाहाबाद. श्यामलाल पाल-सचिव, इलाहाबाद. अशोक पटेल, पूर्व सांसद-सचिव, फतेहपुर. समरनाथ सिंह चौहान-सचिव, जौनपुर. हंसराज ध्रुवे गौड़-सचिव, चंदौली. राम दुलार राजभर-सचिव, आजमगढ़. सनातन पांडेय-सचिव, बलिया. पीएन चौहान-सचिव, कुशीनगर. हाजी मुहम्मद अनवर खां-सचिव बहराइच. विद्यावती राजभर-सचिव, अंबेडकर नगर. डॉ. आरए उस्मानी-सचिव, लखीमपुर खीरी. डॉ. राजपाल कश्यप-सचिव, हरदोई. उमाशंकर चौधरी-सचिव, उन्नाव. सोहन लाल त्यागी-सचिव, गाजियाबाद. सतेंद्र उपाध्याय-सचिव, जौनपुर. प्रो. जाहिद खां-सचिव, बरेली. नईमुल हसन-सचिव, बिजनौर. रमेश प्रजापति-सचिव, मेरठ. आनंद भदौरिया-सदस्य, सीतापुर. सुनील सिंह यादव-सदस्य, उन्नाव. महाराज सिंह धनगर-सदस्य, आगरा. श्रीमती कृष्णा सिंह-सदस्य, आगरा. अश्विनी यादव-सदस्य, आगरा. मिश्रीलाल राजपूत-सदस्य, आगरा. श्रीमती ओमवती यादव-सदस्य, हाथरस. राघवेंद्र तोमर-सदस्य, फिरोजाबाद. नीलम रोमिला सिंह-सदस्य, कानपुर नगर. अमिताभ बाजपेयी-सदस्य, कानपुर नगर. गोपाल यादव-सदस्य, इटावा. पम्पी जैन-सदस्य, कन्नौज. मोहम्मद इरफानुल हक़ कादरी-सदस्य, कन्नौज. दीपमाला कुशवाहा-सदस्य, झांसी. अच्छे लाल निषाद-सदस्य, बांदा. श्रीमती अंबेश कुमारी जाटव-सदस्य, हमीरपुर. निर्भय सिंह पटेल-सदस्य, चित्रकूट. मुश्ताक काजमी-सदस्य, इलाहाबाद. पंधारी यादव-सदस्य, इलाहाबाद. दलजीत निषाद-सदस्य, फतेहपुर. बहादुर सिंह यादव-सदस्य, वाराणसी. कन्हैया लाल गुप्ता-सदस्य, वाराणसी. जगदंबिका सिंह पटेल-सदस्य, मिर्जापुर. जनार्दन बिंद-सदस्य, भदोही. राम निहोर यादव-सदस्य, सोनभद्र. नफीस अहमद-सदस्य, आजमगढ़. संग्राम सिंह यादव-सदस्य, आजमगढ़. नथुनी कुशवाहा-सदस्य, कुशीनगर. कृष्णभान सिंह सैंथवार-सदस्य, गोरखपुर. अवधेश सिंह यादव-सदस्य, गोरखपुर. राम ललित चौधरी-सदस्य, बस्ती. लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद-सदस्य, संत कबीर नगर. श्रीमती जानकी पाल-सदस्य, सुल्तानपुर. शकील अहमद-सदस्य, सुल्तानपुर. धनंजय उपाध्याय-सदस्य, लखीमपुर खीरी. राम कुमार कश्यप-सदस्य, पीलीभीत. वीरेंद्र सिंह गंगवार-सदस्य, बरेली. मिथिलेश कुमार कठेरिया-सदस्य, शाहजहांपुर. बुद्ध सिंह यादव-सदस्य, अमरोहा. डॉ. एसटी हसन-सदस्य, मुरादाबाद. विक्रम सिंह भाटी-सदस्य, गौतम बुद्ध नगर. मांगे राम कश्यप-सदस्य, सहारनपुर. बख्तावर सिंह-सदस्य, सहारनपुर. श्याम लाल बच्ची सैनी-सदस्य, मुजफ्फर नगर. सत्यवीर सिंह प्रजापति-सदस्य, मुजफ्फर नगर. मुकेश चौधरी-सदस्य, मुजफ्फर नगर. श्रीमती सुनीता चौहान-सदस्य, बुलंदशहर.

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

बेशक, संघीय सरकार के हाथ में जो भी होगा, जैसा उन्होंने सेंसर बोर्ड के साथ किया, वैसा करेंगे. सेंसर बोर्ड के साथ जो भी हुआ, बहुत ग़लत है. पुराने लोगों को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर कर दिया गया और इसके बाद अपने लोगों को भर दिया गया. ख़तरनाक बात यह है कि धर्मगुरुओं के पाखंड का मज़ाक उड़ाती फिल्म पीके की तो संघ परिवार ने आलोचना की, लेकिन एमएसजी जैसी फिल्म, जो अंधविश्वास को प्रोत्साहित करती है, उसे सर्टिफिकेट देने की बात कही जा रही है. अगर ऐसा ही चलता रहा, तो लगता है कि मुझे महेश भट्ट जैसे लोगों के साथ खड़ा होना होगा, जो कहते हैं कि फिल्मों में कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए.

भाजपा परिवर्तन के दौर से गुज़र रही है

दिल्ली में भाजपा ने अकल्पनीय काम किया है. वह दिल्ली में एक ऐसे चेहरा सामने लाई है, जिसका किसी भी राजनीतिक दल में कोई अनुभव नहीं रहा है. वह आज भाजपा का चेहरा है. यह सच है कि किरण बेदी के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनका एक उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी वाला रिकॉर्ड भी नहीं रहा है. पर आरएसएस के कुछ लोगों से मेरी बात के बाद मैं उनकी रणनीति में शामिल अंतर्दृष्टि बता सकता हूं. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में उनके पास कोई जाना-पहचाना चेहरा तक नहीं है. ऐसे में, जब तक उनके पास कोई जाना-पहचाना चेहरा न हो, तब तक वे कोई ताकत नहीं बन सकते. वे बंगाल में एक अच्छे रिकॉर्ड वाले नेता की तलाश में हैं, जो उनकी पार्टी का नेतृत्व कर सके. वे अपने संगठन एवं कार्यकर्ताओं को लेकर आश्वस्त हैं कि वे सब मदद करेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें एक चेहरे की आवश्यकता है.

इसलिए मैंने उनसे दिल्ली के बारे में पूछा. मैंने कहा कि दिल्ली में वे एक मजबूत पार्टी होने के साथ-साथ सत्ता में भी रहे हैं, कार्यकर्ता भी हैं, तो फिर उन्हें ऐसे निर्णय की ज़रूरत क्यों पड़ी? उनका नम्र जवाब था कि उनके स्थापित नेता बहुत पुराने हो गए हैं और नए लोगों में ऐसा कोई चेहरा नहीं है, जिससे उम्मीद की जा सके कि वह चुनाव जिता देगा. इसलिए उन्होंने चुनाव में जीत के लिए किरण बेदी को चुना. यह स्पष्टीकरण संघ परिवार की सोच में निहित अंतर्दृष्टि सामने लाता है. वे अब जल्दी में हैं. वे महसूस कर रहे हैं कि मोदी के शीर्ष पर होने के साथ ही उन्हें एक अखिल भारतीय पार्टी बनने और राष्ट्र की चेतना से कांग्रेस को हटाने का मौक़ा मिल गया है. उनके साथ मेरी इस छोटी चर्चा से यही उद्देश्य सामने निकल कर आया. कांग्रेस को हटाने को लेकर वे सीधे-सीधे कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उसका मतलब यही था. इसी तरह जम्मू-कश्मीर में मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाना सबसे बुरा काम हो सकता है, जिसे भाजपा कर सकती है.

कम से कम नेशनल कांफ्रेंस, जब बात अलगाववादियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की आती है, तो वह पीडीपी से बेहतर है. पीडीपी पर नरम अलगाववाद का आरोप है, लेकिन भाजपा उसके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है. क्योंकि, वह देश के हर कोने में अपनी मौजूदगी चाहती है, जैसे कांग्रेस सालों तक देश के हर कोने में मौजूद रही थी. यह भाजपा की नई रणनीति है. यह अच्छा भी है और बुरा भी. बुरा इसलिए, क्योंकि भाजपा हमेशा कहती रही है कि वह औरों से अलग है, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, उसे देखते हुए यही कह सकते हैं कि वह भी अन्य पार्टियों की तरह है. वह कांग्रेस की तरह ही बाहरी लोगों को लेगी, धीरे-धीरे उसका कठोर अनुशासन कमज़ोर होगा और फिर वह भी अन्य पार्टियों की तरह हो जाएगी. यह उनके लिए अच्छा नहीं है, जो संघ परिवार का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे राजनीतिक पर्यवेक्षकों एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं, जो सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक देश के बारे में चिंतित हैं, के लिए अच्छी बात यह है कि अगर भाजपा भी अन्य पार्टियों की तरह ही अपना काम करती रही, तो ये सारे ख़तरे अपने आप दूर हो जाएंगे. और, वे एक मजबूत आरएसएस

हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प दौर में जी रहे हैं. भाजपा परिवर्तन के दौर से गुज़र रही है. अब हम किरण बेदी जैसी शख्सियत को देखें. उन्हें पार्टी में लेना ठीक है, टिकट देना भी ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट करना तो हद है. इससे पता चलता है कि जिन उच्च मानदंडों पर भाजपा खुद को बता रही थी, उनका पतन हुआ है. लेकिन, जैसा कि मेरे उन दोस्त ने मुझसे कहा कि सत्ता में आने के लिए यही एक रास्ता बचा था.

आधारित पार्टी बनाने में कभी सक्षम नहीं होंगे. यह उदार पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ एक व्यापक पार्टी होगी, जो मजबूती से संघ की विचारधारा नहीं अपनाएंगे. वे जबरदस्ती किसी पर हिंदू धर्म नहीं थोप पाएंगे.

बेशक, संघीय सरकार के हाथ में जो भी होगा, जैसा उन्होंने सेंसर बोर्ड के साथ किया, वैसा करेंगे. सेंसर बोर्ड के साथ जो भी हुआ, बहुत ग़लत है. पुराने लोगों को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर कर दिया गया और इसके बाद अपने लोगों को भर दिया गया. ख़तरनाक बात यह है कि धर्मगुरुओं के पाखंड का मज़ाक उड़ाती फिल्म पीके की तो संघ परिवार ने आलोचना की, लेकिन एमएसजी जैसी फिल्म, जो अंधविश्वास को प्रोत्साहित करती है, उसे सर्टिफिकेट देने की बात कही जा रही है. अगर ऐसा ही चलता रहा, तो लगता है कि मुझे महेश भट्ट जैसे लोगों के साथ खड़ा होना होगा, जो कहते हैं कि फिल्मों में कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए. मैं हमेशा इसका पक्षधर रहा हूं कि भारत जैसे देश में कुछ न कुछ सेंसरशिप ज़रूर होनी चाहिए.

हम स्कैंडनिवियाई देशों की तरह यह नहीं कह सकते कि लोग बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हैं. लेकिन, अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा, तो सेंसर बोर्ड तार्किक, निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ पर कैंची चलाएगा और अंधविश्वास, जादू एवं पौराणिक कथाओं को तर्कसंगत ठहराएगा. मुझे नहीं लगता है कि ऐसे में सेंसर बोर्ड की कोई ज़रूरत है.

हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प दौर में जी रहे हैं. भाजपा परिवर्तन के दौर से गुज़र रही है. अब हम किरण बेदी जैसी शख्सियत को देखें. उन्हें पार्टी में लेना ठीक है, टिकट देना भी ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट करना तो हद है. इससे पता चलता है कि जिन उच्च मानदंडों पर भाजपा खुद को बता रही थी, उनका पतन हुआ है. लेकिन, जैसा कि मेरे उन दोस्त ने मुझसे कहा कि सत्ता में आने के लिए यही एक रास्ता बचा था.

यदि वे अपनी विचारधारा से बहकते रहे और ऐसे चेहरे प्रोजेक्ट करते रहे, जो जनता को स्वीकार्य न हों, तो फिर उनके लिए उन राज्यों में आना मुश्किल हो जाएगा, जहां वे अभी नहीं हैं. अगले कुछ हफ्तों में पता लग जाएगा कि क्या होने जा रहा है. एक और बात उन्होंने कही कि केजरीवाल अभी भी मजबूत हैं और भाजपा को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ेगा. ये वे लोग हैं (जिनसे बात हुई है), जो सक्रिय राजनीति में नहीं हैं और न भाजपा का हिस्सा हैं. ये संघ से जुड़े लोग हैं और इसलिए एक निष्पक्ष विचार दे सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

मृत्यु का कोई उपाय कीजिए

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

जेपी से मेरी सबसे पहले कब मुलाकात हुई, इसका निश्चित समय तो मैं नहीं बता सकता. लेकिन जब वह यहां स्कूल में पढ़ते थे, तभी हम मिले थे. यह 1920 से पहले की बात है. बहुत घनिष्ठता तो जब अमेरिका से जयप्रकाश जी लौटकर आए, तब हुई. इसमें एक कारण यह भी था कि प्रभावती जी बाबू बृजकिशोर प्रसाद की लड़की थीं और बाबू बृजकिशोर प्रसाद से मेरा अत्यंत निकट संबंध था. यहां तक कि सदाकत आश्रम में हम लोगों के कमरे अगल-बगल में थे. वह गठिया के रोगी थे, मैं दमे का रोगी था. वैसे भी बृजकिशोर बाबू की मुझ पर कृपा रही है, जिसके गवाह उनके दोनों लड़के हैं. उन्होंने अपनी पत्नी से मुझको दिखाकर कहा, देखो, दो लड़के तुम्हारे तो हैं, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा लड़का यह है. प्रभावती जी से मेरा संबंध इस लिहाज से नहीं था कि वह जयप्रकाश जी की पत्नी हैं, बल्कि इस लिहाज से भी था कि वह बृजकिशोर बाबू की लड़की थीं.

जयप्रकाश जी 1929 में हिंदुस्तान आ गए थे और सन् 30 के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा भी लिया था. उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के दफ्तर में लेबर रिसर्च का विभाग खुला, उसके वह इंचार्ज थे. हम लोगों का मिलना-जुलना होता था, आते-जाते थे. लेकिन उस समय का मिलना ऐसा ही था, जैसे वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिकारी हों और हम लोग भी कांग्रेस के आदमी हों. 1931 में हम लोगों ने बिहार में जब सोशलिस्ट पार्टी बनाई, तो जयप्रकाश जी का ध्यान हम लोगों की ओर आकर्षित हुआ. वह तो अमेरिका में कम्युनिस्ट बन चुके थे, पर यहां आने के बाद उनमें थोड़ा परिवर्तन हुआ. परिवर्तन यह हुआ कि 1930 के आंदोलन की जब कम्युनिस्टों ने मुखालफत की, तो जयप्रकाश जी उनके साथ रहने में हिचकिचाने लगे. जयप्रकाश जी का ख्याल था कि उन लोगों को भी हिस्सा लेना चाहिए.

कम्युनिस्ट 1928 की अपनी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल थीसिस के मुताबिक यह समझते थे कि गुलाम मुल्कों में राष्ट्रीय आज़ादी के जो आंदोलन हो रहे हैं, उनका रूप समाजवादी या साम्यवादी नहीं है, बल्कि यह बुर्जुआ मूवमेंट है. इसलिए इनकी मुखालफत करनी चाहिए. इसीलिए सन् 1930 का जो सत्याग्रह था, इसकी कम्युनिस्ट पार्टी ने मुखालफत की. जयप्रकाश जी इस मामले में उनके साथ नहीं थे, इसीलिए उन्होंने यह सोचा कि यहां एक पार्टी बननी चाहिए. यह ख्याल उनके दिमाग में संभवत: सन् 31 में आया था, लेकिन तब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी. सन् 32 में हम लोग फिर जेल चले गए. जेल के अंदर हमने साम्यवादी साहित्य भी पढ़ा तथा 1930 के आंदोलन का अनुभव भी था. इसके फलस्वरूप हम लोग यह सोचने लगे कि राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले नौजवानों का एक ऐसा दल होना चाहिए, जिसके सामने सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से देश के भविष्य की एक पूरी तस्वीर हो. आज़ादी मिलने के बाद मुल्क की स्थिति क्या होगी, यह अगर हम पहले से नहीं सोचेंगे, तो ठीक नहीं होगा.

1932 में शुरू हुआ आंदोलन 1933 तक चलता रहा. जब हम लोग छूटकर आए, तो पटना में ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का जलसा हुआ. तब हिंदुस्तान में एक ही सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसका राष्ट्रीय आंदोलन से भी ताल्लुक था. वह थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी. पर इस तरह के विचार रखने वाले लोग भिन्न-भिन्न प्रांतों में भी थे. फीरोजचंद जी थे, उन्होंने पंजाब में 1931 के आंदोलन के समय ही सोशलिस्टों का एक ग्रुप बनाया था तथा महाराष्ट्र में भी एक ग्रुप बना था, लेकिन आपस में कोई सामंजस्य और समन्वय नहीं था. इनमें सबसे संगठित और प्रभावशाली सोशलिस्ट पार्टी बिहार की ही थी. उस जमाने में उसके तीन मंत्री थे-मैं, राहुल सांकृत्यायन और फूलन प्रसाद वर्मा. बेनीपुरी जी अवधेश्वर, श्यामनंदन बाबू तथा मणींद्रनाथ राय आदि बहुत से नौजवान लोग भी थे. 1934 में बनारस में एक बैठक हुई, जिसमें इस तरह के सब लोग बुलाए गए. वहां तय हुआ कि ऐसे जितने भी लोग राष्ट्रीय आंदोलन में काम कर रहे हैं, जो समाजवादी विचारधारा रखते हैं, समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं और जनतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों की एक पार्टी बनाई जाए.

इसके फलस्वरूप पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में पहली कांफ्रेंस बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ. हम लोगों ने जो सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, उसमें कांग्रेस नाम नहीं दिया था. इसीलिए बाद में बिहार की पार्टी जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की शाखा बन गई, तब भी यह शर्त कायम रही. बाकी सब जगह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहलाती थी, लेकिन बिहार में हम लोग अपने को सोशलिस्ट ही कहते रहे, हालांकि थे उसकी ही शाखा. हम लोगों ने यही शर्त रखी थी कि अपना नाम बदले बिना यदि हम आपकी शाखा नहीं हो सकते, तो हम एफीलिएटेड बॉडी बनकर आपकी शाखा में रहेंगे. वहां बहुमत से यह तय हुआ कि चूंकि सोशलिस्ट पार्टी के नाम से कुछ और संस्थाएं जैसे सोशलिस्ट रिपब्लिन ऑर्मी या कुछ छोटी-मोटी सोशलिस्ट पार्टियां बन गई थीं, इसलिए उन सबसे खुद को अलग करने के लिए और यह बतलाने के लिए कि हम राष्ट्रीय आंदोलन और एक राष्ट्रीय संगठन का हिस्सा हैं, यह तय किया गया कि अखिल भारतीय पार्टी का नाम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी होगा. आचार्य नरेंद्र देव जी ने वहां अध्यक्षता की और जयप्रकाश जी उसके जनरल सेक्रेटरी चुने गए. वहीं यह भी तय हुआ कि चूंकि कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में हो रहा है, इसलिए इस पार्टी का भी पहला अधिवेशन उसी अवसर पर बंबई में हो. वरली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और पास ही के एक मकान के बड़े हॉल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ. *(क्रमश:)* ■

जयप्रकाश जी 1929 में हिंदुस्तान आ गए थे और सन् 30 के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा भी लिया था. उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के दफ्तर में लेबर रिसर्च का विभाग खुला, उसके वह इंचार्ज थे. हम लोगों का मिलना-जुलना होता था, आते-जाते थे. लेकिन उस समय का मिलना ऐसा ही था, जैसे वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिकारी हों और हम लोग भी कांग्रेस के आदमी हों. 1931 में हम लोगों ने बिहार में जब सोशलिस्ट पार्टी बनाई, तो जयप्रकाश जी का ध्यान हम लोगों की ओर आकर्षित हुआ. वह तो अमेरिका में कम्युनिस्ट बन चुके थे, पर यहां आने के बाद उनमें थोड़ा परिवर्तन हुआ.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

बहस से असल मुद्दा गायब है

किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल कभी बहुत गहरे दोस्त थे, लेकिन उस गहरी दोस्ती में भी एक प्रतिद्वंद्विता छिपी हुई थी. जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, तब हमें संगठक और आंदोलन के चेहरे के रूप में अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे थे. वहीं दूसरी तरफ़ किरण बेदी मंच पर झंडा फहरा कर, इस कोने से उस कोने तक जाकर अपने नाम, अपने चेहरे और अपने अतीत के बल पर स्वयं को आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में स्थापित कर रही थीं. अन्ना हजारे ने मंच पर बातचीत करने के लिए ज़्यादातर अरविंद केजरीवाल को बुलाया, लेकिन किरण बेदी भी शाना-ब-शाना उनके दाएं-बाएं बनी रहीं.

यह बात मैं सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूं, ताकि लोगों को पता चले कि महत्वपूर्ण बनने की प्रतिद्वंद्विता बहुत पुरानी है. इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे की असहमति से या कहें कि सहमति से (क्योंकि केजरीवाल आप को अन्ना की सहमति से बनाई हुई पार्टी कहते हैं) राजनीतिक पार्टी बनाई, तो उसमें किरण बेदी नहीं गईं, क्योंकि किरण बेदी को मालूम था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में उन्हें हमेशा नंबर दो या नंबर तीन की स्थिति में रहना पड़ेगा. इसलिए पहले तो उन्होंने अन्ना हजारे का साथ देकर अरविंद केजरीवाल का जबरदस्त विरोध किया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के हर क़दम का विरोध करती रहीं. किरण बेदी अन्ना हजारे के पास जब तक जाती थीं, वह अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध ही बात करती थीं.

दूसरी तरफ़ अरविंद केजरीवाल ने कभी भी किरण बेदी को विरोध करने लायक व्यक्तित्व नहीं माना. वह उन्हें अनदेखा करते रहे और यह स्वाभाविक था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक पार्टी बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को अपना लक्ष्य बना चुके थे. जब दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनाव आए, तब उन्हें लग रहा था कि शायद किरण बेदी को भारतीय जनता पार्टी उनके ख़िलाफ़ अपना चेहरा बनाए. इसके लिए लालकृष्ण आडवाणी की तरफ़ भी लोग देख रहे थे, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी किरण बेदी को बहुत चाहते हैं. फिर भी भारतीय जनता पार्टी खामोश रही, क्योंकि केंद्र में यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से निर्णय नरेंद्र मोदी के हाथ में आ गया था, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे और राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी को अपरंपरागत तरीकों से सत्ता में लाने के पक्षधर नहीं थे. इसीलिए तमाम अफ़वाहों के बावजूद किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद की दावेदार नहीं बन पाईं. पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में एक परेशानी खड़ी हो गई थी. कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट और कुछ अरविंद केजरीवाल का कैंपेन करने का तरीका भारतीय जनता पार्टी को डरा गया और तब नरेंद्र मोदी ने यह फ़ैसला किया कि उन्होंने जिस तरह महाराष्ट्र में पार्टी को सत्ता दिलाई, जिस तरह झारखंड में दिलाई, जिस तरह हरियाणा में दिलाई, उसी तरह अगर वह दिल्ली में सत्ता भाजपा को दिलाना चाहते हैं यानी अपने जीते हुए राज्यों में दिल्ली को शामिल करना चाहते हैं, तो उन्हें स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा बाहर से किसी को लाना पड़ेगा और इसके लिए किरण बेदी से योग्य कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था. किरण बेदी भाजपा का चेहरा बन गईं. किरण बेदी के भाजपा का चेहरा बनते ही जहां एक तरफ़ भाजपा में अंतर्विरोध पैदा होने शुरू हुए, वहीं आम आदमी पार्टी में भी ऐसे व्यक्तित्व खड़े होने लगे, जिन्हें अरविंद केजरीवाल से अपना हिसाब बराबर करना था.

किरण बेदी के स्वभाव और अरविंद केजरीवाल के स्वभाव में काफी समानताएं हैं. किरण बेदी कहती भले हों कि उन्होंने चालीस साल जनता के बीच काम किया, लेकिन हक़ीक़त यह है कि उन्होंने चालीस साल जनता के बीच नहीं, बल्कि जनता से अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले पुलिस विभाग में काम किया है. हिंदुस्तान में पुलिस से जनता डरती है और किरण बेदी भी उसी पुलिस विभाग का एक अंग रही हैं. और, उन्हें कभी भी पुलिस के ऐसे चेहरे के रूप में नहीं जाना गया, जिसे जनता पसंद करती है. किरण बेदी क़ानून का कड़ाई से पालन कराती हैं, नियम की व्याख्या अपने ढंग से करती हैं और उसमें वह उतनी दूर चली जाती हैं, जिसमें तीस हजारी कोर्ट में वकीलों की बेरहमी से पिटाई हो जाती है. सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बे उन्हीं की निगरानी में धोए जाते हैं. दिल्ली के 75 हज़ार वकीलों का बड़ा वर्ग किरण बेदी के ख़िलाफ़ खड़ा है. लेकिन, किरण बेदी का मानना है कि जब तक नियमों का सख्ती से पालन नहीं होगा, तब तक देश में अनुशासन नहीं आएगा. इसकी झलक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखा दी. उन्होंने लोगों से कहा, आप चुप रहिए, अगर आपको सुनना नहीं, तो आप बाहर चले जाएं. अन्ना आंदोलन में भी किरण बेदी कार्यकर्ताओं को सीधे बैठकर सुनना, इधर-उधर न देखना जैसी साधारण सीखें देती रहती थीं, लेकिन कभी भी वह अन्ना आंदोलन में सैद्धांतिक चेहरा बनकर नहीं उभरीं. आज भी किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद किसी मुद्दे को जानती हैं, इसकी झलक उन्होंने लोगों को नहीं दिखाई.

अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत सामूहिक नेतृत्व से की, लेकिन धीरे-धीरे वह एकांगी नेतृत्व की तरफ़ बढ़ने लगे. उनके सारे साथियों को लगने लगा कि अरविंद केजरीवाल उन लोगों से सलाह-मशविरा नहीं करते हैं, जिन्होंने उनके साथ आंदोलन किया या जिन्होंने पार्टी बनाई. और, यह गुस्सा उनके कार्यकर्ताओं में इतना ज़्यादा भर गया कि बहुत सारे लोग इस बार चुनाव में दिल्ली में अरविंद का समर्थन करने नहीं आए. पराकाष्ठा तो तब हुई, जब पार्टी के संस्थापक सदस्य एवं प्रसिद्ध वकील शांति भूषण अरविंद केजरीवाल का विरोध करने में सीमाएं लांघ गए. मैं इसे बिलो-द-बेल्ट हिट कह रहा हूं, क्योंकि शांति भूषण अपनी अनदेखी से इतने नाराज़ थे कि उन्होंने किरण बेदी को अरविंद केजरीवाल से बेहतर बता दिया. उन्होंने अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व के उन सारे हिस्सों को जनविरोधी बताया, जिन्हें लेकर अरविंद दिल्ली में मशहूर हैं. शांति भूषण यहीं तक नहीं रुके. उन्होंने अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र देने और हटाने की सलाह तक पार्टी के लोगों को दे डाली. शांति भूषण प्रसिद्ध वकील हैं और सारी ज़िंदगी उन्होंने सही वक्त का इंतज़ार कर तर्कों को रखा है. इस बार भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल की उच्च-मध्यम वर्ग की कॉन्स्टीटूएंसी को तबाह करने की कोशिश की. मेरा यह मानना है कि जब चुनाव चल रहा हो और आमने-सामने बातें हो रही हों, तो न किरण बेदी का विरोध भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए और न अरविंद केजरीवाल का विरोध आम आदमी पार्टी में होना चाहिए. विरोध अगर होना है, तो इस आधार पर होना चाहिए कि दोनों दिल्ली को बेहतर बनाने की कोई योजना बना पा रहे हैं या नहीं. अगर नहीं बना पा रहे हैं, तो उस नेतृत्व का विरोध उसके कार्यकर्ताओं को अवश्य करना चाहिए. सबसे बड़ा अफ़सोस तो इस बात है कि दिल्ली के इस चुनाव में न किरण बेदी के पास दिल्ली को बेहतर बनाने का कोई खाका है और न अरविंद केजरीवाल के पास.

दिल्ली की समस्याएं वहीं हैं, जो देश की हैं, लेकिन दिल्ली कुछ मायनों में अलग है. दिल्ली में बिजली, पानी, अस्पताल और शिक्षा जैसे मुद्दे तो हैं ही, लेकिन दिल्ली में एक नया मुद्दा है, देश भर के लोगों का रोजी-रोटी के लिए दिल्ली में दस्तक देना, यहां बस जाना और अपनी जीविका के लिए रास्ते तलाशना. लोगों के आने से दिल्ली के ऊपर बोझ बढ़ता है और ज़रूरत इस बात की है कि दिल्ली में ऐसी सरकार आए, जो यह योजना बनाए कि लोग आ रहे हैं, तो आते रहें, लेकिन वे बसें इस तरह, जिससे दिल्ली में कुछ ही जगहों पर नागरिक सुविधाओं का बोझ न बढ़े. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की परिकल्पना इसीलिए की गई थी कि दिल्ली में केंद्रित होते सरकारी दफ्तर, व्यापारिक केंद्र और औद्योगिक घराने, इन सबको योजनापूर्वक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फैलाया जाए, ताकि दिल्ली की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके. इन सवालों के ऊपर दोनों भावी व्यक्तित्वों या भावी मुख्यमंत्रियों का कोई ध्यान नहीं है. इस चुनाव में एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं और वे हमले व्यक्तिगत ज़्यादा हो रहे हैं.

किरण बेदी के स्वभाव और अरविंद केजरीवाल के स्वभाव में काफी समानताएं हैं. किरण बेदी कहती भले हों कि उन्होंने चालीस साल जनता के बीच काम किया, लेकिन हक़ीक़त यह है कि उन्होंने चालीस साल जनता के बीच नहीं, बल्कि जनता से अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले पुलिस विभाग में काम किया है. हिंदुस्तान में पुलिस से जनता डरती है और किरण बेदी भी उसी पुलिस विभाग का एक अंग रही हैं. और, उन्हें कभी भी पुलिस के ऐसे चेहरे के रूप में नहीं जाना गया, जिसे जनता पसंद करती है.

शायद राजनीति उस जगह पहुंच गई है, चाहे देश की हो या दिल्ली की, जहां केवल एक ही सिद्धांत है, जिसके ऊपर आज नेता भरोसा कर रहे हैं और वह है सत्ता. किसी भी तरह सत्ता मिल जाए और उसके बाद अपना वक्त काटें. दिल्ली इस खेल का एक मज़ेदार उदाहरण बनने जा रही है. दिल्ली के ग़रीबों में अरविंद केजरीवाल की साख बनी हुई है. वहीं दिल्ली के मध्यम वर्ग, उच्च-मध्यम वर्ग में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ दिल्ली जीतने की आकांक्षा से उतरी हुई है. दोनों में से कोई भी जीते. अगर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं, तो नरेंद्र मोदी के लिए, बावजूद इसके कि उन्होंने किरण बेदी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया है, सब मानेंगे कि मोदी का विजय रथ रुक गया. लेकिन, अगर किरण बेदी जीत जाती हैं, तो जीत का सारा श्रेय नरेंद्र मोदी के पास जाएगा. दोनों महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व इस चुनाव में एक दूसरे से टकराने से बच रहे हैं, पर जीत की स्थिति में किरण बेदी का स्वभाव, उनके काम करने का तरीका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली के नेताओं के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि वे किरण बेदी के काम करने के तरीके से न परिचित हैं और न सहमत. दूसरी तरफ़ हार की स्थिति में अरविंद केजरीवाल की पार्टी टूट भी सकती है और अव्यवहारिक भी हो सकती है. अरविंद केजरीवाल परंपरागत विरोधी दलों को भी उतना कोस रहे हैं, जितना वह सत्ता पक्ष को कोस रहे हैं. इसलिए उनका साथ दिल्ली के विरोधी पक्ष, जो देश में कहीं न कहीं लोगों के बीच में केंद्र बने हुए हैं, वे उनका समर्थन चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन, एक अच्छी चीज यह है कि वे लोग दिल्ली में उनका विरोध नहीं कर रहे हैं.

इसलिए दिल्ली की लड़ाई देश की राजनीति में किरण बेदी के जीतने और अरविंद केजरीवाल के हारने की स्थिति में पूर्ण विराम नहीं लगाएगी, बल्कि उसके आगे होने वाली घटनाओं का आधार बनेगी. पर इन सबमें दिल्ली की जनता का क्या होगा, पता नहीं. क्योंकि, दिल्ली सिर्फ़ कनॉट प्लेस या सड़कों के किनारे बने हुए शीला दीक्षित के दिए हुए नाम आरडब्ल्यूए के लोगों की नहीं है. वह बड़ी-बड़ी इमारतों के पीछे रहने वाले लोगों के सैलाब की भी दिल्ली है. उनकी ज़िंदगी में कब सवेरा आएगा, इसे देखने के लिए अभी आंखों को और खुला रखना पड़ेगा. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही हो सकता है. अभी तक पार्टी ने हार के कारणों की समीक्षा या अपनी विचारधारा पुनर्परिभाषित करने की कोशिश नहीं की है. वह संतुष्ट और निष्क्रिय हो गई है. राहुल गांधी को छोड़कर पार्टी नेतृत्व बूढ़ा हो चुका है. राहुल गांधी भी आम तौर पर दिखाई नहीं देते और जब दिखाई देते हैं, तो पार्टी के लिए दायित्व बन जाते हैं.

भाग्य की राजनीति

नेपोलियन ने एक बार कहा था कि उसे अपनी सेना में ऐसे सिपहसालारों की ज़रूरत है, जिनकी किस्मत उनके साथ हो. अगर नेपोलियन को नरेंद्र मोदी का साथ मिला होता, तो वह खुश हो जाता. जरा ग़ौर कीजिए, किस्मत ने मोदी का कितना साथ दिया है. महात्मा गांधी आज से सौ साल पहले दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और यह अवसर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को मिलना था कि वह अपनी पुरानी कर्मभूमि अहमदाबाद में पिछले दिनों आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर इसका जश्न मनाएं. वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन भी इसी स्थान पर कुछ दिनों पहले आयोजित हुआ था. अब गांधी पर कांग्रेस का आधिपत्य समाप्त हो गया है. भाजपा ने उन्हें पूरे देश की संपत्ति बना दिया है. चुनाव से पहले भाजपा ने सरदार पटेल पर अपना दावा पेश किया था और अब गांधी के गुजरात कनेक्शन से भरपूर फ़ायदा उठाया है. अतिरिक्त बोनस के रूप में प्रधानमंत्री की खुशकिस्मती थी और कांग्रेस की बदकिस्मती कि मई 2014 चुनाव के मध्य में जवाहर लाल नेहरू की 50वीं पुण्य तिथि आई. अगर चुनाव छह महीने बाद हुए होते, तो कांग्रेस ने इस अवसर को बंपर पब्लिसिटी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया होता.

कांग्रेस दुर्भाग्य से ग्रसित हो गई है. पार्टी ने 2004 में भाग्य के सहारे चुनाव जीता था. यहां तक कि 2009 में उसकी कामयाबी में किस्मत और भाजपा की अंदरूनी कलह का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उसके बाद भाग्य ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया. सोनिया गांधी की सेहत खराब रहने लगी, मनमोहन सिंह की कई बाईपास सर्जरी हुईं. लोकसभा का सदस्य रहते हुए (हालांकि, वह अक्सर सदन में अनुपस्थित रहे) भाग्य ने राहुल गांधी का साथ नहीं दिया. अब कांग्रेस को न केवल आम चुनाव में भारी पराजय का सामना करना पड़ा है, बल्कि पार्टी एक के बाद एक राज्य में चुनाव हारती जा रही है. अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस कभी पुनर्जीवित हो पाएगी? जिन राजनीतिक दलों का सत्ता में आवागमन लगा रहता है, वे हार के झटके से उबर आते हैं. लेकिन, जो दल हमेशा से सत्ता में रहा हो, उसे इस तरह के झटके से उबरने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. यहां ब्रिटेन की लिबरल पार्टी का उदाहरण अनुचित नहीं होगा. जैसा व्हिग पार्टी का दावा है कि उसने देश में 1688 की शानदार क्रांति का नेतृत्व किया था और अलोकप्रिय मोनार्की (राजतंत्र) के विरुद्ध जनाक्रोश को वैधता प्रदान की थी. ब्रिटेन में लिबरल पार्टी और कंजरवेटिव पार्टी 225 वर्षों तक बारी-बारी सत्ता में आती-जाती रहीं. वर्ष 1905 और उसके बाद लगातार दो चुनाव जीतने के बाद लिबरल पार्टी 1922 में विभाजित हो गई और उसे हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद वह पूरी बीसवीं सदी के दौरान कभी भी अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकी.

कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही हो सकता है. अभी तक पार्टी ने हार के कारणों की समीक्षा या अपनी विचारधारा पुनर्परिभाषित करने की कोशिश नहीं की है. वह संतुष्ट और निष्क्रिय हो गई है. राहुल गांधी को छोड़कर पार्टी नेतृत्व बूढ़ा हो चुका है. राहुल गांधी भी आम तौर पर दिखाई नहीं देते और जब दिखाई देते हैं, तो पार्टी के लिए दायित्व बन जाते हैं. पार्टी में नौजवान नेता हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए इस युवा राजकुमार से असहमति जतानी पड़ेगी. पार्टी के पुराने नेताओं ने पराजय के डर से राज्यसभा का रुख कर लिया है. पार्टी नेतृत्व स्वयं के सकारात्मक रुख की बजाय भाजपा की ग़लतियों की वजह से सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है. सदन में कांग्रेस की रणनीति यह जाहिर करती है कि पार्टी ने यूपीए शासनकाल में भाजपा के व्यवहार से सीख हासिल की है. लेकिन, दोनों का अंतर भी जाहिर है. पिछले चुनाव में यूपीए को बहुत ही कम जन समर्थन हासिल था और उसके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था, जो नई पीढ़ी के मतदाताओं को उत्साहित कर सके. भाजपा इस मामले में भाग्यशाली थी. प्रधानमंत्री अभी भी एक आइकॉन बने हुए हैं. उन्हें मालूम है कि सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है. सोशल मीडिया ऐसा क्षेत्र है, जिसमें सोनिया और राहुल दिखाई नहीं देते हैं. जब कोई राजनीतिक दल चुनाव हारता है, तो त्वरित और रेडिकल तरीके से प्रतिक्रिया करता है. मेरी अपनी पार्टी (लेबर पार्टी) को विपक्ष में रहते हुए सत्ता में वापसी के लिए पिछले 18 वर्षों में चार बार अपना नेता बदलना पड़ा और अपनी विचारधारा पुनर्परिभाषित करना पड़ी. टोनी ब्लेयर किस्मत के धनी थे और वह पहले लेबर नेता थे, जिन्होंने तीन चुनाव जीते. कंजरवेटिव पार्टी ने पिछले 13 वर्षों में चार बार अपना नेता बदला और अपनी विचारधारा भी अपडेट की. हारने वाला नेता हर चुनाव के बाद हटा दिया जाता है और जीता हुआ नेता अपनी अगली हार तक नेता बना रहता है.

भारत में कोई पार्टी अपना नेता बदलती हुई दिखाई नहीं देती. भाजपा ने 2009 की हार के बाद अपना नेता नहीं बदला था. वामपंथी दलों का नेतृत्व भी लगभग स्थायी है. दरअसल, कोई भी पराजित दल अपने अंदर बदलाव नहीं लाता. इसका कारण यह है कि किसी भी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है. भारत को अगर लोकतांत्रिक देश बने रहना है, तो उसे अच्छे राजनीतिक दलों की आवश्यकता होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

संभल कर करें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल

मोनीशा भटनागर

बदलते मौसम में सर्दी जुखाम की या वायरल की चपेट में आना आम बात है. लेकिन हमारे देश में लोग मेडिकल स्टोर में जाकर कई तरह की एंटीबायोटिक्स लेकर इन मर्जों से जल्दी निजात पाने की कोशिश करते हैं. हालांकि इससे लोगों को तात्कालिक तौर पर आराम जरूर मिल जाता है लेकिन हर कोई इसके दूरगामी प्रभावों को नज़रअंदाज कर देते हैं. डॉक्टर की सलाह के बगैर किसी भी बीमारी में एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना घातक साबित हो सकता है. या कहें कि अनावश्यक एंटीबायोटिक्स का उपयोग करने से आपके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं. हाल ही में हुए शोध के परिणामों के मुताबिक ऐसा करने से संक्रमण और एलर्जी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. जार्ज वाशिंगटन, कार्नेल और जांस हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा कि लोगों के बीच यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि एंटीबायोटिक्स हर मर्ज का इलाज है. बिना चिकित्सकों की सलाह के इन्हें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योकि एंटीबायोटिक्स वायरस संक्रमण में असर नहीं करती.

शोध के अनुसार अधिकांश मरीजों का मानना था कि एंटीबायोटिक्स लेने से बीमारी पर जल्दी असर होता है और उनकी सेहत पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है. शोध के मुताबिक मरीजों के विश्वास के विपरीत एंटीबायोटिक्स का अत्याधिक और अनावश्यक प्रयोग एलर्जी और संक्रमण का खतरे को बढ़ा देता है. अनुपयुक्त एंटीबायोटिक उपचार और एंटीबायोटिक्स का ज्यादा प्रयोग प्रतिरोधी जीवाणुओं के उभरने का एक मुख्य कारक है. समस्या तब और जटिल हो जाती है, जब व्यक्ति चिकित्सकीय निर्देशों के बिना एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देता है. कृषि में एंटीबायोटिक का गैर चिकित्सकीय उपयोग होता है. एंटीबायोटिक दवाओं में बार–बार ये निर्देश दिये जाते हैं कि कहां इनकी जरूरत नहीं हैं, या उपयोग गलत है या दी गई एंटीबायोटिक मामूली असर वाला है.

आज से तकरीबन 86 साल पहले महान वैज्ञानिक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया को पेनिसिलीन नामक एंटीबायोटिक की खोज का तोहफा देकर चिकित्सीय क्षेत्र में एक चमत्कारी काम किया था. पेनिसिलिन और एंथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स, जो एक समय चमत्कारिक दवा मानी जाती थी, उनके ज्यादा प्रयोग की वजह से 1950 के दशक के बाद लोगों के शरीर में इनके प्रतिरोधक तत्व उभरने शुरू हो गये है. मौजूदा समय में एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल होने लगा है. आम इंफेक्शन से पीड़ित मरीजों के इलाज में इसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि बेहद खतरनाक है.

शोध के अनुसार अधिकांश मरीजों का मानना था कि एंटीबायोटिक्स लेने से बीमारी पर जल्दी असर होता है और उनकी सेहत पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है. शोध के मुताबिक मरीजों के विश्वास के विपरीत एंटीबायोटिक्स का अत्याधिक और अनावश्यक प्रयोग एलर्जी और संक्रमण का खतरे को बढ़ा देता है. अनुपयुक्त एंटीबायोटिक उपचार और एंटीबायोटिक्स का ज्यादा प्रयोग प्रतिरोधी जीवाणुओं के उभरने का एक मुख्य कारक है. समस्या तब और जटिल हो जाती है, जब व्यक्ति चिकित्सकीय निर्देशों के बिना एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देता है. कृषि में एंटीबायोटिक का गैर चिकित्सकीय उपयोग होता है. एंटीबायोटिक दवाओं में बार-बार ये निर्देश दिये जाते हैं कि कहां इनकी जरूरत नहीं हैं, या उपयोग गलत है या दी गई एंटीबायोटिक मामूली असर वाला है.

अनुपयुक्त एंटीबायोटिक उपचार एंटीबायोटिक दुरुपयोग का एक आम रूप है. उदाहरण के तौर पर हम आम सर्दी–जुकाम के लिए वायरल संक्रमण दूर करने वाली एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आम सर्दी–जुकाम पर वह बेअसर होती हैं. एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेकशन पर काबू पाने के लिए ही किया जाता है. आम वायरल समस्याएं जैसे कि नज़ला, जुक़ाम, साधारण दस्त आदि रोगों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. लेकिन स्थिति यह है कि कई बीमारियों में एंटीबायोटिक्स का असर धीरे–धीरे कम होता जा रहा है. पूरी दुनिया में हजारों एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें कई बेअसर होने की कगार पर हैं. दुनिया भर में एंटीबायोटिक प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है. वे खतरनाक जीवाणु जो पहले एंटीबायोटिक दवाओं से खत्म हो जाते थे, वे ही जीवाणु उस दवाई के लिए प्रतिरोधक हो गये हैं. एंटीबायोटिक्स सिर्फ मान्यता प्राप्त डॉक्टरों की सलीह पर ही लेनी चाहिए. भारत के संबंध में डब्ल्यूएचओ के एक अध्ययन के मुताबिक यह बात सामने आयी है कि यहां के आधे से अधिक लोग दवाओं के नकारात्मक पक्ष को दरकिनार करते हैं और बिना डॉक्टरी परामर्श के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं. जो लोग एंटीबायोटिक दवाओं का डोज से अधिक और अनियमित रूप से सेवन कर रहे हैं, उनमें दवा का प्रभाव धीरे–धीरे कम हो रहा है इससे अधिक एंटीबायोटिक लेने से शरीर एंटीबायोटिक का आदी हो जाता है और बड़ी जरूरतों के समय वे बअसर हो जाती है.

भारत जैसे विकासशील देशों में, बदलती जीवन शैली दवाओं के आकस्मिक और लापरवाह उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार है. यहां एंटीबायोटिक दवाओं के प्रसार के पीछे का कारण बढ़ती आय और सामर्थ्य हैं. डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाई की उपलब्धता, स्वतंत्र रूप चिकित्सकों का एंटीबायोटिक दवाओं का निजी हित के कारण लिखना और साफ–सफाई और टीकाकरण की कमी से इन्फेक्शन का बार–बार होना. भारत में बैक्टीरियल डिजीज यानि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां तेजी से बढ़ रही है जिनके रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में एंटीबायोटिक्स का उपयोग इतनी तेजी से बढ़ा है, कि उसके दुष्परिणाम दवाओं की गुणवत्तत्ता पर हावी हो रहें हैं. कई तरह की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि एंटीबायोटिक्स का अनावश्यक उपयोग हो रहा है, बिना विवेक के मरीजों को एंटीबायोटिक्स दवायें दी जा रही हैं इस वजह से मरीज को साइड इफेक्ट्स का सामना तो करना ही पड़ता है साथ ही इन दवाओं के प्रति विषाणुओं में प्रतिरोधक क्षमता (ड्रग रेसिस्टेंस) भी विकसित हो रही है. इन दवाओं के लगातार सेवन से जीवाणु अब इतने ताकतवर हो गये हैं कि उन पर कई एंटीबायोटिक दवाओं का असर होना बंद हो गया है. मामले की गंभीरता को समझते हुए भारत में भी बिना जाने समझे एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को रोकने की कवायद में तेजी लाने की ज़रूरत है.

एंटीबायोटिक अति प्रयोग से प्रभावित होने वाली सबसे आम बीमारियों में से कुछ हैं ,अस्पताल में संक्रमण विशेष रूप से वो जिनसे सेप्सिस का खतरा हो, निमोनिया और यूटीआई (यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन).जरूरत से ज्यादा और अनियमित दवा खाने से ड्रग रेजिस्टेंट का खतरा है, किसी बैक्टीरिया पर बार–बार एंटीबायोटिक का हमला होता है, तो कुछ समय बाद वे इसके आदि हो जाते हैं. फ़िर बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक दवा से नहीं मरते हैं. क्योंकि वे इन दवाओं के प्रतिरोधी बन जाते है. इस स्थिति को ड्रग रेजिस्टेंस कहते है.इसके अलावा इंसानों में डायरिया, कमजोरी, मुंह में संक्रमण, पाचन तंत्र में कमजोरी, योनि में संक्रमण होने की खतरा अधिक हो जाता है. इसके अलावा किडनी में स्टोन होने, खून का थक्का बनने, सुनाई न पड़ने आदि कई गंभीर शिकायतें बढ़ जाती है. इससे कई लोगों को एलर्जी भी हो जाती है. प्रिगनेंट महिला और वे लोग जिन्हें लीवर की बीमारी हो, उन्हें खासकर बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक दवा नहीं लेनी चाहिए.

बिना डॉक्टर के सलाह और अनियमित एंटीबायोटिक के सेवन से शरीर पर इसका प्रभाव कम हो जाता है. दवा का असर न होने पर व्यक्ति जब डॉक्टर के पास इलाज कराने जाता है, तो भी उसे इन दवाओं से आराम नहीं मिलता. डॉक्टर को जब तक मरीज की बीमारी का पता चलता है, तब तक बीमारी बढ़ चुकी होती है, जिसका खामियाजा उसे महंगा इलाज कराकर भुगतना पड़ता है.■

feedback@chauthiduniya.com

महिला जासूस

अमेरिकी सरकार की मदद की थी एलिज़ाबेथ ने

अरुण तिवारी

एलिज़ाबेथ वैन लिउ का जन्म 25 अक्टूबर, 1818 को अमेरिका के वर्जिनिया प्रांत में हुआ था. वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं. अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अपने सामाजिक कार्य के दौरान बनाए गए संबंधों का उन्होंने जासूसी में बखूबी इस्तेमाल किया. उनके पिता का नाम जॉन वैन लिउ और मां का नाम एलिजा बेकर. उनके नाना फिलाडेल्फिया के मेयर थे. एलिजाबेथ के पिता एक बडे व्यवसायी थे और हार्डवेयर के बड़े व्यापारी थे. उनके पिता कई दास भी रखते थे जो हर समय उनकी सेवा में रहते थे.

एलिजाबेथ को उनके परिवार ने उन्हें शिक्षा के लिए क्वेकर स्कूल में भेजा, जहां उनके मन में दासता के ख़िलाफ पनप रहे बीज और ज्यादा अंकुरित हो गए. 1843 में पिता की मौत के बाद एलिजाबेथ और उनके भाई को उनके पूरे व्यवसाय का आधिपत्य मिल गया. अपने भाई की आशंकाओं के विपरीत एलिजाबेथ ने सबसे पहले सभी दासों को मुक्त कर दिया. उनके भाई को इस बात की आशंका थी कि आजाद होने के बाद दास उनके परिवार से बदला ले सकते हैं. लेकिन इसके विपरीत, कई दास उनके घर में कर्मचारी बन गए जिन्हें उनके काम के लिए तनख्वाह दी जाने लगी. एलिजाबेथ ने अपनी पूरी संपत्ति दासों को छुड़ाने में लगा दी. उन्होंने इसके लिए उस एक आंदोलन शुरू किया और कई जगहों से दासों को मुक्त कराया. जब अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत हुई, तब लिउ ने यूनियन की तरफ से काम करना शुरू किया. उस समय यूनियन वहां की सरकार थी. जिन राज्यों ने यूनियन के खिलाफ विद्रोह किया था, उन्हें कॉनफेडरेट के नाम से जाना जाता था. जब गृह–युद्ध के समय कॉनफेडरेट सैनिकों ने यूनियन के सैनिकों को रिचमंड में गिरफ्तार किया तो लिउ ने कॉनफेडेरेट सरकार से इस बात की इजाजत ले ली कि वे यूनियन के कैदियों के लिए खाने और कपडों की व्यवस्था करें.

उन्होंने बहुत सारे यूनियन के कैदियों की फरार होने में भी मदद की. यही नहीं वे इस बात में इन कैदियों की मदद करती थीं कि वे छिपने की ऐसी जगह पर जाएं जहां पर कॉनफेडरेट सैनिकों को भनक भी न लग सके. उन्होंने कई ऐसे लोगों को जेल के स्टाफ में नौकरी पर लगवा दिया था, जो यूनियन सरकार के प्रति सहानुभूति रखते थे. ऐसे लोग जो जेल स्टाफ के रूप में काम करते थे, उन्होनें यूनियन को खुफिया जानकारियों के जरिए काफी लाभ पहुंचाया. एलिजाबेथ के बिना यूनियन के लिए यह संभव नहीं था. एलिजाबेथ अपने कारनामों से यूनियन को सिर्फ इतना ही फायदा नहीं पहुंचा थीं बल्कि वे भागे हुए कैदियों और ऐसे लोगों को भी अपने घर में पनाह देती थीं, जो कॉनफेडरेट सरकार से किसी भी तरह नाराज थे. एलिजाबेथ अपने संबंधों का फायदा उठाकर हर वह प्रयास करती थीं जिसके जरिए कॉनफेडेरेट सरकार को यूनियन सरकार मात दे सके.

एलिजाबेथ उस समय की इकलौती यूनियन जासूस थीं, जिन्होंने खुद के मातहत काम करने के लिए जासूसों की फौज खड़ी कर ली थी, जो उनके इशारे पर काम को अंजाम दिया करते थे. एक प्रकार से वे अमेरिका की यूनियन सरकार के लिए जासूसों के एक पूरे गैंग संचालन कर रही थीं. उन्होंने कॉनफेडरेट को हराने के लिए हर वह प्रयास किया जिससे कि यूनियन सरकार को जीत हासिल हो सके और अमेरिका की अक्षुण्ता बनी रहे. उन्होंने कॉनफेडरेट सरकार के व्हाइट हाउस तक में अपने जासूस लगा रखे थे, जो खुफिया जानकारियां उन तक पहुंचाया करते थे. उनके बारे में कहा जाता है कि यूनियन अधिकारियों तक खुफिया सूचनाएं पहुंचाने के लिए वे खोखले अंडों में और अखबारों के जरिए पहुंचाया करती थीं. वे यूनियन सरकार के लेफ्टिनेंट जनरल यूलिसिस एस ग्रांट को ताजे फूलों के गुलदस्ते के बीच अखबार रखकर भेजा करती थीं. उन अखबारों के पन्नों में वे कॉनफेडरेट सरकार की जानकारियां यूनियन सरकार से साझा किया करती थीं, जिसकी वजह से यूनियन सरकार को पहले ही इस बात की जानकारी मिल जाया करती थीं कि कॉनफेडरेट राज्यों का अगला कदम क्या होने वाला है? यूनियन के कमांडर एलिजाबेथ के द्वारा दी गई सूचनाओं को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे और उसी के आधार पर निर्णय लेते थे. सेना के अधिकारी उन्हें द ग्रेटर पोर्शन ऑफ आवर इंटेलिजेंस की संज्ञा दी थी. एजिलाबेथ ने अपने सारे जासूसों को खतरे में डालकर इस बात की जानकारी यूनियन सरकार को दी थी. कर्नल यूलरिच डाहलग्रेन की मौत के बाद उन्हें पूरे ईसाई संस्कार के हिसाब से दफनाया गया कि नहीं. कर्नल डाहलग्रेन की मौत रिचमंड में यूनियन सैनिकों को जेल से आजाद कराने के दौरान हो गई थी. कॉनफेडरेट सरकार के कब्जे में उनकी लाश थी. एलिजाबेथ ने गृहयुद्ध के दौरान इस बात का ख्याल रखा कि दोनों ही तरफ के आम नागरिकों की मदद की जाए.जब रिचमंड में यूनियन सरकार की जीत हो गई तो एजिलाबेथ ही पहली महिला थीं जिन्होंने वहां यूनियन सरकार का झंडा लहराया था. बाद में उन्हें सरकार ने पूरे रिचमंड का पोस्ट मास्टर नियुक्त किया था. उन्होंने वहां के पोस्टल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए.एलिजाबेथ की मौत सन 1900 में हुई. उन्हें रिचमंड में ही दफनाया गया. अमेरिका के इतिहास में आज भी उन्हें बहुत ही इज्जत की निगाह से देखा जाता है. उन पर बाद में कई फिल्में भी बनाई गईं और कई किताबें भी लिखी गईं.■

feedback@chauthiduniya.com

शार्ली एब्दो हमला

मुश्किल में यूरोप के मुसलमान

शफीक आलम

फ्रांस व्यंग्यात्मक मैगज़ीन शार्ली एब्दो ने वर्ष 2011 में मुसलमानों के पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद का आपत्तिजनक कार्टून प्रकाशित किया था. दरअसल, यूरोप में हज़रत मुहम्मद के कार्टून के प्रकाशन का यह सिलसिला 9/11 के हमले के बाद से ही शुरू हो गया था. अब भी समय-समय पर कई देशों में ऐसे कार्टून प्रकाशित होते रहते हैं. एक अमेरिकी फिल्मकार ने पैग़ंबर पर एक बहुत ही आपत्तिजनक फिल्म बनाकर उसे यू-ट्यूब पर अपलोड किया था. उस फिल्म को लेकर पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन और हिंसात्मक घटनाएं हुई थीं. लीबिया में अमेरिका के राजदूत की हत्या कर दी गई थी. 2011 में प्रकशित कार्टून की वजह से पेरिस स्थित शार्ली एब्दो के दफ्तर पर तीन तथाकथित इस्लामी आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें मैगज़ीन के संपादक समेत 12 लोग मारे गए. उसके बाद उनमें से दो आतंकवादियों ने एक शॉपिंग कांप्लेक्स में लोगों को बंधक बना लिया. हालांकि, पुलिस कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए और चार अन्य लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठे.

बहरहाल, इन हमलों के बाद फ्रांस, यूरोप और दुनिया के दूसरे देशों से कई तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिनमें बहु-संस्कृतिवाद, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपमान करने का अधिकार, अ-प्रवासन और शरणार्थी क़ानूनों पर बहस से लेकर मुसलमानों एवं उनकी मस्जिदों पर हमले तक शामिल हैं. दरअसल, आज दुनिया सिमट कर एक वैश्विक गांव बन गई है. अब दुनिया के किसी खास हिस्से में होने वाली घटना का प्रभाव केवल उसी हिस्से तक सीमित रहे, यह ज़रूरी नहीं है. अगर वह घटना आतंकवाद से जुड़ी हो, तो उस पर पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं आना लाजिमी है, क्योंकि आज दुनिया का शायद ही कोई हिस्सा होगा, जो आतंकवाद से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित न हो. हालांकि, फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने यह कहकर कि इस घटना का इस्लाम से कुछ लेना-देना नहीं है, देश में मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले संभावित हमलों को कम करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान जानते थे कि इसके बावजूद उन पर हमले ज़रूर होंगे. और, वे हमले केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी उनका विस्तार होगा.

मुसलमानों के इस भय की पुष्टि ओलांद के वक्तव्य के तुरंत बाद फ्रांस की दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल फ्रंट की अध्यक्ष मरीन ली पेन के बयान से हो गई. ली पेन ने अपने एक इंटरव्यू में मुसलमानों से यह मांग की कि वे साबित करें कि इस्लाम पश्चिमी मूल्यों के अनुकूल है और मुसलमान यूरोप के धर्मनिरपेक्ष समाज में रह सकते हैं. फ्रांस में पहले से ही सार्वजानिक स्थानों पर हिजाब पहनने पर पाबंदी, हलाल गोश्त और स्कूलों की कैंटीन में सूअर का मांस अनिवार्य बनाने जैसे मुद्दों पर बहस हो रही थी. अभी हाल में ही प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक मीशेल वेलबेक ने अपने नए विवादास्पद उपन्यास-सबमिशन का ताना-बाना इस विषय पर तैयार किया है कि वर्ष 2022 तक फ्रांस में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी. लिहाज़ा, यह मान लेना कि यूरोप में मुसलमानों के प्रति बढ़ती नफरत (इस्लामोफोबिया) की भावना शार्ली एब्दो हमले का नतीजा है, भ्रामक हो सकती है. अलबत्ता ऐसा ज़रूर है कि इस घटना ने इसमें तेज़ी और कटुता पैदा कर दी है. खुद मुसलमान भी पहले वाली आक्रामकता छोड़कर रक्षात्मक मुद्रा में आ गए हैं. कई जगहों पर मुसलमानों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किए हैं.

जर्मनी, जहां प्रवासन विरोधी पार्टी आल्टरनेटिव फॉर डाउशलैंड (पेजिडा मूवमेंट) पहले से ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ मोर्चा खोले हुए है, इस घटना के बाद उसकी लोकप्रियता में छह प्रतिशत का इजाफा हुआ है. और, ऐसी संस्थाओं और पार्टियों की लोकप्रियता में पूरे यूरोप में बढ़ रही है. हॉलैंड के राजनेता गीर्ट विल्डर्स, जिन पर नस्लीय हिंसा भड़काने के आरोप में मुक़दमा चल रहा है, ने एक बार फिर से यूरोप को इस्लाम मुक्त करने की बात कही है. हालांकि, स्विट्जरलैंड में पहले भी इस्लाम विरोधी प्रदर्शन और मस्जिदों पर हमले हुए हैं, लेकिन फिर भी इसे यूरोप का सबसे सहनशील देश माना जाता है. यहां भी जर्मनी के मुस्लिम विरोधी पेजिडा मूवमेंट की शाखा खुल गई है, जिसके तत्वावधान में इस देश में प्रदर्शन करने की योजना है. उसी तरह ब्रिटेन, स्वीडन, इटली जैसे देशों की अति-दक्षिणपंथी पार्टियां इस घटना का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश कर रही हैं. अमेरिकन न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज ने यह ख़बर प्रसारित की कि पेरिस में एक ऐसा क्षेत्र भी है, जहां कोई नहीं जा सकता और यह कि यहां पर शरिया क़ानून लागू है. हालांकि, पेरिस के मेयर ने अमेरिकी अदालत में इस न्यूज चैनल के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करने की बात कही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस घटना के बाद पश्चिम में दक्षिणपंथी ताक़तें मज़बूत हुई हैं.

सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग साइट्स और बड़े अख़बारों के कमेंट सेक्शन में इस्लाम विरोधी कंटेंट की भरमार नज़र आती है. मिसाल के तौर पर, ब्लॉगिंग साइट स्टोरीफाई ने कुछ ऐसे ट्वीटर संदेश एकत्र करके प्रकाशित किए हैं, जो शार्ली एब्दो पर आतंकवादी हमले के बाद पश्चिमी देशों में इस्लामोफोबिया की नई लहर के नतीजे में सामने आए हैं. इन संदेशों में यह कहा गया है कि सभी पश्चिमी देश से मुसलमानों को बाहर कर देना चाहिए या उन्हें जेल भेज देना चाहिए. ट्वीटर और फेसबुक पर किल ऑल मुस्लिम्स जैसे हैश-टैग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. यही नहीं, हॉलैंड के शहर रॉटरडैम के मेयर एवं मोरक्कों में जन्मे लेबर पार्टी के मुस्लिम नेता अहमद अबू तालिब ने एक टेलीविजन टॉक शो में कुछ इसी तरह की बात कही. उन्होंने कहा कि जिन मुसलमानों को पश्चिमी सभ्यता-संस्कृति पर आपत्ति है, वे अपना बोरिया-बिस्तर समेट कर कहीं और दफा हो जाएं. अबु तालिब ने कहा कि जो मुसलमान हॉलैंड में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं, वही ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिसके चलते अन्य मुसलमानों को भी निर्वासन और बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है.

इस घटना को लेकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसात्मक कार्रवाई भी हुई है. फ्रांस में इस हमले के बाद से अब तक ऐसी 166 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें बुर्का ओढ़ने वाली महिलाओं पर हमले, मस्जिदों के आसपास सूअर का मांस फेंकना और धमकी भरे ई-मेल भेजना आदि शामिल हैं. कुल मिलाकर इस घटना ने यूरोप में मुस्लिम विरोधी ध्रुवीकरण को और मजबूती प्रदान की है. साथ ही यह सवाल भी पैदा किया है कि क्या इस्लाम आधुनिक विचारों के अनुकूल खुद को ढाल सकता है? क्योंकि, इराक में आईएसआईएस द्वारा पश्चिमी देशों के नागरिकों के सिर कलम करने की घटनाएं हों या अलकायदा आतंकवादियों द्वारा बम धमाके हों या बोको हराम की नाइजीरिया में चल रही कार्रवाई, इन सबने इस्लाम को अपने घेरे में ले लिया है, क्योंकि उक्त आतंकवादी संगठन इस्लाम के नाम पर धर्म युद्ध या जिहाद करने का दावा कर रहे हैं.

जहां तक अभिव्यक्ति की आज़ादी और अपमान करने के अधिकार का सवाल है, तो इस पर राजनीतिक और सामाजिक समीक्षक दो खेमों में बंटे दिखाई दे रहे हैं. एक पक्ष का मानना है कि ये ऐसे मूल्य हैं, जिनकी सुरक्षा हर क़ीमत पर की जानी चाहिए, वहीं दूसरा पक्ष यह मानता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और अपमान करने के अधिकार की एक सीमा होनी चाहिए तथा इस्लाम के विरुद्ध एक विशेष धारणा (स्टीरियोटाइप) रखने पर पुनर्विचार करना चाहिए. बहरहाल, यूरोप के तक़रीबन सभी देशों में जहां मुसलमानों की एक अच्छी-खासी आबादी है, वहां की दक्षिणपंथी पार्टियों और संगठनों ने इस घटना का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश की है. उनके निशाने पर बहु-संस्कृतिवाद और मुसलमान ही हैं.

अब शार्ली एब्दो पर हमले की बात करें, तो आतंकवादियों का दावा था कि वे इस्लाम के पैग़ंबर का सम्मान लौटने के लिए हमलावर हुए थे. लेकिन, हमले के बाद न केवल शार्ली एब्दो ने पैग़ंबर के कार्टून पुन: प्रकाशित किए, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी कई अख़बारों ने उन्हें प्रकाशित किया और टीवी चैनलों ने अपनी ख़बरों में दिखाया. यही नहीं, मुसलमान यूरोप के देशों में दूसरे समूहों की हिंसा के शिकार बन रहे हैं. जाहिर है, शार्ली एब्दो जैसे हमले किसी भी तरह से मुसलमानों के हक़ में नहीं हो सकते. लिहाज़ा अब न केवल यूरोप और पश्चिमी देशों, बल्कि दुनिया के हर देश के मुसलमानों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे इस पहलू पर संजीदगी से ग़ौर करें, अन्यथा वह दिन दूर नहीं, जबकि उन्हें पूरी दुनिया में अलग-थलग हो जाने पर मजबूर होना पड़ेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

सऊदी के शाह अब्दुल्लाह का निधन

सऊदी अरब के बादशाह अब्दुल्लाह बिन अबदुल अजीज का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया. शाह अब्दुल्लाह कई हफ़्तों से फेफड़े के संक्रमण से पीड़ित थे. विश्व के प्रमुख नेताओं ने उनकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि दी है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर संदेश में लिखा कि, शाह अब्दुलाह के रूप में हमने एक महत्वपूर्ण आवाज़ खो दी है. अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, वे मध्य-पूर्व एवं अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा और स्थिरता के लिए अमरीका-सऊदी संबंधों के महत्व को लेकर प्रतिबद्ध थे. शाह अब्दुल्लाह के शासन काल में सऊदी अरब और अमरीका के बीच अच्छे संबंध बने रहे. देश के रक्षा मंत्री और शाह अब्दुल्लाह के 79 वर्षीय सौतेले भाई सलमान इब्न अब्दुल अज़ीज़ सऊदी अरब के नए बादशाह होंगे.

बेगानी शादी जैकब ज़ूमा दीवाना

दक्षिण अफ़्रीका के एक भारतीय मूल के व्यापारी के बेटी की शादी में देश के वायु सेना बेस पर बारातियों के जेट विमान को उतारने की इजाज़त देना राष्ट्रपति जैकब ज़ूमा के लिए मुसीबत बन गया है. इसके लिए वायु सेना के जिन दो अफ़सरों को कसूरवार ठहराया गया था, वे अब राष्ट्रपति जैकब ज़ूमा को सिविल कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं. हालांकि राष्ट्रपति ज़ूमा इससे इनकार करते रहे हैं, लेकिन पहले भी उन पर भारतीय मूल के कारोबारी गुप्ता परिवार के असर में काम करने के आरोप लगते रहे हैं.

यमन के राष्ट्रपति का इस्तीफ़ा

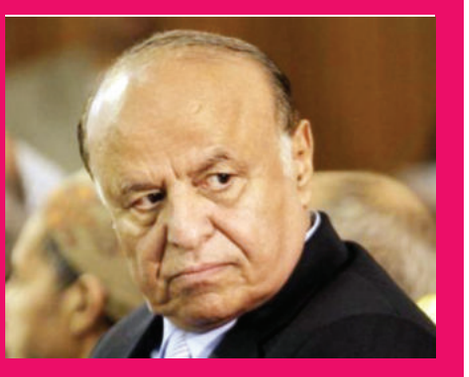

यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के प्रदर्शन के चलते यमन के राष्ट्रपति अब्दराब्बुह मंसूर हादी ने देश के प्रधानमंत्री खालिद बहाह के साथ अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. राष्ट्रपति ने कहा कि हूती विद्रोहियों के शांति समझौते का सम्मान नहीं किया और ऐसी स्थिति में वो अपने पद पर नहीं बने रह सकते. उनके इस्तीफे के बाद उनके मज़बूत गढ़ समझे जाने वाले बंदरगाह शहर अदन में कई धमाके हुए हैं. राष्ट्रपति के इस्तीफे के मांग करने वाले हूती विद्रोहियों ने उन के इस्तीफ़े का स्वागत किया है और सत्ता संचालन के लिए एक परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा है. ख़बरों के मुताबिक विद्रोहियों ने सना में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास पर हमला करके अपने कब्जे में ले लिया था. अरब प्रायद्वीप के इस दक्षिणी देश में अल-क़ायदा चरमपंथी सक्रिय हैं. इसलिए इस घटना क्रम पर अमेरिका ने अपनी चिंता ज़ाहिर की है.

आईएसआईएस पर लंदन में बैठक

आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के खतरे से से निपटने के लिए लंदन में 21 देशों के नेताओं की बैठक होने वाली है. ये वो देश हैं जो अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा हैं. ब्रिटेन के विदेश मंत्री फ़िलिप हैमंड और अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी इस बैठक की संयुक्त रूप से मेज़बानी करेंगे. आईएसआईएस ने सीरिया और इराक़ के कई इलाक़ों पर क़ब्ज़ा जमा रखा है. इन देशों में ख़िलाफ़त की स्थापना कर इस्लामी शरियत क़ानून लागू करने बात कर रहे हैं और नए इलाक़ों पर भी तेज़ी से क़ब्ज़ा करते जा रहे हैं. एक दिन चलने वाले इस सम्मेलन में आईएसआईएस को मिलने वाले पैसों और नए लड़ाकों की भर्ती को रोकने के उपायों पर चर्चा की जाएगी. आईएसआईएस के ख़िलाफ़ लड़ रहे लोगों को और ज़्यादा सैन्य मदद और मानवीय मदद देने पर भी बातचीत होगी. इसके साथ ही लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की रणनीति भी तय की जाएगी.

एक बार श्रीमती तर्खड शिरडी आईं. दोपहर का भोजन प्राय: तैयार हो चुका था और थालियां परोसी ही जा रही थीं कि उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा. श्रीमती तर्खड तुरंत उठीं और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया. कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया. संध्या के समय जब श्रीमती तर्खड मस्जिद में जाकर बैठीं, तो बाबा ने उनसे कहा–मां, आज तुमने बड़े प्रेम से मुझे खिलाया, मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली. सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य मिलेगा. इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा.

समस्त प्राणियों में ईश्वर के दर्शन करो

चौथी दुनिया ब्यूरो

उपनिषदों एवं गीता का यही उपदेश है कि ईशावास्यमिदं सर्वम् यानी सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो. समस्त प्राणियों में ईश्वर के दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है.

एक बार श्रीमती तर्खड ने तीन वस्तुएं, यानी भरित (भुर्ता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैगन और दही), काचर्या (बैगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए) और पेड़ा (मिठाई) बाबा के लिए भेजीं. बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया, इसे देखना बहुत ही दिलचस्प होगा. बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे. एक बार वह शिरडी जा रहे थे. श्रीमती तर्खड ने श्रीमती पुरंदरे को दो बैगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वह एक बैगन का भर्ता और दूसरे का काचर्या बनाकर बाबा को भेंट कर दें. शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद गईं. बाबा उसी समय भोजन के लिए बैठे ही थे. उन्हें भुर्ता बहुत स्वादिष्ट प्रतीत हुआ, इसलिए उन्होंने उसे थोड़ा–थोड़ा सभी को वितरित भी किया. इसके पश्चात राधाकृष्ण माई के पास संदेश भेजा गया कि बाबा काचर्या मांग रहे हैं. वह असमंजस में पड़ गईं कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बैगन की तो अभी ऋतु नहीं है. अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो. जब इस बात का पता लगाया गया कि भुर्ता लाया कौन था, तब ज्ञात हुआ कि बैगन श्रीमती पुरंदरे लाई थीं और फिर उन्हें ही काचर्या बनाने का कार्य सौंपा गया. अब हर आदमी को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया और सबको बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ.

बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे. एक बार वह शिरडी जा रहे थे. श्रीमती तर्खड ने श्रीमती पुरंदरे को दो बैगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वह एक बैगन का भर्ता और दूसरे का काचर्या बनाकर बाबा को भेंट कर दें. शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद गईं. बाबा उसी समय भोजन के लिए बैठे ही थे. उन्हें भुर्ता बहुत स्वादिष्ट प्रतीत हुआ, इसलिए उन्होंने उसे थोड़ा–थोड़ा सभी को वितरित भी किया.

दिसंबर, 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे. प्रस्थान करने से पूर्व वह श्रीमती तर्खड से मिलने आए. श्रीमती तर्खड बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थीं. उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहीं मिला और वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था. फिर भी अति प्रेम के कारण उन्होंने वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया. उन्हें पूरा विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे. शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, लेकिन वहां पेड़ा ले जाना भूल गए. बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, लेकिन जब गोविंद पुन: संध्या समय बिना पेड़ा लिए वहां पहुंचे, तो फिर बाबा शांत न रह सके और उन्होंने पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उत्तर मिला, कुछ नहीं. बाबा ने पुन: प्रश्न किया और गोविंद ने फिर वही उत्तर दोहरा दिया. अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें मां (श्रीमती तर्खड) ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब गोविंद को स्मृति हो आई. वह बहुत लज्जित हुए और बाबा से क्षमायाचना करने लगे. दौड़कर गए और उन्होंने फिर पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया. बाबा ने तुरंत पेड़ा खा लिया. इस प्रकार श्रीमती तर्खड की भेंट बाबा ने स्वीकार की और कहा कि भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूं, यह भगवद् वचन भी सत्य साबित हुआ.

एक बार श्रीमती तर्खड शिरडी आईं. दोपहर का भोजन प्राय: तैयार हो चुका था और थालियां परोसी ही जा रही थीं कि उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा. श्रीमती तर्खड तुरंत उठीं और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया. कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया. संध्या के समय जब श्रीमती तर्खड मस्जिद में जाकर बैठीं, तो बाबा ने उनसे कहा–मां, आज तुमने बड़े प्रेम से मुझे खिलाया, मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली. सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य मिलेगा. इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा. सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो. पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन करो. इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो. बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में न आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूं, मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूं और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूं. बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं. भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था. इसी प्रकार अन्य प्राणी (बिल्लियां, सुअर, मक्खियां, गाय आदि) भी मेरे ही स्वरूप हैं. मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूं. जो इन सब प्राणियों में मेरे दर्शन करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है. इसलिए भेद–भाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो. यह अमृत समान उपदेश ग्रहण कर वह द्रवित हो गईं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, गला रुंध गया और उनके हर्ष का पारावार न रहा.■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

मेगा माइनिंग घोटाला

कवर स्टोरी–उड़ीसा में जिंदल का मेगा माइनिंग घोटाला(19 जनवरी–25 जनवरी 2015) पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक है. बिभूति पति के आलेख से जिंदल ग्रुप के एक और घोटाला की सच्चाई सबके सामने आई है. जिंदल ग्रुप पहले कोयला घोटाला में शामिल रहा है और इस आलेख से पता चलता है कि जिंदल ग्रुप अभी भी नियमों के अनदेखी कर खनन कर रहा है. जिंदल ग्रुप के मालिक नवीन जिंदल कांग्रेस के नेता हैं, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में हार गए. जिंदल ग्रुप यूपीए सरकार के दौरान भी माइनिंग घोटाले में शामिल था. इसलिए सरकार को चाहिए कि इस घोटाले खिलाफ जांच कराए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे.

– रविशंकर यादव,

युवराज को टीम में शामिल करें

भारत का धुरंधर बल्लेबाज, जिसने कई करिश्माई पारी खेलकर टीम इंडिया को कई कप दिलाएं. जिसने इग्लैंड के ब्रांड के एक ओवर में 6 छक्के लगाकर विश्व क्रिकेट में धमाल मचाया था. उस एतिहासिक पारी को चयनकर्ताओं ने भूला दिया. जिस युवराज सिंह को देखकर विश्व के नामी तेज गेदबांजों का लाइन एंड लेंथ बिगड़ जाती था, उसे 2015 विश्वकप के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया. चयन समिति के इस रवैये से क्रिकेट प्रेमियों में नाराजगी और निराशा है. आशा है टीम में उसे स्थान देने का प्रयास होगा. अत: युवराज को टीम में लिया जाए ताकि युवा क्रिकेटरों का हौसला बुलंद हो जाए.

–विनोद कुमार तिवारी, फारबिसगंज, बिहार.

चुनावी जंग

मामा कहकर छू रहे,चरण आज दिन रात.
देंगे फिर दर्शन हमें, पांच साल के बाद.

गिरे हुओं का साथ ले, बनती जब सरकार.
गिरती है हर बार वह, ज्यों कच्ची दीवार.

मुस्लिम हों या हों दलित, करते इस्तेमाल.
सारे दल हर बार क्यों इन्हें समझते सामान.

चीलों के हों घोसले, या कि सियासतदान.
इधर न होता मांस ज्यों, उधर नहीं ईमान.

जनता है आकाश की, उड़ती हुई पतंग.
चरखी इसके हाथ है, डोर दूसरे संग.

कभी सियासत में बने, ऐसे भी संजोग.
हंसों को दाना नहीं, काग उड़ाते भोग.

असमंजस में भाजपा, दें अब किसे महत्व.
मोदी का हिंदुत्व या साक्षी का हिंदुत्व.

बैसाखी ले संघ की, चलते वे हर बार.
अपने दम पर भी कभी, चलो कदम दो–चार.

बेदी और अमेरिका, दोनों एक समान.
कल जवाब थे मांगते, अब देते सम्मान.

करना चाहो कुछ अगर, राजनीति में अर्न.
तो फिर यारों सीख लो, नित लेना यू टर्न.

गांधी नाम पतंग है, राजनीति है डोर.
खींच रहा हर इक जिसे, अपनी–अपनी ओर.

कृष्णा, बिन्नी, शाजिया, जान गए यह इल्म.
बीजेपी के नाम बिन, नहीं चलेगी फिल्म.

कूदे हैं कुछ मंच पर, लेकर पैराशूट.
महफिल में वो छा गए, हुए पुराने हूट.

ओम वर्मा, देवास, मध्य प्रदेश.
– ई–मेल के द्वारा.

अमेरिकी पैसे का दुरूपयोग

गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आगमन पर आतंकवादियो के संभावित आक्रमणों से सुरक्षा के लिए दोनों देश अत्यधिक चिंतित व सचेत हो गये, ऐसा होना भी चाहिए. अमेरिका को आज जब पाकिस्तान के आतंकवादियो से इस खतरे का आभास हुआ तो अमेरिका सतर्क हो गया है. वर्षों से अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत आदि दक्षिण एशिया के देशों को पाकिस्तान के ही आतंकवादियो ने खूनी खेल का खुला मैदान बना रखा है, लेकिन अमेरिका को वहां के निर्दोष व मासूमों की पीड़ा का अमेरिका को कभी कोई अहसास ही नहीं हुआ. इस आतंकवाद से सबसे अधिक हमारा देश भारत ही पीड़ित है, लेकिन हम यह भी नहीं भूले हैं कि अमेरिका दशकों से पाकिस्तान की आवश्यकता से अधिक सहायता करके हमारे शत्रु देश को शक्तिशाली बनाता आ रहा है. उस अमेरिकी डालरों का भरपूर दुरूपयोग करके आतंकवादी संगठन जेहाद की नर्सरी मदरसो व फैक्ट्री प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण कर उनमें खौफनाक आतंकियो को तैयार कर रहे हैं. इन्हीं आतंकवादियो ने पूरे क्षेत्र में दहशतगर्दी फैला रखी है. इस प्रकार निसंदेह सदियों पुरानी कहावत सांप को जितना दूध पिलाओगे वह उतना ही जहर उगलेगा चरितार्थ हो रही है.

–विनोद कुमार सर्वोदय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश. ई–मेल के द्वारा

जनता की आवाज

चौथी दुनिया समाचार पत्र मैं कई वर्षों से पढ़ता आ रहा हूं और यह समाचार पत्र पढ़कर बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो किसी भी समाचार पत्र में नहीं होती है. मैंने 19 जनवरी–25 जनवरी 2015 का अंक पढ़ा. इस अंक में प्रकाशित सभी आलेख प्रभावित करने वाले हैं. कवर स्टोरी–उड़ीसा में जिंदल का मेगा माइनिंग घोटाला और हरदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक आवंटन के खिलाफ ग्राम सभाओं ने पारित किया प्रस्ताव. दोनों स्टोरी तथ्यपरक हैं. यह दोनों खबरें किसी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं हुई. इसी अंक में प्रकाशित आलेख विलय के चक्कर में कहीं गिर न जाए मांझी सरकार, विधान परिषद चुनाव: सपा ने जारी कर दी गलत लिस्ट, चेहरा देखकर बंटे टिकट, कर्मठ हाशिए पर और सम्पादकीय पेज पर प्रकाशित सभी आलेख छोटे उद्यमियों पर ध्यान देने की जरूरत है, एक बूढ़े आदमी की वह यूवा क्रांति, उनके समर्पित शिष्यों ने उनका साथ छोड़ दिया एवं सम्पादकीय असहमति की जगह बचनी चाहिए. चौथी दुनिया समाचार पत्र की सभी खबरें तथ्यों पर आधारित और समाज से जुड़ी हुई होती हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र जनता की आवाज है.■

–प्रीति सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

कहानी

वर्तमान को सर्वश्रेष्ठ बनाएं

भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे. उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए. क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करनेवाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा.सभा में सभी शान्ति से बुद्ध की वाणी सून रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अतिक्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थीं. वह कुछ देर ये सब सुनता रहा फिर अचानक ही आग–बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो. बड़ी–बड़ी बाते करना यही तुम्हारा काम है. तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखतीं ऐसे कई कटु वचनों सुनकर भी बुद्ध शांत रहे. अपनी बातों से न तो वह दुखी हुए, न ही कोई प्रतिक्रिया दी.यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया. अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा, लेकिन वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे .व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पुछा और ढूंढते–ढूंढते वहां पहुंच गया. उन्हें देखते ही वह उनके चरणो में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु!

बुद्ध ने पूछा: कौन हो भाई? तुम्हे क्या हुआ है? क्यों क्षमा मांग रहे हो?

उसने कहा: क्या आप भूल गए. मै वही हूं जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था. मै शर्मिन्दा हूं. मैं क्षमायाचना करने आया हूं.

भगवान बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आया गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो. तुम्हे अपनी गलती का आभास हो गया, तुम निर्मल हो चुके हो. अब तुम आज में प्रवेश करो. बुरी बाते याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते है. बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो.

उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया. उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्यागकर तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया. बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा. उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी.

शिक्षा: हमें, गलती का अहसास होने के बाद, एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

कहीं से आरोपित नहीं है कि वह अन्य भाषा की उपज है. वह हिंदी साहित्य में पूरी तरह से रच–बस चुकी है. यह हाल में प्रकाशित अशोक आलोक के ग़ज़ल संग्रह ज़मीं से आसमां तक की ग़ज़लों से पता चलता है. संग्रह में नब्बे ग़ज़लें हैं, जो सीधे–सीधे यथार्थ और समकालीन पृष्ठभूमि पर जाकर खड़ी होती हैं. अशोक आलोक एक सधे हुए ग़ज़लकार हैं, इसलिए उनकी ग़ज़लों में कथ्य और सौंदर्य का मिला–जुला भाव मिलता है. उनकी ग़ज़लें समकालीनता की शर्तें पूरी करती हैं और उन्हें हम मुक्त कंठ से समकालीन ग़ज़लें कह सकते हैं. अच्छी ग़ज़ल कहने के लिए जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए, वह अशोक आलोक के पास है.

किताब के बहाने उठते सवाल

अनंत विजय

स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो की सोनिया गांधी की फिक्शनलाइज्ड जीवनी कई सालों के अघोषित प्रतिबंध के बाद अब प्रकाशित हुई है. द रेड साड़ी नामक इस किताब के प्रकाशन को लेकर कांग्रेस ने खूब हो–हल्ला मचाया था. लेखक जेवियर मोरो को क़ानूनी धमकियां दी गई थीं. कांग्रेस उस वक्त सत्ता में थी, लिहाजा सोनिया गांधी की इस किताब को हमारे यहां प्रकाशित नहीं होने दिया गया. लगभग चार साल बाद अब स्थितियां बदल गई हैं. कांग्रेस सत्ता से बाहर है और जेवियर मोरो की किताब द रेड साड़ी को लेकर बवाल मचाने वाले कांग्रेस के नेता भी कमजोर हुए हैं. सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस के नेता क्यों विरोध कर रहे थे. सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हो–हल्ला मचाने वाली ब्रिगेड उस वक्त कहां थी? तमिल लेखक मुरुगन की किताब का विरोध करने और वेंडी डोनिगर की किताब को उसके प्रकाशक द्वारा वापस लेने का फ़ैसला करने पर छाती कूटने वाले लोग उस वक्त कहां थे, जब जेवियर मोरो की किताब को डरा– धमका कर प्रकाशित होने से रोका गया था?

सत्ता की हनक में तब भी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी लगी थी, लेकिन विरोध का स्वर उतना तीव्र नहीं था, जितनी अपेक्षा की जाती है. अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्षपातपूर्ण विरोध की यह घटना मिसाल है. अभी हाल में लेखक जेवियर मोरो ने माना है कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी किताब के ख़िलाफ़ एक अभियान चलाकर उसका प्रकाशन रोका था. उनके मुताबिक, उस वक्त तो वह छह महीने तक अपना ईमेल अकाउंट खोलने से भी घबराते थे कि कहीं कोई क़ानूनी नोटिस तो नहीं आ रहा है. 2010 में जेवियर मोरो इसे अंग्रेजी में प्रकाशित कर भारतीय बाजार के अलावा अन्य यूरोपीय देशों और अमेरिका के बाज़ार में सोनिया गांधी के नाम को भुनाना चाहते थे. जेवियर मोरो की यह किताब अक्टूबर 2008 में स्पेनिश में छपी और बाद में इसका अनुवाद इटैलियन, फ्रैंच एवं डच में किया गया. भारत में उठे विवाद के पहले के अनुमान के मुताबिक, इसकी तीन लाख प्रतियां बिक चुकी थीं.

दरअसल, स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो की यह किताब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जीवन पर आधारित है. लेखक मोरो का दावा है कि यह पूरी किताब सोनिया के बचपन से लेकर उनकी राजीव गांधी से मुलाकात और शादी से लेकर सास इंदिरा गांधी के साथ बिताए दिनों के अलावा राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया की मानसिकता का चित्रण करती है. मोरो की इस किताब से इस बात के संकेत मिलते हैं कि सोनिया गांधी अपने पति की हत्या के बाद भारत छोड़कर इटली जाना चाहती थीं. मोरो की किताब में इस तरह के संकेत हैं कि सोनिया गांधी के दिमाग में यह बात आई थी कि उस देश में क्यों रहना, जो अपने ही बच्चों को खा जाता है. किताब में इस बात की ओर भी पर्याप्त इशारा किया गया है कि राजीव की मौत के बाद गांधी परिवार में इटली वापस लौट जाने पर चर्चा होती थी. हालांकि, कई प्रसंगों में साफ़ है कि लेखक ने सोनिया गांधी की ज़िंदगी के यथार्थवादी पहलुओं में अपनी कल्पना का तड़का लगाया है. जैसे एक जगह इस बात का जिक्र है कि रात के तीन बजे सोनिया ने राजीव से कहा कि देश में इमरजेंसी लगाने के ड्राफ्ट में उन्होंने इंदिरा गांधी की मदद की थी.

मोरो लिखते हैं, सोनिया के पैदा होने पर लुजियाना के घरों में परंपरा के अनुसार गुलाबी रिबन बांधे गए. चर्च ने सोनिया को नाम दिया, एडविजे एनटोनियो अलबिना मैनो. लेकिन, उनके पिता स्टीफैनो ने उन्हें सोनिया नाम दिया. रूसी नाम रखकर वह उन रूसी परिवारों का शुक्रिया अदा करना चाहते थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी जान बचाई थी. सोनिया के पिता स्टीफैनो, मुसोलिनी की सेना में थे, जो रूसी सेना से पराजित हो गई थी. सोनिया जियोवेनो के कॉन्वेंट स्कूल में गईं, लेकिन उन्होंने उतनी ही पढ़ाई की, जितनी ज़रूरत थी. यानी वह अच्छी विद्यार्थी नहीं थीं, लेकिन पढ़ाई में कमजोर होने के बावजूद हंसमुख थीं और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थीं. कफ और अस्थमा की शिकायत की वजह से वह बोर्डिंग स्कूल में अकेले सोती थीं. आगे जाकर तूरीन में पढ़ाई के दौरान सोनिया के मन में एयर होस्टेस बनने का अरमान भी जागा था, लेकिन वह सपना जल्द ही बदल गया. उसके बाद सोनिया विदेशी भाषा की शिक्षक या फिर संयुक्त राष्ट्र में अनुवादक बनने की ख्वाहिश पालने लगीं.

लेखक जेवियर मोरो का दावा है कि उनकी किताब लंबे समय तक किए गए शोध पर आधारित है. मोरो का दावा है कि तथ्यों और घटनाओं की सत्यता परखने के लिए उन्होंने सोनिया के होम टाउन लुजियाना में काफी वक्त बिताया. उनका तो यह भी दावा है कि उन्होंने किताब छपने के पहले उसकी पांडुलिपि सोनिया गांधी की बहन नाडिया को भी दिखाई थी, क्योंकि वह स्पेनिश जानती थीं. कांग्रेस नेताओं की आपत्तियों और क़ानूनी नोटिस के हो–हल्ले के बीच जेवियर मोरो की किताब सोनिया एवं उनके इर्द–गिर्द के विवादों और

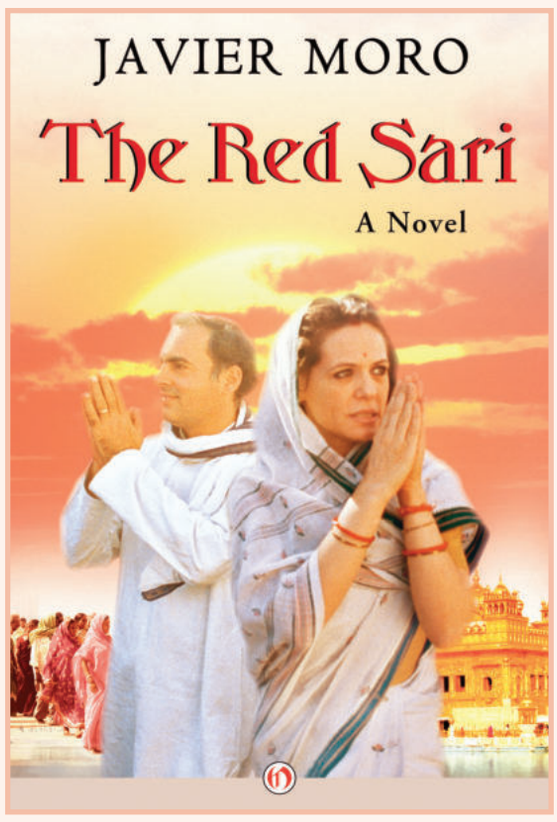

घटनाओं में सिमट कर रह गई. जबकि इस किताब में वर्तमान केंद्र सरकार में मंत्री और सोनिया की देवरानी मेनका गांधी के बारे में ज़्यादा विस्फोटक प्रसंग छपे हैं, जो घटनाओं के चश्मदीदों के बयानों पर आधारित होने की वजह से ज़्यादा प्रामाणिक प्रतीत होते हैं. 23 सितंबर, 1974 को इंदिरा गांधी के पारिवारिक मित्र मोहम्मद यूनुस के घर पर संजय और मेनका परिणय सूत्र में बंध गए. यहां पर जेवियर मोरो ने इस बात के संकेत दिए हैं कि मेनका को गांधी परिवार में एडजस्ट करने में सोनिया से ज़्यादा दिक्कत हुई.

एक और बेहद ही दिलचस्प वाकया इस किताब में है. एक बार मशहूर लेखक खुशवंत सिंह जब गांधी परिवार से मिलने उनके घर गए, तो वहां कुत्तों के बीच जबरदस्त झगड़ा चल रहा था. किताब के मुताबिक, मेनका के आइरिश वुल्फहाउंड और सोनिया के शांत से अफगानी कुत्ते के बीच लड़ाई चल रही थी. सोनिया दोनों को अलग करना चाह रही थीं, लेकिन मेनका इस झगड़े से मजा ले रही थीं, क्योंकि उनका कुत्ता सोनिया के कुत्ते से मजबूत था. लेखक ने इंदिरा गांधी की सचिव उषा के हवाले से लिखा है कि मेनका बेहद ही बुद्धिमान, लेकिन महत्वाकांक्षी थीं. उन्हें हर वक्त यह लगता था कि जल्द ही संजय गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और वह गाहे–बगाहे यह बात सार्वजनिक रूप से कहती भी थीं. लेकिन, नियति को कुछ और ही मंजूर था. 1977 में कांग्रेस की करारी हार के बाद जब संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई, तो इंदिरा गांधी मेनका को लेकर बेहद चिंतित रहने लगीं. उन्होंने अपनी दोस्त पुपुल जयकर से चिंता जताते हुए कहा भी था कि मेनका की मां की महत्वाकांक्षा उसे संजय की जगह लेने के लिए प्रेरित करेगी. इस सोच को बल मिला खुशवंत सिंह के एक लेख से, जिसमें उन्होंने खुलेआम इस बात की वकालत की थी कि संजय की मौत के बाद उनकी राजनीतिक वारिस मेनका हैं. खुशवंत सिंह ने यह भी लिखा कि मेनका संजय गांधी की तरह बहादुर हैं और दुर्गा की अवतार हैं.

जाहिर है, खुशवंत सिंह के इस लेख से इंदिरा गांधी आहत हुईं, क्योंकि बांग्लादेश युद्ध में विजय के बाद इंदिरा गांधी की तुलना दुर्गा से होने लगी थी. खुशवंत की इस तुलना से इंदिरा गांधी के मन में यह संदेह पैदा हो गया कि मेनका की रजामंदी के बाद ही खुशवंत ने उक्त लेख लिखा. मेनका गांधी को घर से निकालने के इंदिरा गांधी के फ़ैसले पर भी यह किताब प्रकाश डालती है. मेनका को घर से बाहर निकाले जाते वक्त हुए हाई वोल्टेज ड्रामे पर भी मोरो ने विस्तार से लिखा है. ये सारी बातें लिखते हुए मोरो ने किताब में एक डिस्क्लेमर भी लगाया है कि बातचीत, संवाद और स्थितियां लेखक की व्याख्या पर आधारित हैं और यह ज़रूरी नहीं है कि वे प्रामाणिक भी हों. इस पूरे विवाद में जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के झंडाबरदारों पर सवाल खड़े होते हैं, उसी तरह लेखक की मंशा पर भी सवालिया निशान लगता है. सवाल वही कि क्या लेखकीय आज़ादी के नाम पर कुछ भी काल्पनिक लिखने की इजाजत किसी लेखक को दी जा सकती है? इन्हीं सवालों के बीच अब सोनिया की यह जीवनी भारतीय पाठकों के लिए उपलब्ध है. राजनीति और राजनेताओं की किताबों की खासी बिक्री के बीच इस बात पर सबकी नज़र रहेगी कि सोनिया गांधी की इस काल्पनिक जीवनी को हमारे देश का पाठक कैसे लेता है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

समीक्षा

ज़मीं की प्यास में नदी की तलाश

कुमार कृष्णन

हिंदी कविता का यह इतिहास रहा है कि वह समय–समय पर अपनी परिधियों को तोड़ती रही है. अपने शिल्प के साथ कथ्य का भी समय–समय पर इसने परित्याग किया है. इसका पुराना इतिहास देखने पर यह सहज ही सोचा और अनुमान लगाया जा सकता है. इसी परिवर्तन के क्रम में इसकी यात्रा गीत, नवगीत एवं मुक्त–छंद कविता से होते हुए ग़ज़ल पर आकर ठहरती है. वैसे तो ग़ज़ल के बारे में यह घोषणा की जाती है कि हिंदी में इसका प्रवेश उर्दू के रास्ते से हुआ है. ख़ैर, यह अलग विषय है. आज जो हिंदी में ग़ज़ल लिखी जा रही है, कहीं से आरोपित नहीं है कि वह अन्य भाषा की उपज है. वह हिंदी साहित्य में पूरी तरह से रच–बस चुकी है. यह हाल में प्रकाशित अशोक आलोक के ग़ज़ल संग्रह ज़मीं से आसमां तक की ग़ज़लों से पता चलता है. संग्रह में नब्बे ग़ज़लें हैं, जो सीधे–सीधे यथार्थ और समकालीन पृष्ठभूमि पर जाकर खड़ी होती हैं. अशोक आलोक एक सधे हुए ग़ज़लकार हैं, इसलिए उनकी ग़ज़लों में कथ्य और सौंदर्य का मिला–जुला भाव मिलता है. उनकी ग़ज़लें समकालीनता की शर्तें पूरी करती हैं और उन्हें हम मुक्त कंठ से समकालीन ग़ज़लें कह सकते हैं. अच्छी ग़ज़ल कहने के लिए जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए, वह अशोक आलोक के पास है.

सचमुच में आज हम जिस परिवेश और यथार्थ में सांसें ले रहे हैं, वह पूरी तरह से कष्टदायी है. एक प्रबुद्ध ग़ज़लकार के नाते अशोक आलोक इस पीड़ा को अच्छी तरह समझते हैं और अपनी ग़ज़लों में बखूबी व्यक्त भी करते हैं. अगर उनके शेर वर्तमान राजनीति के गिरते स्तर पर कटाक्ष करते हैं, तो हमारे घर आ घुसे बाज़ार पर भी उनकी नज़र है. मिसाल देखिए...

मुस्कुराता है अंधेरा ज़िंदगी में इस तरह,
कातिलों का बसेरा रोशनी में इस तरह.

इसी सत्य को संग्रह की भूमिका में अनिरुद्ध सिन्हा भी उद्घाटित करते हैं. उनका कहना है, यथार्थ और कल्पना के स्तर पर दोनों तरह के विकास स्वप्नों का बीज अशोक आलोक की ग़ज़लों में मौजूद है. अशोक जिस प्रकार अपने भविष्य–कल्पना के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उससे तो साफ़ जाहिर होता है कि उन्होंने कटु यथार्थ की यात्रा पूरी शिद्दत के साथ की है. उनके लेखन की विशेषता यह है कि उन्होंने आवेग और आवेश को औजार नहीं बनाया. ऐसा भी नहीं है कि समकालीन यथार्थ के प्रति उनके भीतर गुस्सा नहीं है. काफी

समीक्ष्य कृति : ज़मीं से आसमां तक (ग़ज़ल संग्रह)
ग़ज़लकार : अशोक आलोक
मूल्य : 150 रुपये
प्रकाशन : मीनाक्षी प्रकाशन, दिल्ली

सचमुच में आज हम जिस परिवेश और यथार्थ में सांसें ले रहे हैं, वह पूरी तरह से कष्टदायी है. एक प्रबुद्ध ग़ज़लकार के नाते अशोक आलोक इस पीड़ा को अच्छी तरह समझते हैं और अपनी ग़ज़लों में बखूबी व्यक्त भी करते हैं. अगर उनके शेर वर्तमान राजनीति के गिरते स्तर पर कटाक्ष करते हैं, तो हमारे घर आ घुसे बाज़ार पर भी उनकी नज़र है.

गुस्सा है, लेकिन वह गुस्सा विध्वंस की ओर नहीं जाता है, बल्कि कल्पना और बेहतर भविष्य की ओर जाता है. उन्होंने अपनी ग़ज़लों को नारा नहीं बनाया है. ग़ज़लों में प्यार का मद्धिम–मद्धिम स्वर पिरोया है.

समकालीन कटु यथार्थ को संबोधित करते हुए संग्रह के कुछ और शेर...

जिस्म जाता है सुलग देख के मंज़र अब भी,
कैसे कोई शख्स खुद होंठ को सिलता होगा.

****

है हवा के होंठ पर चिंगारियों का सिलसिला,
कुछ भी नहीं बाकी बचा, आंसू बहाने के सिवा.

****

बेवफ़ा परछाइयां हैं ज़िंदगी में इस तरह,
चीखती तन्हाइयां हैं ज़िंदगी में इस तरह.

संग्रह की ग़ज़लें सिर्फ़ यथार्थ की विसंगतियों की उबड़–खाबड़ ज़मीन ही तैयार नहीं करतीं, बल्कि कल्पना और सौंदर्य का एक बड़ा आसमान भी तैयार करती हैं. उस आसमान में हम खुशियों को तलाश कर सकते हैं. बानगी देखिए...

फूल खुशबू तितलियां थीं और हम,
याद की कुछ बदलियां थीं और हम.

****

किसी सवाल का उत्तर क़रीब तो आए,
कहीं सुकून का मंज़र क़रीब तो आए.

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अशोक आलोक ने अपनी ग़ज़लों में यथार्थ संप्रेषण के साथ–साथ कल्पना और सौंदर्य की प्रमुखता से विवेचना की है. कृति पठनीय है. यह साहित्य प्रेमियों को एक अच्छा संदेश दे, यही कामना है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कविता

पूरे चांद की रात

आज फिर पूरे चांद की रात है
और साथ में बहुत-से अनजाने तारे भी हैं...
और कुछ बेचैन-से बादल भी हैं...
उन्हें देख रहा हूं और तुम्हें याद करता हूं...
खुदा जाने,
तुम इस वक्त क्या कर रही होंगी...
खुदा जाने,
तुम्हें अब मेरा नाम भी याद है या नहीं...
आज फिर पूरे चांद की रात है!!
अलविदा
सोचता हूं, जिन लम्हों को
हमने एक-दूसरे के नाम किया है,
शायद वही ज़िंदगी थी!
भले ही वो ख्यालों में हो,
या फिर अनजान ख्वाबों में...
या यूं ही कभी बातें करते हुए...
या फिर अपने-अपने अक्स को
एक दूजे में देखते हुए हो...
पर कुछ पल, जो तुमने मेरे नाम किए थे,
उनके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूं!!
उन्हीं लम्हों को मैं
अपने वीरान सीने में रख,
तुमसे अलविदा कहता हूं!
अलविदा!!

-विजय कुमार सत्पथी

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

हीरो की दो ई-साइकिल लॉन्च

टू व्हीलर कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक ने अपनी अवियॉर सीरीज के तहत दो ई–साइकिल लॉन्च की हैं. इन ई–साइकिल को खासकर मेट्रो शहरों में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखकर उतारा गया है. हीरो की ई–साइकिल बेंगलुरू, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और चेंनई में भी उपलब्ध होंगी. छह स्पीड गियर की ई–साइकिल में लिथियम बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है जिसे 4.5–5.5 घंटों में चार्ज किया जा सकता है. यह ई– साइकिल अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है. इन ई–साइकिल को पुरूष और महिला दोनों वर्गों के लिए बनाया गया है. ये ई–साइकिल अवियॉर एमएक्स (AVIOR MX) और अवियॉर एफएक्स (AVIOR FX) के नाम से मौजूद हैं. इन ई–साइकिल की कीमत 18,990 और 19,290 रुपये तय की गई है. ■

सोनी ने लॉन्च की स्मार्टवॉच और बैंड

सोनी ने अपनी स्मार्टवाच3 और स्मार्टबैंड टॉक लॉन्च किया है. कंपनी का कहना है कि स्मार्टवॉच3 पहला स्मार्टवॉच है, जिसे विशेष तौर पर एंड्रॉयड वेयर अपडेट के लिए तैयार किया गया है, जबकि स्मार्टबैंड टॉक के जरिए अपनी कलाई से कॉल करने या आवाज नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जा सकेगा. स्मार्टवॉच की स्क्रीन 1.6 इंच की है, जो स्क्रैच और स्प्लैश प्रूफ मल्टी टच डिस्प्ले स्क्रीन है. ब्लूटुथ के साथ म्यूजिक, कॉल की सुविधा भी है और इसको फोन के साथ कनेक्ट किया जा सकता है. इसमें मेल और मैसेज की सुविधा दी गई है. साथ ही इसमें ऐप सर्च करने के लिए लाइववायर मैनेजर है. स्मार्टवॉच3 की कीमत 19,990 रुपये है और इसमें एक माइक्रोफोन, ऐक्सेलेरोमीटर, कंपास, जायरो और जीपीएस सेंसर है. इस वाटर–प्रूफ स्मार्ट उपकरण में 4जीबी की मेमोरी है. कंपनी ने कहा कि माइक्रोफोन और स्पीकर के साथ स्मार्टबैंड टॉक में उपभोक्ताओं को कम दर के लिए कॉल करने और कॉल करने वाले की आवाज सुनने की सुविधा होगी. स्मार्ट बैंड की चौड़ाई 23.5 एमएम और मोटाई 9.5 एमएम है. इस बैंड का डिस्प्ले–1.4 ब्लैक एंड व्हाइट ए इंक डिस्प्ले है. स्मार्टबैंड की कीमत 12,990 रुपये है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

नए अंदाज और फीचर्स के साथ टीवीएस जुपिटर

टीवीएस अपने 110सीसी जुपिटर के स्पेशल एडिशन को लॉन्च किया है. इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए है. जुपिटर स्पेशल एडिशन में 3डी मोनोग्राम का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा इसमें ड्यूरा कूल सीट का इस्तेमाल किया गया है जो सामान्य सीट से 10 डिग्री ज्यादा ठंडी रहती है. टीवीएस जुपिटर 109.7सीसी, 4 स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर एयर–कूल्ड, ओएचसी इंजन पर दौड़ता है. जुपिटर का पावरट्रेन 5.88 केडब्ल्यू (8 बीएचपी) पावर देने में सक्षम है. कंपनी का दावा है कि जुपिटर 62 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है. इसमें अंडर सीट 17 लीटर की स्टोरेज क्षमता है. अभी कंपनी इस नए एडिशन की कीमत का खुलासा नहीं किया है. पहले से मौजूद जुपिटर की कीमत लगभग 44,200 रुपये है. ■

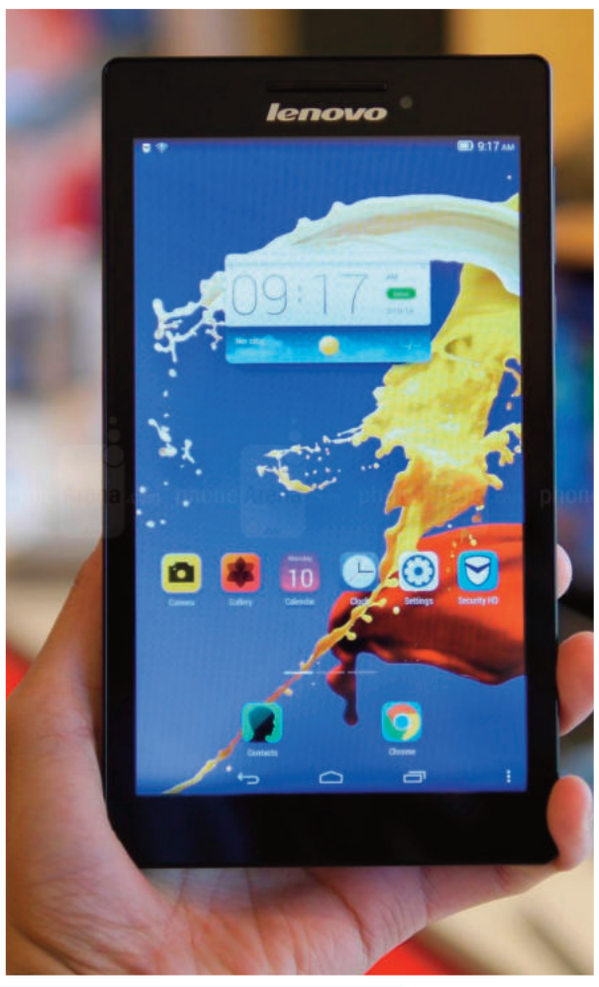

लेनोवो का 7 इंच की स्क्रीन का बेहद सस्ता टैबलेट

लेनोवो ने बेहद सस्ता टैबलेट टैब 2 ए7–10 पेश किया है. ए सीरीज के इस टैबलेट की कीमत महज 4,999 रुपये है. यह 1.3 जीएचजेड क्वॉड कोर मीडिया टेक प्रोसेसर से लैस है. इसमें लेनोवो डू इट ऐप पहले से मौजूद है. इस टैब की स्क्रीन 7इंच की है जो 1024 गुणा 600 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. इस टैबलेट का प्रोसेसर 1.3 जीएचजेड क्वॉड कोर मीडिया टेक से लैस है. साथ ही इसका रैम 1जीबी का है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 8 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. यह टैब एंड्रॉयड 4.4 किटकैट पर आधारित है. इसमें अन्य फीचर– वाई–फाई 802.11, ब्लूटुथ 4.0, जीपीएस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. इसकी बैटरी 3450 एमएएच की है. इस टैब की कीमत 4,999 रुपये है. ■

जिंदगी को आसान व सुरक्षित बनाएं

हर हफ्ते कई नए गैजेट बाजार में लॉन्च होते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग गैजेट के बारे में आइए जानते हैं.

1. घर आए मेहमानों से वीडीएफ से बात करें

गोदरेज सीथ्रू 7

यह गोदरेज सिक्युरिटी सॉल्यूशन द्वारा लॉन्च किया गया नया वीडियो डोर फोन है. जब आप घर पर न हों और घर आए मेहमान से बात करना चाहें तो लैंडलाइन के जरिए अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट हो सकते हैं. 7 इंच स्क्रीन वाले वीडियो डोर फोन में टीवी आउट ऑप्शन है. यह कई सीसीटीवी कैमरा और रिकॉर्डिंग के लिए रिमूवेबल एसडी स्लॉट है. इसकी कीमत 18,999 रुपये है.

2. इंटरचेंजेबल लेन्स कैमरा

निकॉन 1 एडब्ल्यू1

यह दुनिया का पहला इंटरचेंजेबल लेन्स वाटरप्रूफ कैमरा है. इसका मतलब है कि अब समुद्र की गहराई में मछलियों के साथ सेल्फी खींच सकते हैं. इसमें टेलिस्कॉपिक लेन्स फिट करके शार्क की आंख में झांक सकते हैं. ड्रामेटिक फुल एचडी इमेज शूट करने के लिए इससे अच्छा कोई गैजेट नहीं है. इसकी इमेज क्वालिटी जबरदस्त है. इसकी कीमत 39,950 रुपये है.

3. होम थियेटर सेट करें

आसुस विवोमिनी

इंटेल कोर आई5, आई3 या सेलेरन प्रोसेसर से लैस आसुस का नया मिनी पीसी है. वाई–फाई के अलावा 100जीबी तक आसुस वेब स्टोरेज स्पेस उपलब्ध है. कंपनी के होमक्लाउड फीचर से मीडिया लाइब्रेरी से वीडियो स्ट्रीम किया जा सकता है. ऐसा करने से होम थियेटर सेटअप करने में आसानी होगी. इसकी कीमत 13,500 रुपये है.

जियोनी का नया स्मार्टफोन

जियोनी ने एक नया स्मार्टफोन पायनियर पी6 लॉन्च किया है. इसकी खासियत है कि इसमें 2एमपी फ्रंट फेसिंग कैमरा है, जिसमे एलईडी फ्लैश है. जाहिर है, सेल्फी के शौकीनों के लिए यह एक बेहतरीन स्मार्टफोन है. यह एक एंड्रॉयड फोन है और 1.3 जीएचजेड क्वॉड कोर प्रोसेसर से लैस है. इसका रियर कैमरा भी एलईडी फ्लैश से लैस है और 5एमपी का है. यह डुअल सिम फोन है. इस फोन में 8जीबी का इनबिल्ड स्टोरेज है. इसके रियर कैमरा में फेस ब्यूटी, पैनोरमा, फेस डिटेक्शन, जियो टैगिंग, टच टू फोकस, कंटिन्यूअस शॉट्स, जेस्चर शॉट और स्माइल शॉट का ऑपशन है. इस फोन की स्क्रीन 5इंच की है जो 480 गुणा 854 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. यह फोन एंड्रॉयड 4.4 किटकैट पर आधारित है. इसका प्रोसेसर 1.3 जीएचजेड क्वॉड कोर मीडियाटेक 6582 प्रोसेसर से लैस है. पायनियर पी6 में 1जीबी रैम है जिसको माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 8जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. साथ ही इसमें 3जी, वाई–फाई, ब्लूटुथ 4.0, जीपीए की सुविधा भी है. इसकी बैटरी 1950 एमएएच की है. इसकी कीमत 8890 रुपये है. ■

होंडा का नया 150सीसी स्कूटर

यह 153सीसी, सिंगल सिलेंडर, 4–स्ट्रोक एसओएचसी, लिक्वड कूल्ड इंजन के साथ दौड़ता है. यह अधिकतम 13.4बीएचपी पावर और 14एनएम टार्क देने में सक्षम है. होंडा पीएसीएक्स के फ्यूल टैंक की क्षमता 8 लीटर है.

स्कूटर की बाजार में लोकप्रियता दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कई कंपनिया अपने स्कूटर के नए–नए वैरिएंट बाजार में लॉन्च कर रही हैं. इसी के तहत होंडा एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपना 150सीसी स्कूटर होंडा पीसीएक्स लॉन्च किया है. होंडा पीसीएक्स की बात करें तो यह भारत में मौजूद अन्य स्कूटर्स की तुलना में थोड़ा बड़ा है. यह 153सीसी, सिंगल सिलेंडर, 4–स्ट्रोक एसओएचसी, लिक्वड कूल्ड इंजन के साथ दौड़ता है. यह अधिकतम 13.4बीएचपी पावर और 14एनएम टार्क देने में सक्षम है. होंडा पीएसीएक्स के फ्यूल टैंक की क्षमता 8 लीटर है. होंडा पीसीएक्स 150सीसी में चौड़े हैडलैंप्स हैं और हैंडलैंप्स के ऊपर विंड डिफ्लेक्टर दिए गए हैं. होंडा पीसीएक्स 150सीसी की कीमत 70–75 हजार रुपये तक हो सकती है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

> आईपीएल के पूर्व सीईओ ललित मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बीसीसीआई के प्रशासकों पर बीसीसीआई के साथ व्यावसायिक हित रखने पर रोक लगाने आखिरकार हम श्रीनिवासन के प्रभाव के चंगुल से बाहर आ गए हैं. बीसीसीआई में श्रीनिवासन का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था. अब समय उनके प्राधिकार को कम करने का वक्त आ गया है. जब कोर्ट ने उन्हें बीसीसीआई से अलग रहने का आदेश दिया था उस वक्त उनके लिए आईपीएल के सीओओ सुंदर रमन काम कर रहे थे.

सुप्रीम कोर्ट का बाउंसर आरटीआई के दायरे में आया बीसीसीआई

स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, यह फैसला कई मायने में महत्वपूर्ण है. अपने फैसले में कोर्ट ने बीसीसीआई को सार्वजनिक संस्थान घोषित किया है. इस फैसले से बीसीसीआई सहित देश के सभी खेल संस्थान सूचना के अधिकार के दायरे में आ गए हैं. कोर्ट ने एक तीर से दो शिकार किए हैं, एक तरफ तो अपने आदेश से फिक्सिंग पर लगाम लगाई है तो दूसरी तरफ खेल संस्थानों को स्टेट की परिभाषा के दायरे में लाकर उन्हें देश के लोगों के प्रति जवाबदेह बना दिया है. जो काम इतने सालों में देश की संसद नहीं कर पाई वह काम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले से कर दिखाया है.

नवीन चौहान

न्यायाधीश टीएस ठाकुर और फकीर मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्लाह की पीठ ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले पर ऐतिहासिक फैसला दिया है. कोर्ट ने मुद्गल केमटी की रिपोर्ट पर सुनवाई की और अंतिम फैसला देते हुए कहा कि खेल तभी खेल है जब वह साफ–सुथरा और धोखाधड़ी से मुक्त होगा. कोर्ट ने एन श्रीनिवासन के दामाद गुरूनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा को फिक्सिंग का दोषी पाया है. हालांकि कोर्ट ने एन श्रीनिवासन को स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच में बाधा डालने के आरोप से बरी कर दिया. लेकिन हितों के टकराव के मसले पर कार्रवाई करते हुए उनके बीसीसीआई का चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है. इसके अलावा बीसीसीआई को छह सप्ताह के अंदर चुनाव करवाने का आदेश दिया है जिसमें एन श्रीनिवासन सहित उन सभी लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है. जिनका बीसीसीआई में व्यवसायिक हित है. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को बीसीसीआई का चुनाव लड़ने के लिए बीसीसीआई से जुड़े व्यवसायिक हित छोड़ने होंगे, अन्यथा ऐसे व्यक्ति बीसीसीआई का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे.

कोर्ट ने गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक राज कुंद्रा को फिक्सिंग का दोषी ठहराया है. लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उन्हें कोई सजा नहीं दी है लेकिन इन लोगों और इनकी टीमों पर कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन सेवानिवृत्त जजों की कमेटी का गठन किया है. कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा होंगे. कमेटी के अन्य सदस्य न्यायाधीश अशोक भान और न्यायाधीश आरवी रविन्द्रन होंगे. कमेटी इनके खिलाफ जो भी निर्णय देगी वह अंतिम होगा. कमेटी का निर्णय बीसीसीआई और इस मामले से जुड़े अन्य संबंधित पक्षों के लिए बाध्य होगा. आईपीएल के सीओओ सुंदर रमन की संदिग्ध भूमिका के संबंध में जांच लोढ़ा कमेटी करेगी. यदि उनके खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं तो उन्हें क्या सजा दी जाये, इसका निर्णय भी बीसीसीआई की तरफ से कमेटी ही करेगी. बीबी मिश्रा भी इस कमेटी की जांच के लिए उपलब्ध रहेंगे. उनके पास वे सभी अधिकार रहेंगे जो 16 मई, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिए थे.

नियम 6.2.4 में बीसीसीआई द्वारा किया गए संशोधन कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. बीसीसीआई की जनरल बॉडी ने इस नियम में आईपीएल और चैंपियंस ट्रॉफी–टी 20 प्रतियोगिताओं को छोड़कर जैसे शब्दों को जोड़ा गया था उसे गैरकानूनी करार दिया है. बीसीसीआई के नियम 6.2.4 में संशोधन से पहले प्रावधान था कि किसी भी खेल प्रशासक का प्रत्यक्ष अथवा अपत्यक्ष रुप से बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाने वाले मैचों और आयोजनों में व्यावसायिक हित नहीं होना चाहिए. लेकिन इसमें बाद में संशोधन कर दिया गया और व्यावसायिक हितों के दायरे से आईपीएल और चैंपियंस लीग टी–20 को अलग कर दिया गया. बोर्ड के इस फैसले से सीधा–सीधा फायदा एन श्रीनिवासन को पहुंचा. या कहें कि क्लॉज में बदलाव श्रीनिवासन को व्यवसायिक लाभ पहुंचाने के लिए किया गया. संशोधन को निरस्त करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि खेल की पवित्रता को नजरअंदाज करने से खेल का सार खत्म हो जाता है. कोर्ट ने नव गठित कमेटी को बीसीसीआई के मेरोरंडम ऑफ एसोसिएशन के नियमों और विनियमों की जांच करने और उसमें बदलाव करने के तरीकों पर बीसीसीआई को सुझाव देने को कहा है.

13 सितंबर,2007 को बीसीसीआई ने जनरल बॉडी मीटिंग में इंडियन प्रीमियर लीग लॉन्च करने का फैसला किया गया. इसके बाद टीमों की फ्रेंचाइज़ी की नीलामी की गई. इस नीलामी में भाग लेने वालों में इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड भी थी. जिसने चेन्नई फ्रेंचाइज़ी के लिए बोली लगाई और सफल रही. जिसे आगे चलकर चेन्नई सुपर किंग्स नाम दिया गया. इसके बाद 27 सितंबर, 2008 को बीसीसीआई की जनरल बॉडी मीटिंग में एन श्रीनिवासन को बीसीसीआई का सचिव चुना गया. उसी मीटिंग में नियम 6.2.4 में बदलाव का प्रस्ताव पारित किया गया. जिसमें व्यवसायिक हित के दायरे से आईपीएल और चैंपियंस लीग टी–20 को बाहर कर दिया गया. इसके बाद श्रीनिवासन बीसीसीआई के अध्यक्ष भी बने और चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक भी बने रहे.

स्पॉट फिक्सिंग मामले की शुरूआत साल 2013 के आईपीएल सीजन में हुई थी. तब दिल्ली पुलिस ने राजस्थान रॉयल्स के तीन खिलाड़ियों एस श्रीसंत, अजीत चंदेलिया और अंकित चव्हाण को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कार्यकारी और एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सह–मालिक राज कुंद्रा से पूछताछ की गई थी. इन दोनों पर भी फिक्सिंग करने का आरोप लगा. जैसे–जैसे मामले का खुलासा होता गया. बीसीसीआई के बड़े पदाधिकारियों ने पद छोड़ दिया. लेकिन अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने ऐसा करने से इंकार कर दिया, लेकिन कोर्ट के दबाव में अस्थाई रूप से इस मामले की जांच पूरी होने तक पद से अस्थाई रूप से अलग होने पर राजी हो गए.

बीसीसीई द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में गुरूनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा को क्लीन चिट दिए जाने के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव आदित्य वर्मा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस जांच रिपोर्ट को निरस्त कर दिया. बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश मुकुल मुद्गल की अध्यक्षता में जांच कमेटी को इस मामले की जांच करने को कहा. मुद्गल कमेटी ने जांच रिपोर्ट पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में सौंपी. समिति ने बीसीसीआई प्रमुख एन श्रीनिवासन के अलावा 12 अन्य लोगों के खिलाफ आरोपों की जांच की. समिति ने न्यायालय के समक्ष बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी.

आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग एक नज़र में

16 मई 2013:	राजस्थान रॉयल्स के तीन खिलाड़ी सांतकुमारन श्रीसंत, अंकित चव्हाण और अजित चंदेला स्पॉट फ़िक्सिंग के आरोप में गिरफ़्तार.
21 मई,2013:	विंदू दारा सिंह सट्टेबाज़ों के साथ रिश्ते के आरोप में मुंबई में गिरफ़्तार.
24 मई, 2013:	मयप्पन मुंबई पुलिस के सामने हाज़िर हुए, पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया.
02 जून, 2013:	बीसीसीआई की बैठक में फ्रेंचाइज़ी की जांच के लिए दो रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई.
11 जून, 2013:	श्रीसंत और चव्हाण जेल से जमानत पर रिहा हुए.
28 जुलाई, 2013:	बीसीसीआई की बनाई जजों की कमेटी ने राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को क्लीन चिट दी.
30 जुलाई,2013:	बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष आदित्य वर्मा ने बीसीसीआई के ख़िलाफ़ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की.
05 अगस्त,2013:	बीसीसीआई ने दो जजों की कमेटी की जांच रिपोर्ट को ख़ारिज़ करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की.
13 सितंबर,2013:	बीसीसीआई ने श्रीसंत और चव्हाण पर आजीवन प्रतिबंध लगाया.
07अक्टूबर,2013:	सुप्रीम कोर्ट ने फिक्सिंग मामले की जांच के लिए जस्टिस मुदगल कमेटी बनाई.
10 फरवरी,2014:	मुदगल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी
07 मार्च,2014:	बीसीसीआई ने हलफ़नामा दायर किया कि मयप्पन चेन्नई सुपर किंग्स में अधिकारी हैं, इसके मालिक नहीं.
01 सितंबर,2013:	सुप्रीम कोर्ट ने मुदगल समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए दो महीने का और समय दिया.
03 नवंबर, 2014:	मुद्गल कमेटी ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी.
24 नवंबर,2014:	मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई का जवाब.
22 जनवरी, 2015:	सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा को आईपीएल में सट्टेबाज़ी का दोषी माना.

बीसीसीआई निजि संस्थान नहीं

कोर्ट ने बीसीसीआई की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि वह एक निजि संस्था है, कोर्ट ने इस पर कहा कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि बोर्ड कुछ सार्वजनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम, खिलाड़ियों और खेल से जुड़ी गतिविधियों और लोगों को नियंत्रित करता है. बोर्ड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का चयन करता है, उसे विदेशों में खेलने के लिए भेजता है और वह देश के तमाम क्रिकेट स्टेडियमों का मालिक है. इसमें खेलने वाले खिलाड़ियों को सरकार भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों से नवाजती है. बीसीसीआई की गतिविधियों को सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करना या सरकारी कार्य कहा जा सकता है. इसलिए बीसीसीआई राज्य की परिभाषा के दायरे में आता है, भले ही उसका पंजीयन एक निजि संस्था के रूप में क्यों न हुआ हो. अब इसकी संविधान के अनुच्छेद–226 के अंतर्गत लोगों के प्रति जवाबदेही होगी. बोर्ड खिलाड़ियों, टीम, कर्मचारियों आदि के खिलाफ कार्रवाई करता है और पूरे क्रिकेट को नियंत्रित करता है. इतना ही नहीं बोर्ड क्रिकेट मैचों के प्रसारण अधिकार अरबों रुपये में बेचता है इसलिए बोर्ड को निजि संस्थान नहीं कहा जा सकता है. स्पष्ट रूप में यह एक सार्वजनिक कार्य है. पहले बोर्ड यह कहकर बच जाता था कि वह एक निजि और स्वायत्त संस्था है उसे सरकार से किसी तरह की वित्तीय सहायता नहीं मिलती है न ही वह सरकारी सहायता प्राप्त अनुषांगिक संस्था है. इसलिए उसके खिलाफ न तो कोई याचिका दायर कर सकता है और न ही वह सूचना के अधिकार के दायरे में आता है. लेकिन इस फैसले के बाद बीसीसीआई का कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने आ जायेगा. उसे सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 के अंतर्गत लोगों को सूचना उपलब्ध करानी होगी.

चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का भविष्य दांव पर

कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उसके आधार पर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स और राजस्थान रॉयल्स के ऑफीशियल्स गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा को दोषी ठहराये जाने के बाद दोनों फ्रेंचाइजियों के भविष्य पर तलवार लटक गई है. मयप्पन को आईपीएल ऑपरेशन्स रूल्स की धारा 2.2.1 और 2.14 का उल्लंधन किया जो कि खेल की छवि को खराब करने से संबंधित हैं. मयप्पन बीसीसीआई के एंटी करप्शन कोड आईपीएल ऑपरेशनल रूल्स के दायरे में भी आते हैं. इसलिए उन्हें आईपीएल ऑपरेशन रूल्स के रूल 4.4.1 और फेंचाइजी एग्रीमेंट की धारा 11.3 का दोषी पाया गया है. इसी तरह राजस्थान रायल्स में 11 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले राज कुंद्रा भी दोषी पाये गए हैं. सीएसके की फ्रेंचायजी के खिलाफ कार्रवाई करने में कमेटी को ज्यादा विचार नहीं करना पड़ेगा. लेकिन राजस्थान रायल्स के 89 प्रतिशत शेयर धारकों का भी ख्याल नवगठित कमेटी को रखना पड़ेगा. लेकिन आज खेल से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है. यदि ऐसा होता है तो आईपीएल की सबसे सफल और पहली आईपीएल चैंपियन टीमों का हमेशा के लिए अंत हो जायेगा.

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल ने फैसले पर हर्ष जताते हुए कहा कि यह फैसला सार्वजनिक कानून में एक बड़ी प्रगति है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने की वजह से इस फैसले का असर देश की सभी खेल संस्थाओं पर पड़ेगा. हितों का टकराव सिर्फ खेलों में ही नहीं बल्कि सभी सार्वजनिक संस्थाओं में भी उठता है. आईपीएल के पूर्व सीईओ ललित मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बीसीसीआई के प्रशासकों पर बीसीसीआई के साथ व्यावसायिक हित रखने पर रोक लगाने आखिरकार हम श्रीनिवासन के प्रभाव के चंगुल से बाहर आ गए हैं. बीसीसीआई में श्रीनिवासन का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था. अब समय उनके प्राधिकार को कम करने का वक्त आ गया है. जब कोर्ट ने उन्हें बीसीसीआई से अलग रहने का आदेश दिया था उस वक्त उनके लिए आईपीएल के सीओओ सुंदर रमन काम कर रहे थे. कोर्ट ने उनकी भूमिका और संदिग्ध गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए नई कमेटी को आधिकार दिए हैं. कहा जाता है कि ताकत भ्रष्ट बनाती है लेकिन ताकत भ्रष्ट होने योग्य लोगों को आकर्षित करती है. देश में क्रिकेट की साख दांव पर है और इसे बचाए रखने का सारा दारोमदार नई जांच कमेटी के ऊपर है ऐसे में आशा की जानी चाहिए कि यह कमेटी क्रिकेट की अखंडता को कायम रखने के लिए काम करेगी.■

navinonline2003@gmail.com

दुःखद अंत वाली लोकप्रिय फिल्में

बॉलीवुड में बनने वाली अधिकांश फिल्मों में प्रेम कहानियों की हैप्पी एंडिंग वाली होती हैं. सभा फॉर्मूला फिल्मों में संघर्ष करते नायक को अंततः सफलता मिल ही जाती है. लेकिन इससे इतर बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनीं जिनमें हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, लेकिन फिल्मों ने सफलता की नई इबारत लिखी और सफलता के नए झंड़े गाड़े. आइए दुःखद अंत वाली ऐसी ही कुछ सूपर हिट फिल्मों पर नज़र डालते हैं.

राजलक्ष्मी मल्ल

मुगल-ए-आजम

साठ के दशक में के.आसिफ के निर्देशन में बनी फिल्म मुगल–ए–आज़म एक रोमांटिक फिल्म थी. जिसकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक थी. यह फिल्म भारतीय सिनेमा इतिहास की सफलतम फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला मुख्य किरादार में थे. फिल्म का अंत पहले से ही मालूम होने के बावजूद भी यह फिल्म दर्शकों आज भी दर्शकों को जज़्बाती कर देती है. मुगल–ए–आज़म उस दौर में तकरीबन डेढ़ करोड़ रुपये में बनी थी. इस फिल्म में शहंशाह–ए हिंद, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पुत्र सलीम (दिलीप कुमार) को एक नर्तकी, अनारकली(मधुबाला) से प्रेम हो जाता हैं. सलीम उससे शादी करना चाहता है, लेकिन मुग़लिया सल्तनत के वारिस की एक नर्तकी से शादी स्वीकार नहीं होती है. धीरे–धीरे वक्त गुज़रता है, नौबत यहां तक आ जाती है कि शंहशाह अकबर अनारकली को दीवार में चुनवा देना का आदेश दे देते हैं. अनारकली और सलीम के कभी नहीं मिल पाने का ग़म दर्शक अपने साथ थिएटर के बाहर तक लेकर गए. अनारकली और सलीम मुहब्बत की अधूरी कहानी मुग़ल–ए–आज़म ने दर्शकों को इतना लुभाया कि इस फिल्म को 2004 में फिर से रिलीज़ किया गया. मुगल–ए–आजम ने उस दौर में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये. फिल्म को राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार और तीन फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाज़ा गया.

देवदास

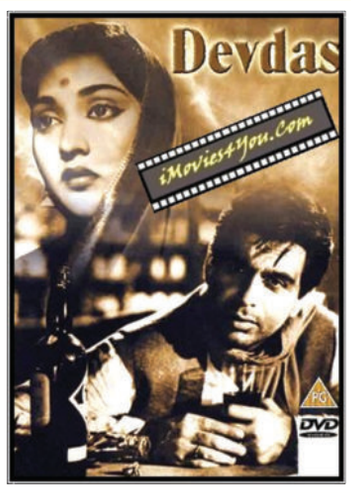

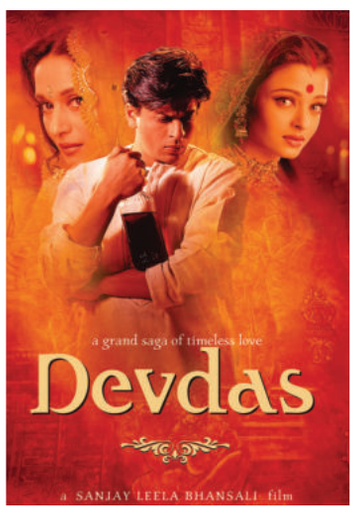

देवदास बंगाली लेखक शरतचंद चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित दुःखद हिंदी फिल्मों में से एक है. सबसे सामान्य और सरल प्रेम कहानी होने के बावजूद यह कभी पुरानी नहीं पड़ती है. इस उपन्यास पर अलग–अलग दौर में तीन बार फिल्म बन चुकी है. सबसे पहले फिल्म देवदास साल 1935 में बनी थी. इस फिल्म में मुख्य भूमिका में के एल सहगल थे. इसे परेश बरुआ ने निर्देशित किया था. इसके बाद साल 1955 में एक बार फिर यह फिल्म रुपहले पर्दे पर आई. इस बार फिल्म को बिमल रॉय ने निर्देशित किया था. इस बार देवदास की भूमिका में बॉलीबुड के ट्रैजडी किंग दिलीप कुमार नज़र आए. इसके बाद यह फिल्म साल 2000 में एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर नज़र आई. साल 2000 में चंद्रमुखी के किरदार में माधुरी दीक्षित और पारो का किरदार एश्वर्या रॉय ने निभाया था. फिल्म देवदास की शुरूआत देव और पारो की प्रेम कहानी से होती है. दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं. पारो बहुत खुबसूरत है, लेकिन देव स्वभाव से गुस्से वाला है. बचपन में ही देवदास पढ़ने के लिए विदेश चला जाता है. देव के वापस लौटने पर उनका प्यार भी वक्त के साथ जवान हो जाता है. देव के पिता उनके प्यार के खिलाफ होते हैं, इसी खिलाफत के कारण एक दिन देव गुस्से में घर छोड़ देता है. पारो की मां का देव के पिता अपमान करते हैं और वह उसकी शादी उनसे भी ऊंचे खानदान में करने की कसम खाती है. पारो को मां की जिद और अपमान के आगे बेबश हो जाती है. उसे दूसरी जगह शादी करनी पड़ती है. पारो की शादी के बाद दिल पर चोट खाया देव को शराब की लत लग जाती है. उसी समय उसकी मुलाकात चंद्रमुखी से होती है, जिसे देव बाबू से प्यार हो जाता है. ऐसे में देव ठान लेता है कि उसे पारो से मिलना है और वह उससे मिलने चल देता है. लेकिन वह उससे मिलने में नाकाम रहता है और पारो के घर के सामने दम तोड़ देता है. देवदास फिल्म हर जवान दिल की, हर प्यार करने वाले की अपनी कहानी कहती है. जो इस कहानी से रू–ब–रू होता है वह उसमें डूबता चला जाता है.

आनंद

साल 1970 में बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन निर्देशकों में से एक ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में राजेश खन्ना एक नए अंदाज़ में नज़र आये. संयोग से सात हिंदुस्तानी के बाद यह अमिताभ बच्चन के करियर की दूसरी फिल्म थी. फिल्म में राजेश खन्ना कैंसर से पीड़ित व्यक्ति की भूमिका में हैं, जो इस दुख को छिपाकर हमेशा एक हंसमुख जीवन का बिताता है. वह इस बात अच्छी तरह जानता है कि वह ज्यादा से ज्यादा छह महीने ही जीवित रहेगा. अमिताभ बच्चन ने डॉ भास्कर की भूमिका बड़े ही संजीदा तरीके से अदा की है. भास्कर आनंद को अपने धर ले आता है. भास्कर को रेनू नाम की लड़की से प्यार है लेकिन वह इसका इज़हार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है. इसमें आनंद उसकी मदद करता है. फिल्म के अंत में चाहकर भी भास्कर एक अच्छे खुशियां बाटने वाले इंसान को नहीं बचा पाता है. फिल्म का अंत में भास्कर के साथ आनंद की उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ होता है जिसमें हम सब तो रंगमंच की कठपुतली हैं बाबू मोशाय वाला संवेदनशील संवाद है.

क़यामत से क़यामत तक

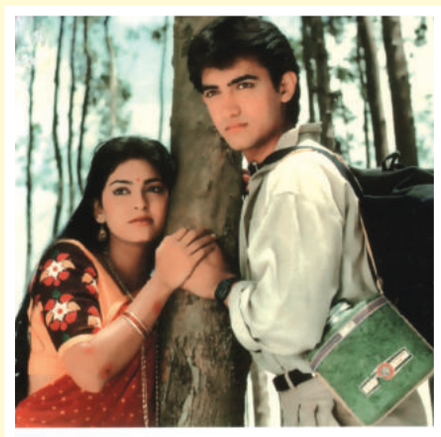

साल 1988 में बनी मंसूर खान की इस फिल्म ज़िक्र होना लाज़िमी है जिसमें प्रेमी–प्रेमिका साथ जीने–मरने की कसमें खाते हैं. दोनों अपनी कसमों को मरते दम तक निभाते हैं. फिल्म के अंत में दोनों की मौत हो जाती है. इस दृश्य को देखते हुए मन में बस एक ही बात रह जाती है कि किसी तरह दोनों बच जाते. फिल्म के दुःखद अंत ने कइयों के आंखें नम कर दी. कहानी कुछ इस तरह से है कि आमिर खान और जूही चावला एक– दूसरे से बेहद प्यार करते हैं. दोनों के परिवार एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं. इसके बाबजूद भी ये दोनों शादी कर लेते हैं. अंत में, परिवार वाले दोनों को मारने की योजना बनाते हैं. आमिर खान गोली मारने की कोशिश में जूही को गोली लग जाती है. जूही की मौत के बाद आमिर भी खुदकुशी कर लेते हैं. इस फिल्म में आमिर और जूही की मासूमियत लोगों को भा गयी. यह दोनों कलाकारों की पहली फिल्म थी. इस फिल्म को जबरदस्त सफलता मिली. इस फिल्म की सफलता की वजह से आमिर खान और जूही चावला रातों रात स्टार बन गए.

रंग दे बसंती

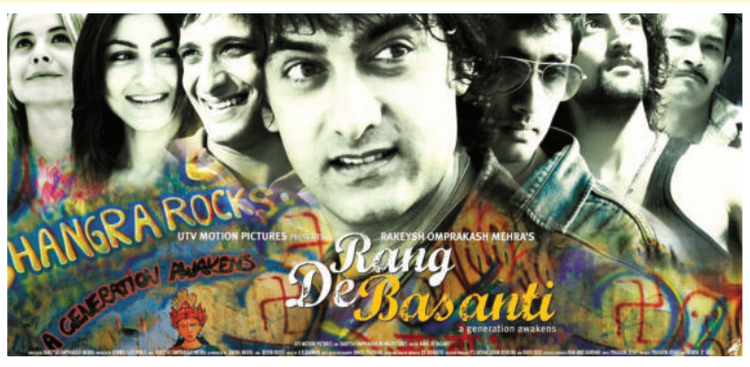

साल 2006 में रंग दे बसंती फिल्म रिलीज हुई. राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने इस फिल्म के जरिये देश में मौजूदा भ्रष्ट व्यवस्था और उसकी वजह से देश के शहीदों के बलिदान को दर्शाया जिसके प्रति युवा पीढ़ी के प्रेम और उनके आक्रोश को अभिव्यक्त किया है. जो आपको अंदर से सोचने पर विवश कर देती है. इस फिल्म का बड़ा हिस्सा कॉलेज कैंपस में फिल्माया गया है. फिल्म में अपने और अपने कॉलेज के दोस्तों में मस्त रहने वाले यूनीवर्सिटी के छात्र कैसे खुद को कुर्बान करके देश को बदलने का जिम्मा अपने सिर पर उठा लेते हैं. क्योंकि भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से उन्होंने अपने एक अजीज दोस्त खोया, इसके बाद उसपर ग़लत इल्ज़ाम लगा. फिल्म में इसे आकर्षक तरीके से दिखाया गया है. आमिर खान के साथ माधवन, शरमन जोशी के अलावा कुछ नए कलाकारों ने इस फिल्म में अभिनय किया. अंत में सत्ता का वरोध करने के कारण आवाज बुलंद करने वालों रंग दे बसंती को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म वर्ग में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और आस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था.

आशिकी-2

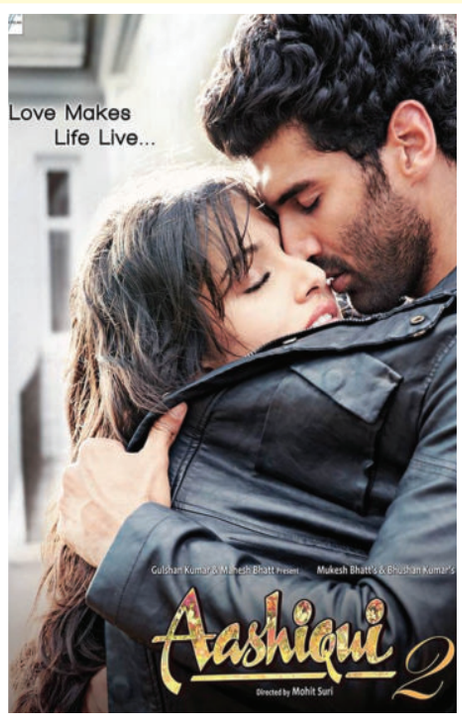

लेखिका शगुफ्ता रफीक़ की फिल्में काफी दिलचस्प और रोमांटिक होती हैं. फिल्म के कई हिस्से बहुत ही तनावपूर्ण और दुःखद होते हैं जो फिल्म को डार्क बनाते हैं. फिल्म में एक का त्याग ही दूसरे की सफलता की सीढ़ी है.ऐसी ही आशिकी–2 में भी नज़र आया. हीरो की ज़िंदगी पटरी पर लाने के लिए हीरोइन का बलिदान फिल्म का ट्रंपकार्ड है. दूसरी तरफ हीरोइन को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए हीरो का बलिदान. आरोही का अपने प्रेमी राहुल के प्रति प्यार और उसे सुधारने की कोशिश करना वाला एंगल दर्शकों को अपने साथ जोड़ पाने में कामयाब होता है. आशिकी–2 की कहानी सिंगर राहुल जयकर (आदित्य रॉय कपूर) और लड़की आरोही शिर्के (श्रद्धा कपूर) की है. राहुल एक रॉक– स्टार गायक है, जिसे शराब पीने की बुरी लत लग जाती है. धीरे–धीरे वह तबाही के रास्ते पर चला जाता है. एक दिन एक बियर बार में आरोही (श्रद्धा कपूर) को अपना गाना गाते सुनता है और उसे आरोही से उसी पल प्यार हो जाता है. वह आरोही से वादा करता है कि उसे एक दिन बहुत बड़ी गायिका बनायेगा. राहुल की मेहनत और अपने टैलेंट से एक दिन आरोही काफी बड़ी गायिका बन जाती है. लेकिन राहुल खुद अपने करियर पर बिलकुल भी ध्यान नहीं देता और बेहिसाब शराब पीता रहता है जिसका उसका करियर लगभग खत्म हो जाता है अंत में वह आत्महत्या कर लेता है.

गोलियों की रासलीला-रामलीला

संजय लीला भंसाली के बैनर तले बनी फिल्म गोलियों की रासलीला: रामलीला साल 2013 में रिलीज़ हुई. फिल्म में दो समुदायों के बीच खूनी रंजिश को दिखाया गया है. इस वजह से दो प्यार करने वाले प्यार के लिए कुर्बान हो जाते हैं. कहानी गुजरात के एक गांव की है, यह गांव दो समुदाय में बंटा हुआ है, रजोड़ा और सनोरा. जो गोली – बंदूको की तस्करी करते हैं सनोरा का राजकुमार है राम (रणवीर सिंह), जिसे प्यार हो जाता है रजोड़े की राजकुमारी लीला (दीपिका पादुकोण) से. दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं. ये जानते हुए भी राम और लीला एक दूजे प्यार करने लगते है, एक दिन लीला के भाई के हाथों राम के भाई का खून हो जाता है. गुस्से में राम भी लीला के भाई को मार देता है. ये बात रजोड़े की बा धनकोर (सुप्रिया पाठक) को बर्दाशत नहीं होती है. वह अपने भतीजे भवानी (गुलशन देवईया) की मदद से सनोरों के खिलाफ जाल बुनने लगती है. मौका पाकर एक दिन राम और लीला भाग जाते हैं. पर वह भवानी के हाथों से दूर नहीं जा पाते हैं. दोनों को अलग–अलग कर दिया जाता है. इसके बाद दोनों अपना–अपना समुदाय चलाते हैं. अंत में गांवों के बीच आपसी रंजिश को मिटाने के लिए दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर लेते हैं. और अपने प्यार को हमेशा के लिए अमर कर देते हैं.

मदर इण्डिया

महबूब ख़ान द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म मदर इंडिया फिल्म साल 1957 में रिलीज़ हुई थी. इस फ़िल्म में आजादी के बाद भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, पुरुषों के बढ़ते आकर्षण का विरोध और अपने स्वाभिमान पर दृढ़ निश्चय को दर्शाया गया. फिल्म में एक औरत के संघर्ष और हौसले को दिखाया गया है, जो विपरीत परिस्थिति में भी डटकर अपेन उसूलों के साथ खड़ी रहती है. फिल्म में लाला का उधार ता उम्र ना चुका पाने का किसान के दर्द को दिखाया है. राधा इस फिल्म की मुख्य किरदार है. फिल्म में पति की मौत के बाद वह अपने दो बच्चों का पालन पोषण तंगी में करती है. लेकिन लाला का कर्ज नहीं चुका पाती है. उसके बेटों में से एक डाकू बन जाता है जो अंत में बदाल चुकाने के लिए लाला की बेटी को उठा लेता है, लेकिन रोकने पर भी न रुकने पर वह अपने लाड़ले बेटे को गोली मार देती है.

रॉकस्टार

दिल्ली विश्विद्यालय में पढ़ने वाला जनार्दन जाखड़ एक बड़ा संगीतकार बनना चाहता है. जनार्दन कॉलेज और दोस्तों में जेजे और जॉर्डन के नाम से मशहूर है. उसे जब भी मौका मिलता है वह अपने संगीत के बल पर लोगों का दिल जीतने का प्रयास करता है. जनार्दन का म्यूजिक के प्रति जुनून देख कैंटीन इंचार्ज खटाना उसे किसी लड़की से सच्चा प्यार करने और प्यार में दिल टूटने के बाद सिंगर बनने की सलाह देता है. इसके बाद जनार्दन कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हीर कौल (नरगिस फाखरी) से अपने प्यार को प्रपोज करता है. शुरुआती नोकझोंक के बाद हीर उसे चाहने लगती है. लेकिन फिर वह उसे छोड़ देता है. हीर का विवाह चेकोस्लोवाकिया में हो जाता है. उस वक्त जेजे को एहसास होता है कि हीर उसके सपनों की रानी है और वह भी एक म्यूजिक कंपनी से करार कर वहीं चला जाता है. लेकिन अंत में नशे की लत पड़ जाती है. अंत में हीर की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है और जॉर्डन एक बार फिर अकेला रह जाता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

02 फरवरी–08 फरवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

सुशासन के साथ

साधू यादव याद दिलाते हैं कि 2007 में तो नीतीश कुमार भी एक समारोह में आए थे तो उस समय तो जदयू को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, उस समय तो कोई दहशत नहीं फैली थी. आज जब महादलित मुख्यमंत्री मेरे घर आता है तो बैचनी हो जाती है. साधू यादव का हौसला तब और बढ़ गया जब मांझी सरकार के कुछ बड़े मंत्रियों ने साधू यादव के पक्ष में बयान दे डाले.

नीतीश को अलग-थलग करने की तैयारी

नीतीश कुमार से नाराज चल रहे जदयू के कुछ मंत्री और विधायक प्लान बी पर भी बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं. प्लान ए तो पहले से ही साफ है कि जदयू का एक बड़ा धड़ा अलग होगा और एक अलग गुट बनाकर भाजपा से तालमेल कर चुनावी अखाड़े में उतरेगा. अगर टूट छोटी हुई तो फिर बागी नेता भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे. गेंद भाजपा के पाले में हैं कि वह बागियों को अपनी चुनावी रणनीति के तहत कितना तवज्जो देती है. कुछ चुनिंदा लोगों को टिकट देती है या फिर अलग गुट के तौर पर उससे सीटों का तालमेल करती है. यह सारा कुछ निर्भर करेगा कि जदयू में कितनी बड़ी टूट होती है. यही वजह है कि जदयू के कई नेताओं ने प्लान बी पर भी काम शुरू कर दिया है. इस योजना को तभी अमल में लाया जाएगा जब भाजपा से उनकी बात नहीं बनेगी. ऐसे में धर्मनिरपेक्षता का नारा बुलंद करते हुए नीतीश से खफा नेता लालू प्रसाद से हाथ मिला सकते हैं. ऐसे नेताओं का यह अनुमान है कि लालू प्रसाद कभी विलय नहीं करेंगे और विलय के नाम पर नीतीश कुमार को केवल उलझा कर रखेंगे. ऐसे में अगर लालू प्रसाद के साथ मांझी गुट का सम्मानजनक तालमेल हो जाता है तो फिर इसे एक बड़ी राजनीतिक और जातीय गोलबंदी का गठबंधन माना जाएगा. जानकार सूत्र बताते हैं कि भाजपा पर दबाव बनाने के लिए इस वैकल्पिक योजना पर भी गौर किया जा रहा है. जदयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने जिस तरह से मंत्री नरेंद्र सिंह और नीतीश मिश्रा का इस्तीफा मांगा उससे बागी खेमा बेहद नाराज है. नरेंद्र सिंह खुद आहत हैं. शरद यादव, नीतीश कुमार और वशिष्ठ बाबू के यहां वह अपनी बात भी रख आए हैं. इसके बावजूद प्रवक्ता का बयान वापस नहीं लिया गया जिसका साफ अर्थ है कि नीतीश खेमा किसी भी हाल में मांझी समर्थक नेताओं को ढील नहीं देना चाहता है. श्याम रजक ने भी अपने यहां भोज में मांझी समर्थक मंत्रियों को न्योता नहीं भेजा. श्याम रजक का कहना है कि इस भोज का राजनीतिक अर्थ लगाना गलत होगा. यह एक सामान्य भोज था. लेकिन जानकार बताते हैं कि यह भोज मांझी समर्थकों पर दबाव बनाने का एक कदम था. लेकिन नरेंद्र सिंह को जानने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वह मौके पर मार करने वाले माहिर खिलाड़ी हैं. फिलहाल भले ही वह चुप हो गए हैं लेकिन जिस तरह अजय आलोक जैसे जूनियर नेता से उनका इस्तीफा मांगवाया गया वह सूबे में आने वाले दिनों में होने वाले सियासी भूचाल का आगाज भर है. इसका अंजाम क्या होगा इस पर इस समय तो केवल अटकलबाजियां ही हो रही है क्योंकि परदे के पीछे जो सियासी गोटियां बिछाई जा रही है उसकी मार बजट सत्र के आस पास दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगी. ■

सरोज सिंह

मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दही चूड़ा खाने लालू प्रसाद के साले और पूर्व सांसद साधू यादव के निवास पर क्या गए कि हंगामा बरप गया. इस छोटी सी घटना ने बिहार के पहले से ही उलझे सियासी समीकरणों को और भी उलझा दिया. यह सभी जान रहे हैं कि सूबे में इस समय राजद और जदयू के विलय को लेकर अटकलों का बाजार बेहद गर्म है. मकर संक्रांति के दिन लालू प्रसाद ने दो राजनीतिक दलों के विलय के मामले को जिस तरह अपने अंदाज में हल्के में उड़ा दिया उससे यह बात तो साफ हो गई कि विलय का रास्ता आसान नहीं है और इसे अभी बहुत सारी अग्निपरीक्षाओं से गुजरना होगा. सूबे के मौजूदा राजनीतिक हालात को समझने के लिए यह भी समझना जरूरी है कि विलय की घटना अपने साथ एक तूफान भी लेकर आएगी. यह तूफान या तो जदयू को दो फाड़ कर देगा या फिर मांझी सरकार को ले डूबेगा. अगर जीतन राम मांझी के साधू यादव के घर जाकर चूड़ा दही खाने पर सूबे में बवाल मच गया तो इसकी पृष्ठभूमि हमें विलय और इसके साइड इफेक्ट के आस-पास ही देखनी चाहिए. बात अब साधू यादव से शुरू करते हैं. लालू -राबड़ी शासनकाल के अस्त होने के बाद से ही साधू यादव राजनीतिक तौर पर अपने को जिंदा रखने की कोशिश करते रहे हैं. नीतीश कुमार से भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वह अचानक तब सुर्खियों में आ गए जब नरेंद्र मोदी से उनकी गुजरात में मुलाकात हुई. चर्चा जोर पकड़ने लगी कि साधू यादव बीजेपी के टिकट पर चुनावी अखाड़े में उतरेंगे. लेकिन भाजपा की स्थानीय इकाई के भारी विरोध के कारण मामला ठंडा पड़ गया. साधू यादव ने हार नहीं मानी और गरीब जनता दल का गठन किया और सूबे की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं. साधू यादव को लेकर मौजूदा बवाल तब शुरू हुआ जब जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया कि जीतन राम मांझी को साधू यादव के घर दही-चूड़ा खाने नहीं जाना चाहिए क्योंकि साधू यादव दहशत के पर्याय हैं.

नीरज का कहना था कि साधू यादव के नाम से ही लोग सहम जाते हैं और ऐसे लोगों के घर मुख्यमंत्री का जाना सुशासन की धारा को कमजोर करता है. सीएम को ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए. जदयू प्रवक्ता के कहते ही साधू यादव ने बिना समय गंवाए पलटवार करना शुरू कर दिया. साधू यादव ने कहा कि मेरी छवि तो कुछ तथाकथित बड़े नेताओं ने बिगाड़ दी. यह एक दिन की कहानी नहीं है. सालों से यह काम हो रहा है. कई नेता आज भी इस काम में लगे हैं. अपने को पाक-साफ बताते हुए साधू यादव कहते हैं कि मुझ पर तो कोई गंभीर मामला भी नहीं चल रहा है, जो है वह चुनावी केस है. लेकिन जिन लोगों पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं उनके बारे में जदयू को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए. इस संदर्भ में उन्होंने मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, हुलास पांडेय, सुनील पांडेय और अनंत सिंह जैसे नेताओं का नाम लिया.

साधू यादव कहते हैं कि महादलित समाज का मुख्यमंत्री मेरे घर पर मेरे निमंत्रण पर दही चूड़ा खाने आया तो यह बात जदयू के नेताओं को नहीं पच रही है. ऐसा करके मैंने कोई अपराध किया है क्या? साधू यादव याद दिलाते हैं कि 2007 में तो नीतीश कुमार भी एक समारोह में आए थे तो उस समय तो जदयू को कोई दिक्कत नहीं हुई थी. इस समय तो कोई दहशत नहीं फैली थी. आज जब महादलित मुख्यमंत्री मेरे घर आता है तो बैचनी हो जाती है. साधू यादव का हौसला तब और बढ़ गया जब मांझी सरकार के कुछ बड़े मंत्रियों ने साधू यादव के पक्ष में बयान दे डाला. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर साधू के घर गए तो इसमें गलत क्या है.

साधू यादव कोई चंबल का डाकू है जो उसके यहां जाने से परहेज करना चाहिए. ठीक इसी तरह की बात वृशिण पटेल और भीम सिंह ने भी कही. कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं ने भी साधू यादव का पक्ष लिया. दरअसल दही चूड़ा प्रकरण ने साधू यादव के लिए राजनीति के कई दरवाजे एक साथ खोल दिए. जानकार सूत्र बताते हैं कि विलय विरोधी नेताओं से साधू यादव अब लगातार संपर्क में हैं. जीतन राम मांझी ने साधू यादव के घर जाकर यह साफ कर दिया कि सत्ता की कुर्सी पर अब वह किसी की अनुकंपा पर नहीं हैं. लालू प्रसाद और नीतीश कुमार इस मुगालते में नहीं रहें कि सत्ता की चाबी उनके पास है. यह सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद अपने साले साधू यादव को पसंद नहीं करते हैं. इसके बावजूद मांझी का उनके घर जाना क्या संदेश देता है, इसे सभी समझ रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

लेसन प्लान संपन्न

मगध टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चर्च रोड, गया का लेसन प्लान का समापन रंगारंग कार्यक्रमों द्वारा संपन्न हुआ. 1 दिसम्बर 2014 से शुरू लेसन प्लान 10 जनवरी 2015 तक चला. सत्र 2014-15 के लिए मगध टीचर्स ट्रेनिंग के 20-20 अध्यापकों/अध्यापिकाओं की टीम, गया जिले के हरिदास सेमिनरी, टी मॉडल, अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालय, रामरुची कन्या उच्च विद्यालय और हादी हासमी स्कूल में 40 दिनों की ट्रेनिंग चली. ट्रेनिंग की समाप्ति पर एक समारोह का भव्य आयोजन हुआ. हरिदास सेमिनरी में प्रो. दीपक कुमार मगध टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, और अध्यक्षता प्राचार्य के हाथों संपन्न हुई तथा टी मॉडल विद्यालय में हुई. इसके बाद रामरुची कन्या उच्च विद्यालय में भी रंगारंग कार्यक्रम के साथ अध्यापक/ अध्यापिका को विदाई दी गयी. कार्यक्रम की अध्यक्षता रामरुची विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने की. संचालन प्रेम लता ने किया. कार्यक्रम में रामरुची विद्यालय के शिक्षकों के अलावा मगध टीचर्स ट्रेनिंग विद्यालय की प्रो. डा. अनीता सिन्हा, डॉ. दीपक कुमार, डॉ. नरेन्द्र और डॉ. प्रशान्त जी का भी योगदान रहा. मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. मंगला यादव, प्राचार्य मगध टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, गया ने अपने भाषण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया.

– अनिल कुमार

नि:शुल्क पौधा वितरण

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उच्च माध्यमिक के मुख्य द्वार के पास स्थानीय महंत हनुमान शरण कॉलेज, राजापुर मैनपुरा, पटना-1 के सौजन्य से नि:शुल्क पौधा वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन परीक्षा समिति के अध्यक्ष प्रो. डॉ. लालकेश्वर प्रसाद सिंह ने किया. इसके उपरांत उक्त कालेज के शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के साथ अध्यक्ष प्रो. डॉ. लालकेश्वर प्रसाद सिंह, कॉलेज के प्राचार्य डॉ बिमल नारायण आर्य तथा कथाकार डॉ. लालजी प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से आम जनता के बीच नि:शुल्क पौधा वितरण किया. उक्त आयोजन में एलोवेरा, अडेनियम, लेमनग्रास, डेजर्त, फलावर, लौंग तुलसी, शम्मी, टिकोमा, सुदर्शन, चाइनीज लीली, रजनीगंधा, बेला, ओड़हुल, कढ़ी पत्ता, नीम, आम, जामुन, शीशम, अमरूद, अपराजिता, रबर प्लांट, मनी प्लांट, पीपल, गेंदा, गुलदाइदी, पत्थरचट्टा, करोटन इत्यादि फल फूल एवं औषधि के लगभग तीन हजार पौधे बांटे गए. उक्त अवसर पर कालेज के प्राचार्य डॉ. बिमल नारायण आर्य एवं कथाकार डॉ. लालजी प्रसाद सिंह ने कहा कि हम शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के साथ मिलकर विगत कई वर्षों से अपने कालेज की नर्सरी में पौधों को तैयार करते रहे हैं और समय-समय पर आम जनता के बीच में निशुल्क वितरण करते रहे हैं. उक्त समारोह में मुख्य रूप से प्रो. पंकज कुमार, प्रो. नवीप कुमार, प्रो. भूपेन्द्र कुमार, प्रो. मीरा कुमारी, प्रो. रीना सिन्हा, प्रो. दीपक कुमार, सीएन आर्य, डॉ. सुमा सिन्हा, डॉ. उर्मिला कुमारी, प्रो. धर्मनार्थ सिंह, प्रो. गुलाम रब्बानी, प्रो. सरिता सिन्हा, प्रो. अजय आजाद, बिन्देश्वर प्रसाद, शैलेन्द्र सिंह, छोटन प्रसाद इत्यादि शामिल थे.■

– भारती

स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का घोटाला

इंतेज़ारुल हक़

बिहार की सुशासन सरकार स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने व भ्रष्ट अधिकारियों तथा घोटालेबाजों पर कार्रवाई करने के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो जरूर करती है और निगरानी विभाग के अधिकारियों का सहारा भी लेती है किन्तु पूर्वी चम्पारण जिले के स्वास्थ्य विभाग की खबर नहीं लेती. इस कारण यह विभाग इन दिनों भ्रष्टाचार की मजबूत दीवारों से बनी उस वातानुकूलित इमारत की तरह हो गया है जिस के अन्दर बैठे व्यक्तियों को मौसम के मिजाज की चिंता नही होती है और खुलेआम करोड़ों का घोटाला करना व मरीजों का दोहन करना इनकी फितरत सी बन गयी है.चौथी दुनिया को कई ऐसे महत्वपूर्ण दास्तवेज मिले हैं जिसे पढ़ने व देखने का बाद एक तरफ करोड़ो रूपये का घोटाला होने का मामला सामने आया है तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को सह देने व विभागीय आदेशों की धज्जिया उड़ाने वाले को कैसे बचाया जाता है,यह भी खुलासा हुआ है.

पूर्वी चम्पारण जिले का केसरिया व मधुबन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इसका ज्वलन्त नमूना है. केवल केसरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 92 लाख 30 हजार सात सौ 89 रुपये का घोटाला हुआ है जिसकी सूचना वहां के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन डॉ. मीरा वर्मा को कार्यालय के पत्रांक 616 दिनांक 9.12.014 के तहत इसकी सूचना दे दी गयी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह राशि एनआरएचएम योजना की है. स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रतिनियुक्त कर्मचारी संजय कुमार पाण्डेय के नाम से उक्त राशि का चेक काटा गया था. बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर वर्ष 2009 से 20011 तक हुए खर्च का जब ब्योरा तैयार किया गया तब उक्त राशि के घोटाला का मामला सामने आया. संजय द्वारा वर्ष 2006 से मई 20012 तक एनआरएचएम के विभिन्न कार्यक्रमों में राशि खर्च की गयी है जिसमें अधिकांश की निकासी नगद होने की बात बतायी गयी है और इसकी अभिश्रव व भुगतान पंजी कार्यालय को नही सौंपी गयी है.मई 2012 में जब संजय द्वारा लेखापाल रवि रंजन एवं लिपिक मुरारी कुमार गुंजन को प्रभार दिया गया था तभी यह मामला सामने आया था किन्तु इस संचिका को सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा आरोपी को बचाने की नीयत से किसी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया.इसके बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने अपने कार्यालय के पत्रांक 228 दिनांक 10.4.14 के द्वारा ही इस मामले से सिविल सर्जन को अवगत कराते हुए विभागीय कार्रवाई करने व प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया किन्तु इसपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. दूसरी तरफ इसी तरह का मामला मधुबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से जुड़ा हुआ है.मरीज दवा के लिए भटकते रहे और मजबूर हो निजी दुकानों से खरीदते रहे. इसका परिणाम यह हुआ कि दवा एक्सपायर हो गयी और इसे शौचालय में फेंक दिया गया. इसकी शिकायत सिविल सर्जन से की गयी और इस मामले को मंत्री रमई राम की अध्यक्षता में हुई जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में उठाया गया. सिविल सर्जन की खिंचाई भी हुई और इस मामले की गहनता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी.

दूसरी तरफ मोतिहारी सदर अस्पताल समेत जिले भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए खाना बनाने व कपड़ा धुलाई का कार्य करने वाली संस्था पुष्पभारती के साथ हुई घटना भी किसी से छिपी हुई नहीं है. पहले खुलेआम प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा रंगदार की तर्ज पर रिश्वत मांगी गयी और नहीं देने पर परफॉरमेन्स खराब कर देने की धमकी तक दे डाली गयी. पुष्पभारती के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा सराहनीय कार्य किये जाने की चर्चा एक तरफ जहां लगातार होती है और अस्पताल के मरीज भी उनका गुण-गान करते है तो दूसरी तरफ इसके अधिकारियों से सदर अस्पताल के अधिकारी रिश्वत के लिए मजबूर करते हैं. मोतिहारी व छौड़ादानो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉ. श्रवण पासवान व स्वास्थ्य प्रबंधक बिजय चन्द्र झा पर संस्था के अधिकारियों से रिश्वत मांगने का लगा आरोप इसका ज्वलन्त उदहारण है. पुष्पभारती के संचालक कृष्णनन्दन सिंह ने अनुमण्डल दण्डाधिकारी के न्यायालय में धमकी का एक आवेदन भी जमा कराया और सिविल सर्जन को विधिवत इसकी सूचना भी दी किन्तु इसका भी कोई असर नहीं हुआ.

सदर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक विजय चन्द्र झा पर रिश्वत के तौर पर संस्था के संचालक से कीमती मोबाइल व गोदरेज की अलमिरा मांगने का आरोप लग चुका है. आखिर इस मामले को सिविल सर्जन ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया और इसकी निष्पक्षता से जांच क्यों नहीं करायी, इस बाबत अनेक तरह की चर्चाएं हो रही है. इसके अलावा भी कई एसे मामलों का खुलासा हुआ है जिससे सदर अस्पताल व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े गये हैं. कुल मिलाकर सदर अस्पताल व स्वास्थ्य विभाग इन दिनों भ्रष्टाचार का मुख्य केन्द्र बनता दिख रहा है.इस बीच लोजपा युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव परवेज खां इसके लिए बिहार की सरकार को सीधा जिम्मेदार बताते हैं और कहते हैं कि सरकार की भ्रष्ट नीति ने स्वास्थ्य विभाग को और भ्रष्ट बना दिया है.वे कहते हैं कि अस्पताल में मरीजों के इलाज के नाम पर केवल लूट मची हुई है और राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

चीनी मिल मजदूरों को आखिर कब मिलेगा न्याय?

इंतेज़ारुल हक़

चंपारण के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित चीनी मिलों में कार्यरत कर्मचारियों व मजदूरों को आखिर कब मिलेगा न्याय? कब तक इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मिल प्रबंधकों द्वारा किया जाता रहेगा और प्रशासनिक पदाधिकारी व विभागीय अधिकारी इस बाबत चुप्पी साधे रहेंगे? विभागीय अधिकारी व प्रशासनिक पदाधिकारी इनपर इतना मेहरबान क्यों हैं? क्या यहां कार्यरत मजदूरों व कर्मियों के साथ लगातार हो रहे अन्याय पर रोक लगाने के लिए सरकार व विभाग के पास कोई कानून नहीं है?अगर है तो फिर इनकी मनमानी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस मुद्दे पर इन दिनों एक गरम बहस छिड़ी हुई है और प्रशासनिक पदाधिकारियों व विभागीय अधिकारियों की चुप्पी पर अनेक तरह की चर्चाएं की जा रही है.काफी दिनों से बंद पड़ी सुगौली की चीनी मिल को जब दो साल पूर्व एचपीसीएल कम्पनी ने अपने हाथों में लेकर चालू कराया तो वहां के स्थानीय लोगों, किसानों व मिल में वर्षों से काम कर रहे मजदूरों को एक बड़ी उम्मीद जगी था और उन्हें लगा था कि अब उनकी जिन्दगी की गाड़ी ठीक से गुजर सकेगी. किन्तु ठीक इसका उल्टा हो गया.

चीनी मिल चालू तो हुई और गन्ने की पेराई भी हुई लेकिन मिल प्रबंधन के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने इसे अपने पॉकेट की मिल बना दिया. इस मिल पर कुछ खास लोगों का दबदबा कायम हो गया और सभी नियमों व कानूनों की खुलेआम धज्जियां उडाई जाने लगीं.

वर्षो से काम कर रहे स्थानीय मजदूरों व सैकड़ों सीजनल कर्मियों को पिछले वर्ष हटाये जाने का मामला अभी ठण्डा भी नहीं हुआ था कि इस वर्ष भी एक दर्जन के करीब वैसे कर्मियों को हटा दिया गया जो मिल के अन्दर मची लूट का विरोध करते थे.जानकार बताते हैं कि सुगौली मिल में अपनी सेवा दे रहे आनन्द सिंह, दिलीप सिंह, रामपुकार राउत, उदय तिवारी, सौरभ रंजन, जेपी महतो,मनोज सिंह,खुर्शीद आलम,जेपी ठाकुर व शैलेन्द्र सिंह को इस बार इस लिए जीएम ने हटा दिया है कि इनलोगों ने कम्पनी को लगाये जा रहे लाखों के चूने व नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियों विरोध किया था.इसके अलावा मिल के स्थायी कर्मी मृत्युन्जय कुमार को निलंबित कर दिया गया है. हालांकि इसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ और अधिकारियों को इस की जानकारी भी दी गयी किन्तु कोई कार्रवाई नही हुई.स्थानीय समाज सेवी व सर्व मानव कल्याण फाउण्डेशन के सचिव सैयद शमीम अख्तर उर्फ शहवर्दी बताते हैं कि मिलप्रबंधन की नीति पर सवाल खड़ा करते हैं और कहते हैं कि खुलेआम कम्पनी अधिनियम की धज्जिया उड़ायी जा रही है और इसमें कार्यरत ईमानदार व योग्य मजदूरों व कर्मियों को लगातार प्रताड़ित किया जाता है.वे और भी कई आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि कर्मियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. मिल से निकलने वाला दुषित पानी, इथिनौल व ब्वोयलर से निकलने वाला धुआ मानव जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करने लगा है. दूषित पानी व इथिनौल से एक तरफ कनिहार,अण्डा टोला,क्रुम टोला,बेला टोला आदि गावों के किसानों की फसलें बर्बाद हो गयी और पोखरों में पाली गयी मछलियां मरने लगी.इसका धुंआ भी आस पास की गांवों में पहुंचने लगा और लोगों की आंगन में राख गिरती है.इसी तरह का हाल मोतिहारी व चकिया में स्थापित चीनी मिल का है. किसानों के साथ-साथ मिल मजदूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना मोतिहारी चीनी मिल प्रबंधक की आदत सी बनी हुई है.यहां भी करीब 600 मजदूर जहां भुखमरी के के कगार पर हैं वहीं गन्ना उत्पादकों का करीब दस करोड़ रूपये मिल मालिक के यहां बकाया है.

पूर्व में प्रत्येक वर्ष गन्ने की पेराई के मौके पर किसानों को मिल प्रबंधन द्वारा मिल चलाने का आश्वासन दिया जाता था और इसे चालू भी किया जाता था किन्तु ब्वॉयलर खराब होने की समस्या बताकर फिर बन्द कर दिया जाता था किन्तु इस बार यह भी नहीं हुआ. न तो कर्मियों की आर्थिक तंगी की खबर ली जाती है और न ही किसानों का बकाया भुगतान करने की दिशा प्रबंधक द्वारा कोई ठोस निर्णय लिया जाता है.पिछले माह आर्थिक तंगी से जूझ रहे कार्यरत मजदूरों ने कई दिनों का अनशन भी किया और उनके परिजनों ने सामूहिक रूप से भिक्षाटन भी किया किन्तु कोई कार्रवाई नही हुई.यही स्थिति चकिया चीनी मिल की है और इसकी जमीन को अवैध तरीके से अतिक्रमित कर लिया गया है. इस मिल के पास करीब 600 एकड़ अपनी जमीन है. बीते दिनों चकिया कृषि समिति के प्रांगण में चकिया चीनी मिल बचाओ किसानों, मजदूर संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता नागेन्द्र सहनी ने की. इस बैठक में चकिया चीनी मिल के तत्कालीन प्रबंधक विष्णुकान्त गुप्ता के द्वारा चीनी मिल को नुकसान पहुंचाने व इसकी जमीन की बिक्री करने का कड़ा विरोध किया गया. मिल प्रशासन की मनमानी के खिलाफ आगामी 19 फरवरी को एक दिवसीय धरना चकिया अनुमण्डल कार्यालय के समक्ष करने का निर्णय लिया गया. बैठक में रामचन्द्र प्रसाद कुशवाहा, मुकेश पटेल, जय प्रकाश यादव, भिखारी गिरी, सुनिल ठाकुर, दिनेश पाठक, राज किशोर सिंह, प्रभू बैठा, भरत दास, नरेश भगत, हरेन्द्र साह, सिकन्दर यादव, सुनिल कुमार सहनी, कमलेश नारायण सिंह, प्रमोद कुमार, वकील सिंह सहित अन्यलोग मौजूद थे.

दूसरी तरफ पश्चिमी चम्पारण जिले के नरकटिया गंज की चीनी मिल प्रबंधक की मनमानी व मजदूरों के शोषण का मामला तो सालों भर सुर्खियों में रहता है.मिल के सीजनल कर्मचारी व गन्ना लिपिक विनोद कुमार पर जिस तरह से पिछले वर्ष झुठा आरोप लगाकर बाहर कर दिया गया वह किसी से छिपा हुआ नहीं है. सब से चौंकाने वाला तथ्य तो यह है कि भारत सरकार के कृषि मंत्री राधामोहन सिंह मोतिहारी के सांसद हैं और इनके द्वारा भी इस समस्या के समाधान के लिए कोई पहल नही किया गया जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक हो रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

मनमाने होल्डिंग टैक्स से गया वासियों मे उबाल

सुनील सौरभ

गया नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स में मनमाने तरीके से वृद्धि को लेकर पुन: गया वासियों मे उबाल है. आधा दर्जन से अधिक सामाजिक संगठनों ने राज्य के मुख्यमंत्री समेत नगर विकास से संबंधित उच्च अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर गया नगर निगम के स्व-कर निर्धारण प्रपत्र 2014-15 का विरोध जताया है. इस स्व-कर निर्धारण में गया शहर की 'अन्य सड़क की श्रेणी' सड़कों एवं गलियों को मुख्य सड़क की श्रेणी में लाकर बारह गुना होल्डिंग टैक्स का निर्धारण कर दिया गया है. गया नगर निगम द्वारा नये सिरे से किये गये इस भवन कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के साथ-साथ अजीबोगरिब पद्धति भी अपनायी जा रही है, जिससे भवन मालिकों को कम से कम छह गुना अधिक होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना होगा. लोगों की आपत्ति इन्ही बातों को लेकर है. इससे पूर्व भी बिहार के विभिन्न नगर निकायों द्वारा भवन कर में की गईं अन्यायपूर्ण वृद्धि पर जब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश का ध्यान आकृष्ट कराया गया था तो जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए होल्डिंग टैक्स मे वृद्धि के प्रस्ताव पर तत्काल रोक लगाकर भवन कर निर्धारण के लिए कर बोर्ड बनाने का निर्देश उन्होंने दिया था. कर बोर्ड का प्रावधान पूर्व से ही बिहार नगर पालिका अधिनियम की धारा 138(1) में है, जिसमें आम सहमति से भवन कर का निर्धारण करने का निर्देश दिया गया है. तमाम नियमों अधिनियमों के बावजूद गया नगर निगम के द्वारा मनमाने तरीके से होल्डिंग टैक्स का निर्धारण करने से गया वासियों मे आक्रोश है. दुर्भाग्य है कि गया नगर निगम के निर्वाचित वार्ड आयुक्त भी इस संबंध में जानकारी नहीं रखने के कारण चुपचाप हैं.

अधिकांश वार्ड पार्षद गया नगर निगम में अपने मतलब के कार्यों तथा 'मौज मस्ती' के कारनामे में लिप्त हेाकर रह गये हैं. गया शहर की समस्याओं से वार्ड पार्षदों को बहुत मतलब नहीं रह गया है. गया नगर निगम के बोर्ड से पास प्रस्ताव को कार्य रूप देने वाले नगर आयुक्त से अपने मतलब के कार्यो को कराने में ही वार्ड पार्षद बड़ी बात समझ लेते हैं. जनप्रतिनिधि के अधिकार व कर्तव्य से ऐसे वार्ड पार्षदों का कोई लेना-देना नहीं है. नतीजा है कि गया वासियों को छह से पन्द्रह गुना अधिक होल्डिंग टैक्स देने का स्व-कर प्रपत्र भरने को विवश किया जा रहा है. वार्ड पार्षदों को बढ़े होल्डिंग टैक्स से परेशान गया वासियों की समस्याओं से सच कहें तो कोई लेना-देना नही रह गया है. फलत: गया के विभिन्न समाजिक संगठनों, सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, प्रवृद्ध नागरिक परिषद, साउथ बिहार इन्ड्रस्ट्रीज एसो-सीएशन, गया मोबाइल एसोसिएसन, गया बार ऐसोसिएशन, नगर विकास परिषद आदि ने होल्डिंग टैक्स के मनमाने निर्धारण के खिलाफ आवाज उठाई है. इन संगठनों ने राज्य के मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, नगर विकास विभाग के संबंधित इच्च अधिकारियों को लिखित रूप से आवेदन देकर जनसामान्य के हित में होल्डिंग टैक्स निर्धारण की वर्तमान प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की हैं. गया शहर का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जब यहां के निर्वाचित जनप्रतिनिधि डॉ. प्रेम कुमार राज्य के नगर विकास विभाग के मंत्री थे, तब भी होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी मनमाने तरीके से की गयी थी, गया वासियों की तमाम मिन्नतों के बाद भी डॉ. प्रेम कुमार ने होल्डिंग टैक्स के मामले में गया वासियों को सहयोग नहीं किया गया था.

सेंट्रल बिहार चैम्बर आफ कॉमर्स के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया आये और उनका ध्यान इस मामले पर आकृष्ट कारया गया तो उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए होल्डिंग टैक्स की वृद्धि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए कर बोर्ड गठन करने का निर्देश दिया था. तब जाकर गया वासियों को राहत मिल सकी था. लेकिन अब पुन: गया नगर निगम के निर्वाचित वार्ड पार्षदों को तकनीकी जानकारी नहीं रहने तथा गया वासियों को नये होल्डिंग टैक्स की प्रक्रिया से भविष्य में आने वाली समस्याओं की तरफ सोच नहीं रखने के कारण गया वासियों पर भवन कर के रूप में भारी आर्थिक भार वहन करने को विवश किया जा रहा है.

सेंट्रल बिहार चैम्बर आफ कॉमर्स के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया आये और इनका ध्यान इस मामले पर आकृष्ट कारया गया तो उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए होल्डिंग टैक्स की वृद्धि को तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए कर बोर्ड गठन करने का निर्देश दिया था. तब जाकर गया वासियों को राहत मिल सकी था. लेकिन अब पुन: गया नगर निगम के निर्वाचित वार्ड पार्षदों को तकनीकी जानकारी नहीं रहने तथा गया वासियों को नये होल्डिंग टैक्स की प्रक्रिया से भविष्य में आने वाली समस्याओं की तरफ सोच नहीं रखने के कारण गया वासियों पर भवन कर के रूप में भारी आर्थिक भार वहन करने को विवश किया जा रहा है. अन्य राज्यों के नगर निकायों मे भवन की दशा एवं भवन कितना पुराना है, उसके अनुसार भवन कर में छूट का प्रावधान है. लेकिन गया नगर निगम मे यह प्रावधान लागू नहीं है. इसी प्रकार किसी भी श्रेणी की सड़क पर स्थित बहुमंजिली इमारतों मे भूतल की तुलना में उपर के अन्य तलों का वार्षिक किराया मूल्य कम होता जाता है. परन्तु गया नगर निगम के वर्तमान स्व-कर प्रक्रिया में सभी तलों का समान रूप से होल्डिंग टैक्स लेने का प्रावधान किया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम स्व कर निर्धारण 2014 की प्रक्रिया संबंधी विभागीय सूचना किसी भी प्रमुख समाचार पत्र मे प्रकाशित नहीं की गयी. गया नगर निगम द्वारा स्व-कर निर्धारण प्रपत्र 2014-15 बिहार नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत वितरित किया गया है, प्रपत्र में इसका उल्लेख नहीं है.

समाचार पत्रों मे छपे समाचार से ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि देरी से प्रपत्र जमा करने वालों पर नगर पालिका अधिनियम के तहत आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा. परन्तु दिये गये प्रपत्र मे जमा करने की अंतिम तिथि एवं दण्ड की राशि आदि की जानकारी नहीं दी गयी है. पिछले दो वर्षो से गया नगर निगम तथा यहां के निर्वाचित प्रतिनिधि- पदाधिकारी अपने-अपने कारनामों, पद से हटाओ, पद पर बैठाओ गया नगर निगम को अपनी जागीर समझ कर ही कार्य करते रहे हैं. गया शहर की समस्याओं, विकास से कोई लेना देना नही रहा. इन्ही सब बातों को देखते हुए शहर के विभिन्न संगठनों ने होल्डिंग टैक्स के मामले मे आगे आकर विरोध व जन आन्दोलन कर मन बनाया है. संगठनों के लोगो ने बताया है कि यदि इस मनमाने होल्डिंग टैक्स को वापस नहीं लिया गया तो गया नगर निगम के पदाधिकारियों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ अभियान चलाया जायेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त ख़बरें

चला स्वच्छता अभियान

पूर्वी चम्पारण जिले के अरेराज नगर पंचायत में बसंत पंचमी को लेकर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया. नप अध्यक्षा पूर्णिमा देवी के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान में शिव भक्तों के पड़ाव स्थलों, मुख्य मार्गो की सफाई की गयी. नप अध्यक्षा ने बताया कि शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो,इस बाबत हर तरह की तैयारी की गयी है. उन्होंने बताया कि पड़ाव स्थलों, मुख्य मार्ग, अरेराज चौक से शिव मंदिर तक तथा नगर क्षेत्र में सफाई की गयी. मौके पर वार्ड पार्षद मंटू दूबे, अशोक पांडेय, बंगाली राय, मुन्ना तिवारी, मो. आजाद, विजय शर्मा, ई. विजय तिवारी, चंदन पांडेय, न्यास के उपाध्यक्ष विनय बिहारी वर्मा उपस्थित थे.

एसएसबी ने लगाया शिविर

पूर्वी चम्पारण जिले के घोड़ासहन में एसएसबी बड़हरवा द्वारा समाजिक चेतना अभियान के तहत पशु रोग व कृषि रोग एवं मानव स्वास्थ्य संबंधित रोगों के प्रति जागरूकता लाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में डॉक्टर ए.के.सिकदार के द्वारा बीमार लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गयी और इनके बीच दवा का वितरण किया गया. डॉ. सी.बी.सिंह ने पशु को ठंढ से बचाने एवं दूध बढ़ाने का गुर पशु पालकों को सिखाया. वहीं आर.बी.शर्मा ने मशरूम की खेती करने की सलाह दी एवं वर्तमान कृषि रोगों से संबंधित जानकारी दी. मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविन्द कुमार गुप्ता, सहायक सेनानायक आर.के.सिंह, मुखिया हरेन्द्र प्रसाद यादव, दिनबंधु राम, सब-इंस्पेक्टर महेश कुमार जाट, अविनाश कुमार सिंह सहित दर्जनों एसएसबी के जवान एवं ग्रामीण उपस्थित थे.

– इंतेज़ारुल हक़

एसडीओ के आश्वासन पर टूटा अनशन

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के परबत्ता प्रखंड में एमओ कार्यालय के समक्ष करना गांव में राशन केरोसिन वितरण कराने को लेकर जदयू जिला महासचिव मुकेश कुमार के नेतृत्व में जारी अनशन एसडीओ संतोश कुमार के आश्वासन पर समाप्त कर दिया गया. एसडीओ संतोष कुमार के अनशन स्थल पर पहुंचते ही भुख हड़ताल में शामिल मुकेश कुमार सिंह, जवाहर सिंह, नवीन कुमार, शंकर सिंह, बच्ची लाल सिंह आदि ने कहा कि करणा गांव का राशन व केरोसिन करणा गांव में ही वितरण हो. अनशनकारी ने कहा कि करणा गांव वालों को राशन व केरोसिन लाने के लिए परबत्ता जाना पड़ता है जिसकी दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है. जिस कारण लोगों का काफी परेशानी होती है. एसडीओ संतोष कुमार, बीडीओ डॉ. कुन्दन, सीओ शैलेन्द्र कुमार, थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार, एमओ मंजीत महेश्वरी ने बारी-बारी से भूख हड़ताल में शामिल लोगों को समझाया-बुझाया. एसडीओ ने भूख हड़ताल में शामिल लोगों को समझाते हुए कहा कि 1 या 2 महीने के बाद नये डीलरों की रिक्तियां भरी जायेंगी जिसमें करणा गांव में एक नया डीलर बना दिया जायेगा. तत्काल वर्तमान पैक्स अध्यक्ष को जनवितरण का भार मिलेगा जो केएमडी कॉलेज के पास अपनी जमीन पर दुकान बनाकर वितरण करेंगे. लेकिन इस कार्य के लिए समय लगेगा. लेकिन अनशन में शामिल लोगों का कहना था कि जब तक हमारी बातें नहीं मानी जायेगी तक तक हम भूख हड़ताल पर रहेंगे. लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद वे लोग मान गये. भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को एसडीओ ने जूस पिलाकर हड़ातल समाप्त कराया. इस प्रकार भूख हड़ताल एसडीओ के आश्वासन पर समाप्त कर दिया गया.

बोतल फोड़ो व शराब छोड़ो रैली

गोगरी अनुमंडल में महिलाओं ने बोतल फोड़ो व शराब छोड़ो रैली निकाली. महिलाओं ने शराब के बढ़ते प्रचलन के विरोध में गोगरी में महिलाओं ने एकजुट होकर इसके विरोध में अपना मोर्चा खोल दिया. राष्ट्रीय युवा ब्रिगेड व दुर्गा दस्ता की महिलाओं ने बोतल फोड़ो, शराब छोड़ो जैसे नारों के साथ रैली निकाली. राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड की सचिव अनीता देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने गोगरी शिव मंदिर से रैली निकालकर जमालपुर बाजार के विभिन्न चौक-चौराहे होते हुए नगर का भ्रमण किया और शराब सेवन के विरोध में नारे लगाये. महिलाओं ने अनुमंडल मुख्यालय पहुंचकर वहां शराब की बोतल फोड़कर अपना विरोध प्रकट किया. इस अवसर पर सचिव अनीता देवी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शराब लोगों को बर्वाद कर देती है. वहीं रुकमणि देवी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को शराब की लत जाये तो उसके परिवार को इजड़ने से कोई रोक नहीं सकता है. महिलाओं ने बारी-बारी से सभा को संबोधित कर नशा करने वालों का जमकर विरोध किया. इस मौके पर मीरा कुमारी, लाली देवी, शांति देवी, किरण देवी, रानी देवी, अर्चना देवी सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद थीं.

विकास को कोई रोक नहीं सकता

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के सर्किल नंबर एक में सांसद चौधरी महबूब अली कैसर व परबत्ता से लोजपा की पूर्व प्रो. सुहेली मेहता ने क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को जाना. इनके साथ ही एनडीए गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे. सांसद ने लोगों की समस्या सुनने के बाद कहा कि क्षेत्र में खेल के साथ ही अन्य विकास गतिविधियों पर बल दिया जायेगा. लोजपा नेत्री प्रो. सुहेली मेहता ने बीरवास में स्थानीय लोगों की दान की जमीन पर घोषित ओपी के लिए सांसद से भवन की मांग की. जिस पर इन्होंने सांसद निधि से सहयोग का भरोसा दिया. लोगों ने देवठा मैदान में स्टेडियम और ज्ञान मंदिर पैंकांत स्कूल में भवन बनाने की मांग की. इस पर सांसद ने कहा कि स्टेडियम में तो अधिक राषि की जरूरत होती है. परंतु वे यथा संभव मदद करेंगे. देवठा मैदान में न्यू इलेवन स्टार क्लब देवठा द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर फुटबाल मुकाबले का आयोजन किया गया. मौके पर परबत्ता से लोजपा के विधायक प्रत्याशी रही सुहेली मेहता भी साथ थी. मैच में मुख्य निर्णायक रामसेवक सिंह एवं चन्द्रशेखर शर्मा माजूद थे. मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर भाजपा के जिला अध्यक्ष रामानुज चौधरी, लोजपा जिलाध्यक्ष कपिलदेव यादव, पूर्व विधायक सुनीता शर्मा, सांसद प्रतिनिधि नीतीश कुमार सिंह गोगरी, मों. जफर अली, मो मासूम, पैंकात मुखिया सिकन्दर शर्मा, पिपरापांती के पूर्व मुखिया क्षत्री शर्मा, मुखिया विवेकानन्द साह, प्रमोद सिंह,लोजपा युवा नेता साकेत कुमार गुड्डू, जदयू के प्रदेश महासचिव गजेन्द्र कुमार सिंह, सहित बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे.■

– गीता कुमार

एक नज़र

गरीबों की हो रही उपेक्षा

लोजपा नेता सह बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी सवीह अहमद ने कहा कि सूबे की सरकार गरीबों की उपेक्षा कर रही है. सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड के कोईली में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम के मौके पर लोजपा नेता ने तकरीबन तीन दर्जन से अधिक गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया. इस दौरान कहा कि सरकारी स्तर पर गरीबों को किसी प्रकार की मदद नहीं की जा रही है. जिसके कारण सर्दी के प्रकोप को झेलना गरीबो के लिए मुश्किल साबित हो रहा है. कार्यक्रम में लोजपा जिलाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ झा उर्फ मोहन झा, नानपुर प्रखंड अध्यक्ष मुकेश कुमार पासवान, राजेश राज, रघुनाथ पासवान, चंदन पासवान व रामबाबू पासवान समेत अन्य थे.

–विकास कुमार

पुण्य तिथि मनायी

सीतामढ़ी शहर के गांधी मैदान में क्षत्रीय चेतना मंच के तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. महाराणा प्रताप के पुण्य तिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज के प्राचार्य डॉ ओम प्रकाश सिंह एवं रविज कॉमर्स के संचालक रवि सिंह को बेहतर कार्य को लेकर सम्मानित किया गया. मंच के संयोजक विशाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में रालोसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन कुमार सिंह, सहकारिता नेता रामबाबू सिंह, युवा जदयू अध्यक्ष राहुल सिंह, शिवहर युवा जदयू जिलाध्यक्ष विशाल गौरव, विवेक सिंह, अभिषेक ठाकुर, श्याम गुप्ता, आनंद शाही व वीरेंद्र सिंह समेत अन्य थे. कार्यक्रम के दौरान राजद युवा नेता सुधीर कुंवर व कुश सिंह, ने कपरौल रोड में महाराणा प्रताप के नाम पर एक सामुदायिक भवन निर्माण के लिए जमीन दान देने की घोषणा की.

– ब्रजेश

सर्विस सेंटर का उद्घाटन

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय में बालाजी मोटर नामक ऑटो सेल एंड सर्विस केंद्र का उद्घाटन जदयू के वरीय नेता राजेश चौधरी ने फीता काट कर किया. मौके पर युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप राय, सरपंच संजीव कुमार, पैक्स अध्यक्ष सरोज राय, मो इलियास, केदार राय, चंद्रशेखर प्रसाद यादव, चितरंजन सिंह, रेयाज खां व सेंटर के संचालक रामा शंकर राय समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे.

सदस्यता को शिविर का आयोजन

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित थाना चौक पर भाजयुमो के तत्वावधान में सदस्यता अभियान शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन जिला प्रभारी मनोज तिवारी, जिलाध्यक्ष कार्तिकेश झा, जिला सदस्यता समन्वयक विनोद कुमार ने संयुक्त रूप से किया. शिविर में करीब ढाई सौ लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. अभियान को गति देने को लेकर करीब एक दर्जन शक्ति केंद्र की स्थापना की गयी है. मौके पर विनोद कुमार, युगल किशोर गुप्ता, पवन कुमार उपमन्यु, ज्योति कुमार मिश्र, अरुण कुमार सिंह, सुधीर रंजन वर्मा, जितेंद्र कुमार, अरुण कुमार गुप्ता, चंदन यादव, अजय कुमार व अविनाश कुमार सिंह समेत अन्य थे.

– विभा

भाजपा नेत्री ने किया कंबल वितरित

सीतामढ़ी जिले के पुपरी अनुमंडल मुख्यालय समेत सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के अलग -अलग स्थानों पर भाजपा उपाध्यक्ष डॉ. कुमकुम सिन्हा ने गरीबों के बीच कंबल वितरित किए. इस दौरान उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार संवेदनाहीन हो चुकी है. सत्ता की चाह ने सरकारी तंत्र को जनता से विमुख कर दिया है. कड़ाके की ठंढ में एक ओर गरीबों का जीना मुहाल है तो दूसरी ओर सूबे की सरकार नमो दहशत से सरकार बचाये रखने की फिराक में लगी है. दर्जनों गरीबों के बीच कंबल का वितरण के दौरान उपाध्यक्ष ने कहा कि अब बिहार में अगली सरकार हर हाल में भाजपा की होगी. कार्यक्रम में दर्जनों पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य लोग मौजूद थे.

– गोविंद

शुरू हुई टेलीमेडिसिन सेवा

पूर्वी चम्पारण जिले के छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर के निकट स्थित रहमानिया मेडिकल सेन्टर में टेलीमेडिसीन सेवा आज से शुरू हो गयी. इस सेवा के माध्यम से उच्च स्तरीय चिकित्सा का लाभ मरीजों को तो मिलेगा ही साथ ही परामर्श के लिए उन्हें बनारस नहीं जाना पड़ेगा. वाराणसी के जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल ने रहमानिया मेडिकल सेन्टर को अपना सेन्टर बनाया है. कटे होठ और तालू एवं जलने से विकृत हुए मरीजों की बेहतर सेवा यहां हो सकेगी. इसकी जानकारी देते हुए रहमानिया सेन्टर के संचालक डॉ. तबरेज अजीज, डॉ. साजिया तरन्नूम व डॉ. एमके सिंह ने बताया कि वीडीओ कॉन्फ्रेसिंग का भी लाभ मिलेगा और स्पीच थेरोपी के लिए मरीजों को वाराणसी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. पूरे प्रोजेक्ट की शुरूआत क्लेट मरीजों को स्पीच थेरेपी प्रदान के उद्देश्य से की गयी थी. दूर-दराज के मरीज अब घर बैठे ही अथवा साइबर कैफे में जाकर वाराणसी केन्द्र से स्पीच थेरेपी प्राप्त करने में सक्षम होंगे. मोतिहारी अथवा आसपास के मरीजों को प्लास्टिक सर्जरी के एक्पोर्ट से राय लेने के लिए तीन दिन और सैकड़ों रूपये खर्च कर वाराणसी या अन्य शहरों में नही जाना पड़ेगा और यही यह काम हो जायेगा.

डीएम का जनता दरबार

जिलाधिकारी जितेन्द्र श्रीवास्तव ने आज सर्वाधिक माओवाद प्रभावित क्षेत्र पकड़ीदयाल में जनता दरबार लगाया और पीड़ितों की फरियादें सुनी.दरबार में उन्होंने जनता की शिकायत पर एक तरफ जहां बड़का गांव पंचायत के पंचायत सचिव को निलंबित करने का आदेश दिया तो दूसरी तरफ पीएचईडी के कनीय अभियंता रामाश्रय यादव के खिलाफ थाना में मुकदमा दर्ज करने का फरमान जारी किया. उन्होंने डुमरबाना वार्ड नम्बर आठ निवासी मराक्षो कुंवर की शिकायत पर राजस्व कर्मचारी के दलाल नगीना राय को भी नही बख्शा और शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेजने की हिदायत दी. नगीना का आरोप था कि दाखिल खारिज के लिए तीन हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है और नहीं देने पर इसे परेशान किया जा रहा है. जनता दरबार में डीएम के समक्ष उप प्रखण्ड प्रमुख उमाशंकर राय ने पंचायत सचिव श्री नारायण सिंह व ओम प्रकाश श्रीवास्तव पर सोलह लाख रुपये का गबन करने का आरोप लगाया जिसे डीएम ने गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया. मौके पर अनुमण्डल पदाधिकारी शैलेश कुमार, श्रम अधीक्षक संजीव कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी रामानन्दन प्रसाद, मध्याह्न भोजन के प्रभारी जय चन्द्र श्रीवास्तव, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चित्रगुप्त बैठा समेत सभी विभागों के अधिकारी व प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे.■

– इन्तेजारूल हक

इनके अलावा कुछ ऐसे भी चेहरे हैं, जो जिले की राजनीति में सक्रिय रहते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. इनमें पूर्व राजद सांसद सीताराम यादव की पुत्र वधु उषा किरण, जिला परिषद सदस्य सरिता यादव, भाजपा उपाध्यक्ष डॉ. कुमकुम सिन्हा, किरण श्रीवास्तव, जदयू की किरण गुप्ता व आरती प्रधान समेत अन्य शामिल है. पूर्व सांसद की पुत्र वधु उष किरण सीतामढ़ी जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं. जबकि जिला परिषद सदस्य सरिता यादव अपने पति महेंद्र सिंह यादव के साथ जन समस्याओं के निदान को लेकर संघर्ष कर रही है.

सीतामढ़ी

घर की दहलीज से निकल राजनीति में बनाया मुकाम

वाल्मीकि कुमार

वैसे तो सीताढ़ी जिले का नाम ही जगत जननी मां जानकी की जन्म स्थली के रूप में चर्चित है. परंतु जिले की महिलाओं का जज्बा भी अपने आप में कम नही है. वर्ष 1972 में जिले का दर्जा मिलने के बाद यहां की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी. बाद में शिवहर जिले को सीतामढ़ी से अलग कर दिया गया. बावजूद इसके सीतामढ़ी की आधी आबादी ने अपना राजनीतिक संघर्ष जारी रखा. सूबे बिहार में जब राजद शासन के खिलाफ राजनीतिक गोलबंदी ने जोर पकड़ी तब महिलाओं को राजनीति में स्थान मिला. इसी दौर में रुन्नीसैदपुर से जनतादल यूनाइटेड के टिकट पर गुड्डी देवी तो बेलसंड से सुनीता सिंह चौहान के अलावा बाजपट्टी से डॉ. रंजू गीता को चुनाव लड़ने का मौका मिला. राजनीतिक बदलाव का आलम रहा कि तीनों को विधानसभा तक पहुंचने में कामयाबी मिल गयी. इनके अलावा तत्कालीन बथनाहा विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2005 में लोजपा की टिकट पर नगीना देवी को भी विधायक बनने का मौका मिला था. अब इन महिला विधायकों की सफलता पर चर्चा करना आवश्यक लग रहा है.

रुन्नीसैदपुर से जदयू विधायक गुड्डी देवी एक ऐसी प्रतिनिधि के रूप में लोगों के बीच उभरीं जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी. परंतु पति राजेश चौधरी के

आरती प्रधान

डॉ. कुमकुम सिन्हा

डॉ. रंजू गीता

गुड्डी देवी

किरण गुप्ता

किरण श्रीवास्तव

नगीना देवी

सरिता यादव

सुनीता सिंह चौहान

ऊषा किरण

प्रधान समेत अन्य शामिल है. पूर्व सांसद की पुत्र वधु उष किरण सीतामढ़ी जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं. जबकि जिला परिषद सदस्य सरिता यादव अपने पति महेंद्र सिंह यादव के साथ जन समस्याओं के निदान को लेकर संघर्ष कर रही है. भाजपा की डॉ. कुमकुम सिन्हा पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के अलावा पुपरी लायंस क्लब एक्टीव का भी कमान संभाल रही है. वही कुशल नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण किरण श्रीवास्तव जिले में पार्टी संगठन को मुकाम तक लाने में अहम भूमिका निभाती रही है. जदयू की किरण गुप्ता पिछले तकरीबन डेढ़ दशक से जिले की राजनीति में अहम योगदान देती रही हैं, तो सोनबरसा की आरती प्रधान भी पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर लगातार प्रयासरत रही हैं. इनके अलावा कई अन्य महिलायें भी है जो जिले की राजनीति में बढ़ कर योगदान देती आ रही हैं.

अब चुनावी मौसम में पार्टी संगठन का झंडा लेकर शहर से गांव तक अलख जगाने वाली इन महिलाओं को आगामी विधानसभा चुनाव में मौका मिलेगा अथवा नही कहा नहीं जा सकता है. परंतु चल रही चर्चाओं पर भरोसा करें तो इनमें अधिकांश ने अपने स्तर से चुनावी समर में आने का मन बना चुकी है. अलग–अलग क्षेत्रों से दावेदारी को लेकर कमोवेश सभी ने जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक अपनी पहुंच बनाने का प्रयास भी शुरू कर दिया है. वैसे चुनावी चर्चाओं को फिलहाल विशेष तरजीह नहीं दी जा सकती. पहला कारण यह है कि अभी विधानसभा चुनाव का वक्त है. गठबंधन का फाइनल निर्णय भी आना बाकी है. विधानसभा से पहले विधान परिषद के स्थानीय निकाय का चुनाव भी होना है. लेकिन महिलाओं की राजनीतिक कदम अगर डगमगायी नहीं तो किसी भी क्षेत्र के अन्य संभावित प्रत्याशियों के लिए मुसीबत बन सकती है. ऐसी आशंका को ख़ारिज नहीं किया जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर नारी सशक्तीकरण को लेकर चलाया गया अभियान सीतामढ़ी में हाल के दशक में कारगर साबित होता रहा है. महिलाओं में जागरूकता को लेकर चलाये गये अभियान का नतीजा जिले की राजनीति में साफ झलक रहा है. वर्तमान में सीतामढ़ी जिले के कुल 8 में से तीन विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व की कमान महिला जनप्रतिनिधियों के हाथ में है. इनमें एक डॉ. रंजू गीता बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री तो गुड्डी देवी व सुनीता सिंह चौहान बतौर विधायक मौजूद हैं. जबकि कई अन्य जिले की राजनीति में वर्षो से सक्रिय रह कर मुकाम पाने की राह देख रही हैं....

राजनीतिक प्रयास के साथ उनकी खुद की मेहनत ने सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया. आलम हुआ कि वर्ष 2005 के बाद वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में लगातार सीट बचाये रखी. बेलसंड से सुनीता सिंह चौहान की जीत का श्रेय भी उनके पति राणा रंधीर सिंह चौहान की राजनीतिक सूझ–बूझ को दिया जाता है. बाजपट्टी की जदयू विधायक डॉ. रंजू गीता की राजनीति जिला परिषद सदस्य के रूप में शुरू हुई. बाद में धन–बल की राजनीति का आलम रहा कि जिला परिषद अध्यक्ष पद तक पहुंची. राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बढ़ते कदम ने उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया जहां वे मंत्री पद पाने में कामयाब रहीं. पूर्व विधायक नगीना देवी का राजनीतिक जीवन भी उनकी खुद की मेहनत का नतीजा बताया जाता है. समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर सर्वप्रथम बतौर जिला परिषद सदस्य के रूप में क्षेत्र के विकास की कमान थामने वाली नगीना देवी को वर्ष 2005 में लोजपा के टिकट पर बथनाहा से भाग्य आजमाने का मौका मिला था. तब उनको सफलता भी मिली थी. अब एक बार फिर उक्त पूर्व से लेकर वर्तमान तक की सभी महिला प्रतिनिधि आगामी विधानसभा चुनाव के समर में कमर कसने को तैयार है. अबकी बार सूबे में चल रही गठबंधन की राजनीति के कारण कुछ को टिकट मिलने तो कुछ को टिकट न मिलने का अंदेशा अभी से ही सताने लगा है. वैसे चुनाव में अभी वक्त है. पार्टी गठबंधन का अंतिम निर्णय आने में विलंब है.

इनके अलावा कुछ ऐसे भी चेहरे हैं, जो जिले की राजनीति में सक्रिय रहते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. इनमें पूर्व राजद सांसद सीताराम यादव की पुत्र वधु उषा किरण, जिला परिषद सदस्य सरिता यादव, भाजपा उपाध्यक्ष डॉ. कुमकुम सिन्हा, किरण श्रीवास्तव, जदयू की किरण गुप्ता व आरती

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

02 फरवरी–08 फरवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

पूर्व डीजीपी बृजलाल भाजपा में शामिल, कई और आएंगे

भाजपा में शामिल होने की होड़, पार्टियों में भगदड़

प्रभात रंजन दीन

दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक भाजपा ने विपक्षी दलों को परेशान कर रखा है. हर दिन नए–नए समीकरण सामने आ रहे हैं और विपक्ष हतप्रभ हो जा रहा है. दिल्ली में किरन बेदी और शाजिया इल्मी को पार्टी में शामिल कर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को चौंकाया तो कृष्णा तीरथ को शामिल कर कांग्रेस को हतप्रभ किया. बंगाल और बिहार में भी भगदड़ का आलम है. इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों को परेशान कर रखा है. समाजवादी पार्टी के कई विधायकों के भाजपा से सीधे सम्पर्क में रहने की खबर है. दूसरी तरफ जिस पूर्व पुलिस अधिकारी के बसपा में शामिल होने की चर्चा थी, उन्हें भाजपा में शामिल कर मायावती को करारा झटका दिया गया. उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक बृजलाल पिछले दिनों भाजपा में शामिल हो गए. बृजलाल के साथ ही यूपी पुलिस में डीआईजी रहे ज्ञान सिंह और बसपा नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह भी भाजपा में शामिल हुए. बृजलाल को ढोल, नगाड़े और समर्थकों की जोरदार नारेबाजी के बीच भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने पार्टी की सदस्यता दिलाई. बृजलाल

के स्वागत के लिए भाजपा कार्यालय में उमड़ी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ बसपा के साथ–साथ सपा को भी अपना संदेश दे रही थी. कार्यकर्ताओं के उत्साह का आलम ऐसा था कि बृजलाल को माला पहनाने और शुभकामना दे रहे समर्थकों को काबू करने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष डा. लक्ष्मीकांत बाजपेयी को माइक संभाल कर मंच से नीचे उतरना पड़ा.

पूर्व डीजीपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा और उनके सिद्धांतों के कारण ही उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया. प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने यह माना कि बृजलाल के भाजपा में शामिल होने से उत्तर प्रदेश की सियासत में परिवर्तन की एक नई शुरुआत हो रही है. भाजपा को चुनाव में इसका फायदा मिलेगा और यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी. बृजलाल के साथ ही भाजपा में शामिल हुए बसपा नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह लगभग 20 साल तक बसपा में संगठन की कई अहम जिम्मेदारी निभाते रहे. वे मिर्जापुर से विधायक रहे हैं. उनके जरिए भाजपा सोनभद्र, मिर्जापुर इलाके में बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ ही कुर्मी समाज को अपनी ओर खींचने की रणनीति पर भी काम कर रही है. आईपीएस ज्ञान सिंह का इस्तेमाल भी पार्टी पिछड़ा बहुल इलाकों में करने की तैयारी में है.

बृजलाल का भाजपा में शामिल होना उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा और मायावती के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. पुलिस सेवा में रहते हुए बृजलाल ने पूरे प्रदेश को विभिन्न आयामों से जाना और समझा. इसका फायदा राजनीतिक रूप से उन्हें और पार्टी दोनों को मिलेगा. बृजलाल का दलित समुदाय में ही नहीं बल्कि समग्र समुदाय में सम्मान है. खास तौर पर दलित समुदाय में उन्हें रोल मॉडल की तरह देखा जाता है. इसका खासा फायदा भाजपा को मिलेगा. किसी भी सरकार के कार्यकाल में बृजलाल की क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल किया गया. हर सरकार ने उनकी प्रशासनिक क्षमता, अपराधियों से जूझने और फिर उसे अंजाम तक पहुंचाने की प्रवृत्ति के चलते उन्हें हमेशा कानून–व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी. दलित वोट के दृष्टिकोण से देखें तो बृजलाल अनुसूचित जाति में कोरी जाति से ताल्लुक रखते हैं. राजनीतिक नजरिए से भाजपा का यह कदम पूर्वांचल में मिशन–2017 की ठोस शुरुआत माना जा रहा है. पूर्वांचल में सुल्तानपुर, गोंडा, फैजाबाद के अलावा बुंदेलखंड में भी कोरी जाति की संख्या ज्यादा है. बृजलाल को बसपा सरकार की सख्त कानून–व्यवस्था का चेहरा माना जाता था. उनकी ईमानदारी और साफगोई वाली छवि के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें 1991 में मेरठ में एसएसपी बनाया था. उन्हें समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने 1989 में इटावा का एसएसपी भी बनाया था. वह पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार में भी लखनऊ के एसपी सिटी बनाए गए थे.

30 नवम्बर को रिटायर होने के बाद से ही भाजपा ने उन्हें अपने साथ जोड़ने की पहल शुरू कर दी थी. बसपा वाले तैयारी ही करते रह गए और बृजलाल को भाजपा में शामिल करा लिया गया. रिटायर होने के बाद ही दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से बृजलाल की गोपनीय मुलाकात हुई थी और फिर केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें भाजपा में शामिल करने को हरी झंडी दे दी थी. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी भी उनके खासे करीबी माने जाते हैं. इसका दूसरा राजनीतिक पहलू यह है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो दलितों का ठोस समर्थन मिला, उसे वह अपने साथ बनाए रखना चाहती है. यही वजह है कि पार्टी की कोर टीम के साथ ही मोर्चों में भी उत्तर प्रदेश के चेहरों

(शेष पृष्ठ 18 पर)

कई और भी हैं इस राह में

भाजपा के नेता कहते हैं कि यह तो अभी शुरुआत है. अभी कई और महारथियों का आना बाकी है. पिछले दिनों मायावती से बगावत करने वाले राज्यसभा सदस्य जुगल किशोर के भी जल्दी ही भाजपा में शामिल होने की चर्चा है. पूर्व डीजीपी बृजलाल के भाजपा में आने के साथ ही अब परिवार बढ़ने का सिलसिला शुरू होगा. कई दलों के दलित तथा पिछड़े वर्ग के नेता भाजपा नेताओं के सम्पर्क में हैं और वे कुछ अंतराल में भाजपा का दामन थाम सकते हैं. जुगल किशोर के भाजपा में शीघ्र ही शामिल होने की चर्चा है. पिछले विधानसभा चुनाव तक जुगल किशोर बसपा के खासे ताकतवर नेता थे. पिछले दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती ने जुगल किशोर को किनारे लगा दिया. इसके अलावा रामचंद्र प्रधान के भी भाजपा में जाने की चर्चा है. पिछले दिनों बसपा ने दारा सिंह चौहान समेत कई नेताओं को पार्टी से निकाल दिया. इनके अलावा बसपा में कई और दलित नेता बाहर आने के लिए माकूल समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यही हाल समाजवादी पार्टी के भी अंदर है. सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि सपा के 60 से अधिक विधायक भाजपा के सम्पर्क में हैं. ■

अखिलेश यादव
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

आजम खां
नगर विकास मंत्री

विनोद सिंह
प्रभारी मंत्री, महराजगंज

कार्यालय–नगर पालिका परिषद महराजगंज

नगर पालिका परिषद महराजगंज को स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध एवं अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु नागरिकों से अपील:–

1–नगर की सम्मानित जनता से अनुरोध है कि कूड़ा निस्तारण हेतु कूड़ेदान का प्रयोग करें. कूड़ा नालियों में कदापि न डालें.
2– नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों द्वारा की गयी सफाई के उपरान्त उसको बनाये रखना आप के सहयोग से ही सम्भव है इसलिए इस सम्बन्ध में आपका सहयोग अपेक्षित है.
3– जल अमूल्य है. जल संरक्षण में आपका सहयोग अपेक्षित है. टोटी खुला न छोड़ें तथा मार्गों पर पानी न बहायें.
4– सभी व्यवसायियों एवं आम जनता से अनुरोध है कि प्रतिबंधित पॉलीथीन एवं प्लास्टिक का प्रयोग न करें.
5– नगर पालिका परिषद की सार्वजनिक भूमियों, सड़कों, मार्गों, तालाबों, नालों एवं नालियों पर अतिक्रमण न करें. इस श्रेणी की भूमियों पर यदि किसी व्यक्ति का अतिक्रमण पाया गया तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122वीं के अन्तर्गत वाद संस्थित कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी. इसके अतिरिक्त लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(2) के अन्तर्गत सुसंगत कार्रवाई की जाएगी.
6– शासन के निर्देशों के क्रम में नगर पंचायत सीमा अन्तर्गत गृहकर का रोपण किया जाना है. इस हेतु स्वकर निर्धारण सम्बन्धी प्रपत्र/फॉर्म नगर पंचायत कार्यालय से प्राप्त कर, समस्त वांछित सूचनाएं भरकर 31–01–2015 तक नगर पालिका परिषद कार्यालय में जमा कर दें, जिससे कि आपके भवन/भूखण्ड का वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित कर उसका प्रशासन कर गृहकर/सम्पत्ति कर निर्धारित किया जा सके. निर्धारित समय तक स्वकर निर्धारण प्रपत्र जमा न करने पर नगर पालिका परिषद महराजगंज द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एकतरफा रूप से किया जाएगा.

पृथ्वीनाथ गुप्ता
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
महराजगंज

रीता भारती
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
महराजगंज

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

नियम-कानून के विरुद्ध अवैध खनन हो रहा है

शिव दास प्रजापति

उत्तर प्रदेश में अवैध खनन का धंधा बेखौफ जारी है. यह धंधा माफियाओं समेत सूबे के राजनीतिकों का भी दोनंबरी धन-स्रोत बना हुआ है. सोनभद्र में तो यह नया इतिहास ही लिख रहा है. भ्रष्टाचार के आरोपी राज्य के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ लोकायुक्त जांच कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ सोनभद्र में बसपा विधायक उमा शंकर सिंह नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध खनन कर रहे हैं. संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने के मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है. घोरावल (सोनभद्र) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सपा विधायक रमेश चंद्र दुबे पर अवैध खनन और स्मारक घोटाले में पहले ही जांच चल रही है. अवैध खनन से जुड़े ऐसे ही कुछ राजनीतिक चेहरों के साथ कुछ सफेदपोशों की छानबीन की गई जिसमें एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए. ऐसे ही तथ्यों पर आधारित है यह रिपोर्टः

मजदूरों की कब्रगाह के रूप में चर्चित सोनभद्र का बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र सफेदपोश खनन माफियाओं का चारागाह बन गया है. पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिहाज से क्रिटिकल जोन में शामिल इस क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय समेत विभिन्न भारतीय कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. सूबे की सत्ता में काबिज समाजवादी पार्टी समेत भाजपा, बसपा, कांग्रेस के नेता अवैध खनन के धंधे में शामिल हैं.

आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील प्रशासन ने बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टों और उनके संचालकों द्वारा किए जाने वाले खनन की जांच क्षेत्रीय लेखपाल से कराई थी. क्षेत्रीय लेखपाल ने गत 15 सितंबर को अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों दी. इसे रॉबर्ट्सगंज (सदर) तहसील के उप-जिलाधिकारी ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अगोरी परगना के राजस्व निरीक्षक की संस्तुतियों के साथ जिला प्रशासन को सौंप दी. इस रिपोर्ट में उल्लेखित खनन पट्टाधारकों, जो अवैध खनन कर रहे हैं, के नामों की सूची पर गौर करें तो इनमें सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस के नेताओं समेत कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के रिश्तेदार तक शामिल हैं.

सपा नेता रमेश चंद्र वैश्य

उक्त रिपोर्ट में ओबरा (बारी-डाला) निवासी वरिष्ठ सपा नेता रमेश चंद्र वैश्य और उनके रिश्तेदारों का नाम भी शामिल है. रमेश चंद्र वैश्य के स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स रबिशा स्टोन प्रोडक्ट के नाम बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-4920, 4921, 4922 और 4924 की 1.75 एकड़ भूमि पर खनन पट्टा आबंटित है जो 3 जनवरी 2017 तक के लिए स्वीकृत है. क्षेत्रीय लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पट्टाधारक के स्वीकृत क्षेत्र के उत्तर दिशा में अवैध खनन किया जा रहा है और सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है. साफ है कि रमेश चंद्र वैश्य अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध खनन कर रहे हैं क्योंकि सीमा स्तंभ समेत आस-पास के क्षेत्र में होने वाले अवैध खनन की जिम्मेदारी पट्टाधारक की होती है. कुछ ऐसी ही स्थिति उनकी पत्नी विन्दो देवी के स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स शिवम स्टोन प्रोडक्ट के नाम से आबंटित खनन पट्टे की भी है. बिल्ली-मारकुंडी गांव की आराजी संख्या-4949-ख के करीब दो एकड़ में आबंटित इस खनन पट्टे की मियाद 12 दिसम्बर 2020 तक है. सपा नेता के छोटे भाई अजय कुमार के स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स अजय स्टोन प्रोडक्ट के नाम से आबंटित खनन पट्टे के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं. अजय कुमार के बारे में क्षेत्रीय लेखपाल ने लिखा है कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से दक्षिण और पश्चिम में अवैध खनन किया गया है और सीमा स्तंभ भी मौके पर नहीं पाया गया. रमेश चंद्र वैश्य के बड़े भाई सुभाष चंद्र गुप्ता और उनके भतीजे विजय वैश्य की संयुक्त स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स विजय स्टोन प्रोडक्ट के नाम से आवंटित खनन पट्टे के बारे में भी क्षेत्रीय लेखपाल की ऐसी ही रिपोर्ट है. क्षेत्रीय लेखपाल के रिपोर्ट पर उच्चाधिकारियों की मिली सहमति से यह साफ है कि सपा नेता रमेश चंद्र वैश्य और उनके रिश्तेदार उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों समेत शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर रहे हैं. जिला प्रशासन द्वारा रमेश चंद्र वैश्य और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से खनन पट्टा आवंटित किया जाना भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि वह रॉबर्ट्सगंज तहसील के सबसे बड़े बकायादारों की सूची में शामिल हैं. दो साल पहले तक रमेश चंद्र वैश्य की स्वामित्व वाली फर्म रबिशा स्टोन प्रोडक्ट पर शक्तिनगर विशेष क्षेत्र प्राधिकरण (साडा) का 18,19,320 रुपये बकाया था और 99,000 रुपये की उनसे वसूली की गई थी. अभी भी उनपर साडा के लाखों रुपये बकाया हैं. इन हालात में सपा नेता और उनके रिश्तेदारों का अवैध खनन के गोरखधंधे में संलिप्त पाया जाना जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है.

> **साफ है कि रमेश चंद्र वैश्य अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध खनन कर रहे हैं क्योंकि सीमा स्तंभ समेत आस-पास के क्षेत्र में होने वाले अवैध खनन की जिम्मेदारी पट्टाधारक की होती है. कुछ ऐसी ही स्थिति उनकी पत्नी विन्दो देवी के स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स शिवम स्टोन प्रोडक्ट के नाम से आबंटित खनन पट्टे की भी है. बिल्ली-मारकुंडी गांव की आराजी संख्या-4949-ख के करीब दो एकड़ में आबंटित इस खनन पट्टे की मियाद 12 दिसम्बर 2020 तक है.**

सपा नेता और चोपन नगर पंचायत अध्यक्ष इम्तियाज अहमद

गत वर्ष सितंबर महीने में रॉबर्ट्सगंज तहसील प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी को सौंपी गई रिपोर्ट में चोपन नगर पंचायत अध्यक्ष और सपा नेता इम्तियाज अहमद और उनके साझीदारों का नाम भी शामिल हैं. क्षेत्रीय लेखपाल समेत तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पट्टेदारों द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से सटे पूर्व दिशा में अवैध खनन किया जा रहा है. ऐसा नहीं है कि सपा नेता और उनके साझीदार पहली बार अवैध खनन के मामले में संलिप्त पाये गए हैं. इससे पहले 2013 में 22 अगस्त और 23 सितंबर को भी तहसील प्रशासन की ओर से जिला प्रशासन को भेजी गई की रिपोर्ट में ये लोग अवैध खनन करते पाए गए थे. गौर करने वाली बात यह है कि अवैध खनन के इस गोरखधंधे में जाति-धर्म और क्षेत्रीयता की सभी सीमाएं पीछे छूट गईं. उक्त खनन पट्टे के अलावा भी सपा नेता इम्तियाज अहमद और उनके रिश्तेदारों के नाम से वर्दिया खनन क्षेत्र में खनन पट्टा आबंटित हैं. अगर इन खनन पट्टों का भौतिक सत्यापन किया जाए तो यहां भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ है और हो रहा है. पूर्व में भी सपा नेता और चोपन नगर पंचायत अध्यक्ष इम्तियाज अहमद, उनकी पत्नी फरीदा और उनके भाई सरफराज के नाम से बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में डोलो स्टोन के खनन पट्टे आवंटित किए गए थे. लोगों की मानें तो इन सभी के नाम से आवंटित खनन पट्टों में मानक विपरीत जाकर खनन किया गया था और उसके प्रमाण आज भी वहां मौजूद हैं. ऐसे खनन पट्टों में वर्ष 2001-11 तक कमलेश्वर और सरफराज के नाम से स्वीकृत खनन पट्टा भी शामिल है. इसी अवधि के दौरान राजेश कुमार पुत्र स्व. कलीराम और फरीदा पत्नी इम्तियाज के नाम से आवंटित खनन पट्टे की भूमि पर हुआ खनन भी इनकी कारस्तानियों की देन है. वर्ष 2002-12 तक की अवधि के दौरान इम्तियाज पुत्र मजनू, उमेश कुमार राय पुत्र वंशीधर राय और चंद्रगुप्त पुत्र राम बाबू के नाम से आवंटित खनन पट्टे में हुए अवैध खनन के लिए भी इनकी कारगुजारियां सवालों के घेरे में हैं.

सपा नेता इश्तियाक खान

बिल्ली-मारकुंडी गांव निवासी इश्तियाक खान की पत्नी मेसर्स पूर्वांचल सेवा समिति की सचिव हैं और उनका नाम भी तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में अवैध खननकर्ताओं की सूची में शामिल है. सूत्रों की मानें तो इश्तियाक खान खुद को सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का करीबी बताता है. इससे जिला प्रशासन समेत अन्य लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचाते हैं. इससे पहले 3 अप्रैल 2013 को भी इश्तियाक खान की पत्नी के नाम आवंटित खनन पट्टे में अवैध खनन करने की बात तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में कही गई थी.

भाजपा नेता वृषभान अग्रवाल

ओबरा के राममंदिर कॉलोनी स्थित 14/364 निवासी भाजपा नेता वृषभान अग्रवाल के प्रबंध निदेशकत्व वाली कंपनी/ फर्म मेसर्स बी. अग्रवाल स्टोन प्रोडक्ट लिमिटेड का नाम भी तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में है. तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भाजपा नेता वृषभान अग्रवाल के नाम से स्वीकृत खनन क्षेत्र के दक्षिण ओर अवैध खनन किया गया है और सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है. वृषभान ओबरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से पिछला चुनाव भी लड़ चुके हैं. भाजपा नेता के चचेरे भाई संजीव कुमार अग्रवाल के स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स मक्खन वर्क्स भी अवैध खनन के गोरखधंधे में संलिप्त पाई गई है. तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इनके स्वीकृत क्षेत्र के पूर्व की ओर अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिए गये हैं.

बसपा नेता और विधायक (रसड़ा) उमा शंकर सिंह

बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक और बसपा नेता उमाशंकर सिंह के खिलाफ बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में अवैध खनन करने के मामले को लेकर जिला प्रशासन पिछले साल मुकदमा दर्ज कराया. उमाशंकर सिंह की कंपनी सी.एस. इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (छात्र शक्ति इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड) बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र की अराजी संख्या-6229-ख की 1.50 एकड़ भूमि पर 13 मार्च, 2010 से डोलो स्टोन का खनन कर रही है. इसकी मियाद 12 मार्च, 2020 तक है. गौर करने वाली बात यह है कि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की कंपनी छात्र शक्ति इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी ने बहुजन समाज पार्टी की पिछली सरकार में सोनभद्र में लोक निर्माण विभाग से होने वाले अधिकतर सड़क निर्माण के कार्य को अंजाम दिया है लेकिन वे सभी सड़क मार्ग बनने के दौरान ही उखड़ने लगे थे. ये बातें जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट में भी सामने आ चुकी हैं. फिलहाल भ्रष्टाचार में लिप्त होने के मामले में उमा शंकर सिंह की विधायकी जाने वाली है.

रविन्द्र जायसवाल और राकेश जायसवाल

वाराणसी जिले के पांडेयपुर स्थित सी-9/471-सी निवासी रविन्द्र जायसवाल और उनके साझीदार राकेश जायसवाल का नाम भी तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में अवैध खननकर्ताओं की सूची में शामिल है. तहसील प्रशासन ने गत सिम्बर की अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पट्टाधारकों के स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण अवैध खनन किया जा रहा है और सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है. वहीं दक्षिण की तरफ खड़ी पहाड़ी है जो खतरनाक स्थिति में है. विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो रविन्द्र जायसवाल के साझीदार राकेश जायसवाल उत्तर प्रदेश की पूर्व बसपा सरकार में खनन मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा के करीबी पूर्व विधायक आरपी जायसवाल के करीबी हैं. राकेश जायसवाल की पत्नी आरती जायसवाल और ओबरा निवासी श्याम बिहारी की स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स सुशील ग्रीट कॉर्पोरेशन भी अवैध खनन के गोरखधंधे में संलिप्त पाई गई है. इस फर्म के नाम से बिल्ली-मारकुंडी की आराजी संख्या-7410-क के 0.93 एकड़ क्षेत्रफल में खनन पट्टा आवंटित है. तहसील प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पट्टाधारकों द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से उत्तर और पश्चिम में अवैध खनन किया जा रहा है और सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है. रॉबर्ट्सगंज तहसील प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी को 8 जुलाई 2013 को भेजी गई रिपोर्ट में साफ लिखा है कि खान अधिनियम-1952 की धारा-22(2)22-ए(2) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगे होने के बावजूद पट्टाधारकों द्वारा विद्युत टॉवर के नीचे खनन किया जा रहा है. पत्थर के ऊपर जमी हुई मिट्टी को हटाया जा रहा है जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है. इसके बावजूद पट्टाधारकों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है. इससे इलाके में अवैध खनन का दौर बदस्तूर जारी है. चौंकाने वाली बात है कि सोनभद्र के बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में आवंटित डोलो स्टोन के खनन पट्टों में सबसे अधिक खनन पट्टे राकेश जायसवाल, उनकी पत्नी आरती जायसवाल के नाम से है. कुछ सीधे उनके नाम से हैं तो कुछ में ये साझेदार हैं. तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में राकेश जायसवाल और आरती जायसवाल के नाम से आवंटित खनन पट्टों में बार-बार अवैध खनन किया गया लेकिन जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की.

रूपा सिंह

श्रीमती रूपा सिंह पुत्री स्व. अजय सिंह और बिल्ली-मारकुंडी गांव निवासी अब्दुल सत्तार पुत्र स्व. कुर्बान अली के नाम से बिल्ली-मारकुंडी गांव की आराजी संख्या-4476 के 1.00 एकड़ रकबे में खनन पट्टा आवंटित है. इसकी मियाद 3 फरवरी 2017 तक है. गत वर्ष 15 सितंबर की तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इनके स्वीकृत क्षेत्र के पूर्व की ओर अवैध खनन किया जा रहा है. सूत्रों की मानें तो श्रीमती रूपा सिंह आईपीएस अधिकारी (डीआईजी) अमर नाथ सिंह की बहू हैं और इनके दामाद आईएएस अधिकारी राजेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ आरपी सिंह करीब आठ साल पहले सोनभद्र के जिलाधिकारी रह चुके हैं. फिलहाल जिला प्रशासन ने पिछले दिनों उक्त खदान में अवैध खनन पाया था और खान अधिकारी को इस खदान के पट्टाधारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया था.

श्रीमती मीरा राय

गाजीपुर जिले के रेवतीपुर डाकखाना क्षेत्र अंतर्गत तिलवा गांव निवासी श्रीमती मीरा राय पत्नी अमरनाथ राय के स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स सत्यम स्टोन वर्क्स के नाम से बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-4959, 4961 से 4967 और 4972 से 4974 के 1.41 एकड़ रकबे में खनन पट्टा आवंटित है. इसकी मियाद 3 जनवरी 2017 तक है. तहसील प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इनके स्वीकृत खनन क्षेत्र के दक्षिण और पश्चिम अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है. सूत्रों की मानें तो श्रीमती मीरा राय बागपत के एसपी और आईएएस अधिकारी अवधेश कुमार राय की रिश्तेदार हैं. इसलिए इनके खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया की रिपोर्ट का असरः

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अवैध खनन के खिलाफ फूंका बिगुल

शासन-प्रशासन और खनन माफियाओं के गठजोड़ से उत्तर प्रदेश में नियमों के खिलाफ अवैध खनन हो रहा है. अवैध खनन के कारण मरने वाले मजदूरों पर केंद्रित चौथी दुनिया की रिपोर्ट में उठाए गए सवालों को लेकर जनहित मंच के संयोजक संतोष सिंह चंदेल की अगुआई में दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता गत 28 दिसंबर को रॉबर्ट्सगंज तहसील परिसर में अनिश्चित कालीन धरने पर बैठ गए. धरने के दौरान उन्होंने जिला प्रशासन समेत उत्तर प्रदेश सरकार से सोनभद्र में वीआईपी के नाम पर हो रही अवैध वसूली पर जवाब मांगा. साथ ही उन्होंने वर्ष 2012 में 27 फरवरी को घटित बिल्ली-मारकुंडी खनन हादसे की मजिस्ट्रेटियल जांच रिपोर्ट पूरी नहीं होने और उसमें मरने वाले मजदूरों को मुआवजा नहीं मिलने का कारण पूछा.

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण मंत्रालय की एनओसी के बिना सोनभद्र की 101 पत्थर की खदानों में अवैध खनन, खनन क्षेत्र में अवैध विस्फोटकों की आपूर्ति और मानक के विपरीत उनका प्रयोग किए जाने आदि मुद्दों पर भी राज्य सरकार से श्वेत-पत्र जारी करने की मांग की. संतोष सिंह चंदेल ने जिला प्रशासन पर अवैध खनन कराने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बड़गवां की आराजी संख्या-2368/1 और कोटा की आराजी संख्या-4043-क, 4043-ख, 4044, 4045, 4046, 3984-ग और 3984-घ पर स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि समाप्त हो चुकी है लेकिन इन पट्टों की एमएम-11 परमिट पर खनिजों को परिवहन अब भी हो रहा है. अब तक हजारों एमएम-11 परमिट जारी हो चुका है लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी में उक्त खनन पट्टों पर गेहूं और बैगन बोने की बात कही गई है. उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की. सामाजिक कार्यकर्ता रामधीन पासवान, नागेश्वर चेरो, प्रेम कुमार, राजकुमारी देवी, संतोष त्रिनेत्र, राम नारायण सिंह, कमल यादव, राजबहोर सिंह, सियाराम जायसवाल, रवि केशरी, रमाकांत चेरो, राजेन्दर वनवासी, अतवारू, पुनवासी, होसिला, मुन्ना, लाल बिहारी, जयराम, कैलाश, प्रमोद, डब्बू समेत दर्जनों लोग धरने पर बैठे रहे. पीयूसीएल के प्रदेश संगठन संचिव विकास शाक्य समेत अन्य कई अधिवक्ताओं ने अवैध खनन के खिलाफ चल रहे धरने का समर्थन किया. धरने के 18वें दिन चंदेल ने जिला प्रशासन की बरसी मनाते हुए अपना मुंठन कराकर धरने को स्थगित किया. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अवैध खनन के खिलाफ इस अभियान के समर्थन में डेढ़ लाख लोगों का हस्ताक्षर लेने और उसके आधार पर उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही. गौरतलब है कि चौथी दुनिया(उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) ने 22 दिसंबर-28 दिसंबर, 2014 के अंक में मजदूरों की हत्या का राज दफन' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी.

-चौथी दुनिया ब्यूरो

अवैध खनन पर बोला तो चरित्र हनन

दीनबंधु कबीर

उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के भ्रष्टाचार मामले को लोकायुक्त अदालत में ठोस शक्ल तक ले जाने वाली समाजसेवी नूतन ठाकुर को पहले तो धमकियां मिलीं, अब उनके पति आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर पर बलात्कार करने और नूतन ठाकुर पर बलात्कार में सहयोग करने की एक शिकायत दर्ज की गई है. जिस महिला ने बलात्कार की शिकायत की है, उसका पति सपा का एक छुटभैया नेता है और इस षडयंत्र-प्रकरण के पीछे खनन मंत्री की भूमिका की आशंका जताई जा रही है. नूतन ठाकुर ने बताया कि पुष्पा देवी पत्नी भुजवीर, जी-9, अम्बेडकरनगर कॉलोनी, गाजियाबाद ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को पत्र लिख कर यह शिकायत की है कि एक नेता (नेता का नाम नहीं लिखा है) ने उसकी नूतन ठाकुर से भेंट कराई थी. आरोप है कि श्रीमती ठाकुर ने नौकरी दिलाने के नाम पर उस महिला को लखनऊ बुलाया. श्रीमती ठाकुर के गोमतीनगर आवास पर उसे बुला कर अमिताभ ठाकुर से मिलाया जहां दरवाजा बंद कर उसके साथ बलात्कार किया गया. राज्य महिला आयोग को लिखे गए इस पत्र की जानकारी मिलते ही नूतन ठाकुर ने प्रदेश के डीजीपी और लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया.

नूतन ठाकुर और उनके पति आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी अरुण कुमार गुप्ता से मिल कर गाजियाबाद की उक्त महिला द्वारा लगाए गए फर्जी आरोपों की तत्काल उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की. ठाकुर दम्पति ने कहा कि यह हाई-प्रोफाइल षडयंत्र का हिस्सा है जो उनके सामाजिक कार्यों से नाराज किसी रसूखदार द्वारा रचा गया है. ठाकुर दम्पति ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जरीना उस्मानी से भी मुलाकात की और षडयंत्रकारी तत्वों द्वारा महिला आयोग का गलत उपयोग नहीं करने देने का अनुरोध किया और कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच को सामने आना चाहिए.

नूतन ठाकुर ने इस षडयंत्र के पीछे खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की भूमिका की आशंका जताई. उन्होंने बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला के पति सपा नेता और गायत्री प्रजापति की भूमिका की सीबीआई से जांच कराने की मांग की. ठाकुर दम्पति ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश करने का आग्रह किया है. नूतन ठाकुर का कहना है कि आरोप लगाने वाली महिला के बारे में पूरा तथ्य सामने आने के बाद यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि यह षडयंत्र प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति द्वारा उनके खिलाफ चल रही जांच में डराने और फंसाने के लिए कराया गया है. षडयंत्र के इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर पीपुल्स फोरम के तत्वावधान में लखनऊ के समाजसेवियों ने धरना भी दिया. इसमें प्रमुख रूप से संजय शर्मा, उर्वशी शर्मा, इंदु सुभाष, अनुपम पाण्डेय, कुमार सौवीर, अशोक गोयल, महेंद्र अग्रवाल, राम स्वरूप यादव, देवेन्द्र कुमार दीक्षित, तुलसी वल्लभ मिश्र, ओमेन्द्र मिश्र, रोहित कुमार, अनामिका पोरवाल, जगदीश प्रसाद शर्मा, डॉ. नूतन ठाकुर समेत कई अन्य लोग मौजूद थे.

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के खनन मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते ही सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर को धमकियां मिलनी शुरू हो गई थीं. नूतन ठाकुर ने गोमतीनगर थाने में तहरीर भी दी थी, पर कोई एफआईआर नहीं लिखी गई. नूतन ठाकुर का कहना है कि उन्हें और उनके आईपीएस पति अमिताभ ठाकुर को टेलीफोन पर दी गई धमकी में पुलिस की भी मिलीभगत है. इसी वजह से गोमतीनगर थाने में पूरी तरह गलत तरीके से सनहा दर्ज किया गया. फोन पर धमकियां देने वाले ने नूतन ठाकुर से कहा था कि उनकी अवैध सम्पत्ति और अवैध प्लॉटिंग के मामले में पड़ने से उन्हें दिक्कत होगी. उसने यह भी कहा था कि उनके पति सरकारी नौकरी में हैं, इस कारण उन्हें भी दिक्कत हो सकती है. फोन पर दी गई धमकी और कथित बलात्कार की शिकायत को देखें तो षडयंत्र की कड़ियां जुड़ती हुई साफ-साफ दिखाई देती हैं. बहरहाल, उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का भ्रष्टाचार उजागर करने वाले ओमशंकर द्विवेदी के शिकायत वापस ले लिए जाने के बाद समाजसेवी नूतन ठाकुर ने खनन मंत्री के साथ-साथ ओमशंकर द्विवेदी की मिलीभगत के खिलाफ भी लोकायुक्त से शिकायत की थी और मोर्चा खोल दिया था.

समाज का भयावह सच है दरवाजे पर चस्पा नोटिस

नागरिक सुरक्षा महकमे में संयुक्त निदेशक (आईजी) के पद पर लखनऊ में तैनात आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अपने दफ्तर के कक्ष के दरवाजे पर नोटिस चिपका दी है कि कोई भी महिला आगंतुक कृपया अकेले मेरे कक्ष में प्रवेश न करें- आज्ञा से अमिताभ ठाकुर, संयुक्त निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ.प्र., लखनऊ. अमिताभ ठाकुर ने कहा कि मैंने ऑफिस के दरवाजे पर नोटिस लगाने के साथ-साथ घर पर सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया है ताकि भविष्य में गाजियाबाद की महिला की तरह कोई अन्य महिला ऐसा फूहड़ और झूठा आरोप न लगा दे. श्री ठाकुर ने कहा कि गाजियाबाद की उस अज्ञात महिला की शिकायत के बाद एक मनोवैज्ञानिक भय समा गया है कि किसी भी सम्मानित व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर कोई मिनटों में आघात पहुंचा सकता है. ■

लोकपाल बिल लागू होता तो भ्रष्टाचारी सालाखों के पीछे होते-खण्डूड़ी

लोकपाल बिल लागू होता तो देवभूमि उत्तराखंड की छवि भ्रष्टाचार की नहीं होती और प्रदेश के लोगों को शर्मसार करने वाले भ्रष्टाचारी सालाखों के पीछे होते. चाहे वह मुख्यमंत्री हो या मंत्री, गढ़वाल के सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी ने कही. खंडूड़ी ने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की विदेश कूटनीति सशक्त मजबूत हुई है और विश्व के सभी देशों में भारत का जज्बा पहचाना जा रहा है. अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम गिरने के बाद भी महंगाई कम न होने के सवाल पर जनरल खंडूड़ी ने कहा कि आने वाले माह अच्छे दिनों का संकेत दे रहे हैं जिसमें महंगाई से जनता को निजात मिलेगी. भ्रष्टाचार रोकने के सवाल पर सांसद खंडूड़ी ने कहा कि छोटी इकाई जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी विधायक व सांसद की तरह करवाने के लिए उन्होंने लोकसभा से मुहिम शुरू करवा दी है. उत्तराखंड में एनआरएचएम दवाई घोटाला के सवाल पर उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा तो मिलनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि वे प्रदेश सरकार की आलोचना न कर विकास कार्यों को तेजी से करवाने की नसीहत दे रहे है. वहीं कोटद्वार रेलवे स्टेशन के निर्माण कायरे का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि वहां हो रहे कार्य शून्यता की ओर है वहीं खंडूड़ी ने कार्यकर्ताओं व जनता से आह्वान किया कि वह जागरूक होकर स्वच्छ मानसिकता का परिचय दें व जिस भी दल को सत्ता सौंपनी है उसे पूर्ण समर्थन दें. वहीं केन्द्र में उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व मिलने के सवाल पर सांसद खंडूड़ी ने कहा कि तीन सांसदों को समितियों का सभापति बनाया गया है. यदि दलित सांसद अजय टम्टा मंत्री नहीं बन पाये तो इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है क्योंकि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर कार्य कर रही है. पूर्व मुख्यमंत्री ने किरन बेदी के हवाले दिल्ली किए जाने पर हर्ष जताते हुए कहा कि पूरे देश में विकास की हवा बहेगी. ■

भाजपा में शामिल होने की मची होड़, पार्टियों में भगदड़

पृष्ठ 17 का शेष

को महत्व दिया जा रहा है. अभी घोषित राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा की टीम में यूपी से चार लोगों को जगह मिली है. उत्तर प्रदेश में दलित वोटों पर नजर का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि यहां क्षेत्रवार चार लोगों को राज्य प्रभारी बनाया गया है. इसमें गोपाल पछेरवाल, सुरेश राठौर, के के राज और स्वरूपचंद रंजन शामिल हैं. वैसे भाजपा में पिछड़ा-दलित गठजोड़ मजबूत करने की कवायद तभी शुरू हो गई थी जब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आगरा के सांसद रामशंकर कठेरिया को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था. भाजपा के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसके दूसरे संगठन भी सामाजिक समरसता की बहाली के लिए दलित वर्ग में अपनी पैठ बनाने में लगे हुए हैं. इसके लिए भाजपा ने विशेष सदस्यता अभियान भी चलाया था. इसका भी गहरा झटका बसपा, सपा और कांग्रेस को लगा और उन्हें अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ीं.

मायावती के करीबी रहे बृजलाल ने भाजपा में आने के बाद कहा कि बसपाकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा तो सपाकाल में अपराध बढ़ा है. उन्होंने यह भी कहा कि बसपा ने दलितों का केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया. मौजूदा हालात पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है. आज राजनीति में अपराधीकरण इतना हावी हो चुका है कि प्रदेश में पुलिस पिट रही है और दोषियों पर कार्रवाई के बजाए पुलिस वालों का ही तबादला किया जा रहा है. इससे पुलिस में हीन-भावना पैदा हो रही है. बसपा सरकार में कानून-व्यवस्था तो अपेक्षाकृत ठीक रहती है, लेकिन सपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं. बसपा ने दलितों को केवल वोटबैंक समझा, उनका इस्तेमाल किया. बसपा सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे दलितों या दबे कुचले लोगों का उद्धार हुआ हो. बसपा ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया. दलितों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया. इसी वजह से दलित बसपा से कटा और यह सिलसिला लगातार जारी है.

बेटे के आगे मुलायम बेबस

समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने बेटे के आगे बेबस हैं. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों की करतूतों पर बोल-बोल कर पस्त हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन बातों से बेअसर, मस्त हैं. मुलायम लगातार यह बोल रहे हैं कि अखिलेश सरकार के कुछ मंत्री जनविरोधी गतिविधियों और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उन मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, जबकि जनता इससे आजिज आ चुकी है और उन्हें पत्र लिख-लिख कर शिकायत करती है. 21 जनवरी को पार्टी मुख्यालय में सपा विधायक दल की सभा को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने फिर कहा कि अखिलेश सरकार के कुछ मंत्री लूट-खसोट में लगे हैं. कुछ विधायक भी कमीशनखोरी कर रहे हैं. पता नहीं, अखिलेश ऐसे मंत्रियों को हटाते क्यों नहीं? मुलायम ने बड़ी विवशता से कहा कि बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद कुछ मंत्री लूट-खसोट में लगे हैं. मुझे ऐसे मंत्रियों की पूरी जानकारी है. मुझे ऐसे मंत्रियों की भी जानकारी है जो टेलीफोन करने के बाद भी उनके लोकसभा क्षेत्र में नहीं गए. पता नहीं विधायकों की मुख्यमंत्री से मुलाकात क्यों नहीं हो पाती? मैं मुख्यमंत्री था तो विधायकों, मंत्रियों से खूब मिलता था. उनसे मुलाकात के दिन तय कर रखे थे.

मुख्यमंत्री अखिलेश के ऐसे रवैये के प्रति नाराजगी जाहिर करने के बावजूद मुलायम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि यदि उन्हें किसी मंत्री या अफसर से शिकायत है तो उन्हें गोपनीय पत्र लिखें. जनता ने जो भरोसा किया है उसे हमें टूटने नहीं देना चाहिए. अब 2017 में फिर चुनाव होने हैं. ऐसे में हमें अपनी छवि के बारे में सतर्क रहना होगा.

संजय जोशी फिर से भाजपा की मुख्यधारा में

भारतीय जनता पार्टी से बहुत दिनों तक बहिष्कृत रहे मोदी-विरोधी संजय जोशी क्या फिर से भाजपा की मुख्यधारा में लौट रहे हैं? लखनऊ में यह चर्चा खूब गर्म रही. 22 जनवरी को संजय जोशी का लखनऊ में सक्रिय दिखना और स्वच्छ भारत अभियान में झाड़ू लेकर सड़क पर निकलना तो यही बता रहा था. संजय जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनप्रिय नेता बताते हुए उनकी नीतियों की तारीफ की और कहा कि मोदी ने स्वच्छता अभियान को गति दी है. लोगों को जागरूक किया है और राजनीति को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने की कोशिश की है, यह प्रशंसनीय है. संजय जोशी ने खुद झाड़ू लगाकर लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की.

संजय जोशी एक दिन के लिए लखनऊ आए थे, लेकिन इसी एक दिन के दौरे में स्वच्छता अभियान में उनका हिस्सा लेना, संगोष्ठी में शरीक होना और संघ व अन्य संबंधित संगठनों के लोगों से मुलाकात करने के निहितार्थ तो समझे ही जा सकते हैं. झाड़ू लगाने में जोशी के साथ प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर की महिला महंत दिव्या गिरि के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रभुनारायण, अमरनाथ, संयुक्ता भाटिया, केके शुक्ला वगैरह भी मौजूद थे. स्वाभाविक है कि राजनीति के समीक्षक इसे संजय जोशी की भाजपा में पुनरवापसी का स्पष्ट संकेत मानेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

लागू होगा बाबा का योगापाठ्यक्रम, भड़के कांग्रेसी

योगगुरु बाबा रामदेव की चारो ओर से बल्ले-बल्ले धर्म नगरी में होने वाली है. केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा पातंजली योगपीठ द्वारा तैयार किए गए योग पाठ्यक्रम को पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर ली गई है. सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो पतंजलि योगपीठ द्वारा तैयार किया जा रहा योग पाठ्यक्रम पूरे देश में एक साथ लागू होगा. हरियाणा के बाद अब भाजपा शासित अन्य राज्यों से भी पाठ्यक्रम की मांग की जान लगी है. जबकि छत्तीसगढ़ और सिस्किम में यह पाठ्यक्रम पहले से चल रहा है. बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण की अगुवाई में योगाचार्यों के एक मंडल ने दो वर्ष पूर्व योग पाठ्यक्रम तैयार किया था. इसे सबसे पहले सिक्किम और इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया. हाल ही में हरियाणा सरकार ने बाबा को हरियाणा का राज्य का ब्रांडअम्बेसडर बनाने के साथ ही इनकी संस्था द्वारा तैयार पाठ्यक्रम को राज्य में लागू करने की तैयारी भी कर ली है. बाबा रामदेव पर मोदी सरकार की मेहरबानियों से हरिद्वार के संत हैरान हैं. संतों के साथ कांग्रेस के नेता और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार बाबा को कालेधन के मुद्दे पर मुंह बन्द रखने के लिए कई तरह से उन्हें पुरस्कृत कर रही है. उपाध्याय ने बाबा को शुरू से संघ के ऐजेंडे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा के कथनी करनी में अन्तर है. बाबा के योग पाठ्यक्रम को लागू करने के पहले ही विरोध की चिंगारी उठ रही है जो किसी भी क्षण भड़क सकती है. किशोर उपाध्याय ने रामदेव को चैलेंज दे डाला कहा कि यदि कालाधन देश में वापस आया तो वह बाबा रामदेव के पैर धोकर पीएंगे. किशोर उपाध्याय ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव ने काला धन देश में वापस लाने और प्रत्येक देशवासी के बैंक खाते में 100 दिनों में 15 लाख रुपये जमा कराने के नाम वोट मांगा. दोनों ने यूपीए सरकार को देश भर में घूम-घूमकर कालेधन को लेकर बदनाम किया. ***-राजकुमार शर्मा***

निजी अस्पतालों और क्लीनिकों को मनमानी की छूट

सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ही प्रदेश में निजी अस्पतालों और क्लीनिकों को मनमानी की छूट दी है. सूचनाधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कहने पर ही 25 अगस्त 2014 तक क्लीनिकल इस्टेबलिशमेंट एक्ट को लागू न करने की ताकीद की थी. मुख्यमंत्री द्वारा तय समय के बीत जाने के बावजूद प्रदेश में यह कानून लागू नहीं हो पाया है.

इसके नियम कायदे नहीं लागू हो पा रहे और इस वजह से इलाज के तय शुल्क का कोई मानक नहीं हैं और प्रदेश के मरीजों को निजी अस्पतालों व क्लीनिकों में डॉक्टरों को मनमानी फीस देनी पड़ रही है और विभिन्न परीक्षणों का भी मनमाना शुल्क देना पड़ रहा है. उत्तराखंड आरटीआई क्लब को मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून के कार्यालय के लोक सूचनाधिकारी से सूचनाधिकार के तहत जो सूचनाएं मिलीं हैं उनके मुताबिक यह एक्ट 29 मार्च 2011 को राज्य विधानसभा ने अंगीकृत कर लिया था. 22 मार्च 2013 को शासन के चिकित्सा अनुभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत क्लीनिकल एस्टेबलिशमेंट एक्ट (नैदानिक स्थापन रजिस्ट्रीकरण व विनियम अधिनियम-2010)के तहत हर जिले में जिला स्तर पर गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष जिलाधिकारी को व संयोजक मुख्य चिकित्साधिकारी को नामित किया गया है.

यही नहीं प्रदेश शासन ने क्लीनकल इस्टेबलिशमेंट के रजिस्ट्रीकरण व विनियमन के लिए 2013 में नियमावली बना ली थी. इस एक्ट के तहत निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम ही नहीं बल्कि सरकारी चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एसएडी व सब सेंटर पंजीकृत होने थे. देहरादून में अभी केवल पंजीकरण होना है और इसके लिए भी उच्चाधिकारियों के आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है.29 दिसंबर 2014 को देहरादून में जिला स्तर पर गठित सलाहकार समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि जब तक मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में शासन नए निर्देश जारी नहीं करता तब तक एक्ट के विभिन्न प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे. ■ ***-रेनू शर्मा***

feedback@chauthiduniya.com